भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड की रूपरेखा		1
परिचय	1.1	2
2012-13 के राजकोषीय संचालन का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट आकलन एवं वास्तविक	1.1.3	5
लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट	1.1.4	6
बजट के मुख्य नीति उद्गम	1.1.5	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	13
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.3.2	16
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	16
13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग	1.3.4	17
त्यक्त राजस्व	1.3.5	18
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	18
ऋण एवं अग्रिमों से वसूली	1.4.1	19
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	20
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1.4.3	20
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	20
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	21
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.6.1	21
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1.6.2	23
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	24
मुख्य कार्यक्रम	1.6.4	26
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता	1.6.5	28
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली	1.6.6	28
व्यय की गुणवत्ता	1.7	31
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	32
व्यय के इस्तेमाल की दक्षता	1.7.2	33

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	36
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	36
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	36
निवेश एवं वापसी	1.8.3	37
सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) परियोजनाओं में निवेश	1.8.4	38
राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	1.8.5	39
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.6	40
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	41
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	41
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	41
आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन	1.9.3	43
प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	1.9.4	43
ऋण प्रबंधन	1.10	44
ऋण की रूप रेखा	1.10.1	44
ऋण धारणीयता	1.10.2	44
राजकोषीय असंतुलन	1.11	46
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	46
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली	1.11.2	47
घाटा/अधिशेष के गुण	1.11.3	48
झारखण्ड सरकार का बाजार उधार	1.12	49
परिचय	1.12.1	49
झारखण्ड में बाजार उधार की स्थिति	1.12.2	50
ऋण धारणीयता संकेतक - बाजार ऋण के सापेक्ष कुल दायित्व	1.12.3	50
बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति	1.12.4	52
ब्याज दर की रूपरेखा	1.12.5	53
पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार ऋण की उगाही किया गया	1.12.6	53
बाजार उधार के लिए अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर	1.12.7	54
भा.स. द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक का उधार	1.12.8	54
बाजार उधार की उपयोगिता की निगरानी प्रणाली	1.12.9	55
अनुपालन	1.13	56
निष्कर्ष	1.14	56
अनुशंसाएँ	1.15	57

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	59
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	59
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	60
वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन	2.4	61
आबंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	61
सतत बचत	2.4.2	62
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.4.3	66
वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता	2.4.4	67
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	67
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	68
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	68
प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.8	69
व्यय का वेग	2.5	69
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	69
अनुदान सं.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव	2.7	70
निष्कर्ष	2.8	73
अनुशंसाएँ	2.9	74
अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन		
भुगतित अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	75
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखापरीक्षा एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.2	76
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	76
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा	3.2.2	77
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण	3.3	78
दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	78
निधि आहरित कर बैंक खाते/ पी.एल. खाते में रखना	3.5	79
खुफिया सेवा निधि के प्रशासनिक लेखा परीक्षा का बकाया प्रमाणपत्र	3.6	80
निष्कर्ष	3.7	80
अनुशंसाएँ	3.8	81

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 पार्ट-ए	झारखण्ड का परिचय	83
परिशिष्ट 1.1 पार्ट-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	84
परिशिष्ट 1.1 पार्ट-सी	वित्त लेखे की अभिन्यास	84
परिशिष्ट 1.2 पार्ट-ए	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	85
परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007	86
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	87
परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए	वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	90
परिशिष्ट 1.4 पार्ट-बी	31 मार्च 2013 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	93
परिशिष्ट 1.5	13वें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे	95
परिशिष्ट 1.6	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण	98
परिशिष्ट 1.7	बाजार ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज उत्तरदायित्व	99
परिशिष्ट 1.8	अग्रिम सांकेतिक कैलेन्डर के अनुसार सरकार द्वारा बढ़ाये गए बाजार ऋण	99
परिशिष्ट 2.1	₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी	100
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2012-13 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	102
परिशिष्ट 2.3	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित राशि	105
परिशिष्ट 2.4	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	106
परिशिष्ट 2.5	निधि का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	108
परिशिष्ट 2.6	₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी	109
परिशिष्ट 2.7	30 और 31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि	111
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	115
परिशिष्ट 2.9	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान असंशोधित रह गई	116
परिशिष्ट 2.10	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा पूरे आबंटन की बचत	117
परिशिष्ट 2.11	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा निरर्थक अनुपूरक	118
परिशिष्ट 2.12	बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय	119
परिशिष्ट 2.13	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण	120

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2013 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	122
परिशिष्ट 3.2	नि.म.ले.प. डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	123
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों, गणना के आधार एवं संक्षिप्ति की सूची	126

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमश: वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच में पायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है। आवश्यकतानुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से प्राप्त की गयी है।

3. अध्याय 3 'वित्तीय प्रतिवेदन' वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में लेन-देन लेखापरीक्षा निष्कर्षों और संविधिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कम्पनियों से उत्पन्न प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय अधिनियम 2007, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार की गयी है।

अध्याय-1 वित्तीय लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2013 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि के अलावा गैर-बजटीय माध्यमों से राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (भा.स.) से सीधे हस्तांतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करती है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आबंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय-3 झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

इस प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट भी समाहित है। अंत में ***'परिशिष्ट 4.1'*** प्रतिवेदन में प्रयुक्त किये गये राज्य वित्त से संबंधित शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों की शब्दावली को प्रस्तुत करती है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा:-

- वर्ष 2012-13 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में वृद्धि ते.वि.आ. मानदंड 14.50 *प्रतिशत* के विरुद्ध 11.5 *प्रतिशत* रहा।
- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 1370 करोड़ था। स.रा.घ.उ. के राजस्व अधिशेष की प्रतिशतता 'मध्यावधि

राजकोषीय योजना लक्ष्य' के 3.32 के विरुद्ध 0.9 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 3406 करोड़) स.रा.घ.उ. का 2.2 *प्रतिशत* था जो तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों (तीन *प्रतिशत*) के अन्दर था।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण

- वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य बजट के बाहर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से वर्ष 2011-12 के ₹ 4194.42 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2621.91 करोड़ का हस्तांतरण राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किया। अत: वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रस्तुत नहीं करते हैं। राज्य सरकार तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.) को ससमय व्यय प्रतिवेदित करने हेतु मापदण्ड के अभाव में इन अभिकरणों द्वारा समरूप लेखांकन पद्धति का अनुकरण नहीं किया जाता है।

राजकोषीय असंतुलन एवं संसाधन जुटाने का प्रबंधन

- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,770 करोड़) में पिछले वर्ष से 10.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। तथापि, बजट आकलन की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7656 करोड़ रूपये से कम थी। राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व 47 *प्रतिशत* रहा जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 53 *प्रतिशत* रहा। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में पिछले वर्ष से आठ *प्रतिशत* की कमी हुई।

पूँजीगत व्यय

- वर्ष 2012-13 के दौरान, पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 3159 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4218 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता में वर्ष 2011-12 के 13 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान 15 *प्रतिशत* की बढ़ोत्तरी हुई।

राजकोषीय प्राथमिकता एवं व्यय प्रबंधन-

- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय (₹ 23,400 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 11 *प्रतिशत* बढ़ा। कुल व्यय का 83 *प्रतिशत* राजस्व व्यय के रूप में हुआ। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 15 *प्रतिशत* था। कुल राजस्व में

योजनागत राजस्व व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 36 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में 33 तक घटी। वर्ष 2012-13 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹ 15,657 करोड़) में 17 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और यह कुल राजस्व व्यय का 67 *प्रतिशत* रही।

- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थायीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता वर्ष 2011-12 के ₹ 4530.23 करोड़ से घटकर वर्ष ₹ 1427.25 करोड़ हुई।

विकास व्यय पर जोर

- वर्ष 2012-13 के दौरान, विकास व्यय की वृद्धि पिछले वर्ष के सापेक्ष 18.23 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 52 *प्रतिशत* थी जबकि विकासात्मक पूँजीगत व्यय सिर्फ 14 *प्रतिशत* थी। अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य सरकार ने शिक्षा एवं प्रक्षेत्रों को कम प्राथमिकता दी।

अर्पूण परियोजनाएँ

- मार्च 2013 के अनुसार ₹ 10 लाख से अधिक की लागत वाले 189 अपूर्ण परियोजनायें थी। इन परियोजनाओं में कुल ₹ 1972 करोड़ अवरुद्ध थे।

सरकार के निवेशों की समीक्षा

- 31 मार्च 2013 के अनुसार झारखण्ड सरकार ने सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों इत्यादि में ₹ 187.82 करोड़ निवेश किया। वर्ष 2012-13 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2011-12 के ₹ 1.17 करोड़ के विरुद्ध ₹ 15 करोड़ था। निवेश में वापसी (7.99 *प्रतिशत*) उधार पर औसत ब्याज दर (8.76 *प्रतिशत*) की तुलना में कम था।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य की राजकोषीय दायित्व (₹ 34,869 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 14 *प्रतिशत* बढ़ी। इस वर्ष राजकोषीय दायित्व ते.वि.आ. की सिफारिश के 28.7 *प्रतिशत* के सापेक्ष स.रा.घ.उ. का 22.2 *प्रतिशत* था। सरकार ने सभी ऋणों की मुक्ति के लिए निक्षेप निधि स्थापित नहीं किया।

बाजार उधार

- जब स.रा.घ.उ. से कुल लोक ऋण की प्रतिशतता वर्ष 2008-09 के 20.01 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में 16.07 *प्रतिशत* हो गयी, कुल दायित्व में बाजार ऋण की हिस्सेदारी वर्ष 2008-2009 के 24.80 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 33.77 *प्रतिशत* हो गई। नगद की तत्काल आवश्यकता का आकलन किये बिना राज्य सरकार ने पर्याप्त राशि होने के बावजूद ऋण लिया। ₹ 213 करोड़ का बाजार ऋण केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना लिया गया जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

- वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 9225.13 करोड़ की विशाल बचतें हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत विशाल बचतें राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विगत पाँच वर्षों में सतत बचतें 15 विभागों में पायी गयी।

- वर्ष 2012-13 के दौरान बजट उपबंधों से ₹ 1263.18 करोड़ अधिक व्यय किये गये जिसे भारत के संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-12 के दौरान किये गये ₹ 8540.79 करोड़ के अधिक व्यय को भी नियमित किया जाना शेष था।

- वर्ष 2012-13 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों ने विभागों के ₹ 23,400.20 करोड़ का व्यय (कुल व्यय का 76.71 *प्रतिशत*) एवं ₹ 14,641.32 करोड़ की प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों का 48.78 *प्रतिशत*) को महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ समाशोधन नहीं किया ।

- विभाग में बजटीय-नियंत्रण के अभाव में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने बजट नियम पुस्तिका के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया।

वित्तीय प्रतिवेदन

- राज्य के संस्थाओं/निकायों द्वारा ₹ 4640.48 करोड़ के सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया गया, जिससे

राज्य सरकार इसके संचालन में दायित्व सुनिश्चित करने एवं कार्यकुशलता सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने से बाधित हुई।

- सरकार के विभागों ने अनुदानग्राही निकायों के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किये। स्वायत्त निकायों के लेखे 'पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों' को राज्य विधान मंडल के समक्ष समयानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया।
- विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-13 की अवधि से संबंधित ₹ 5243 करोड़ राशि के बड़ी संख्या में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (24,583) 11 नवम्बर 2013 तक बकाये थे।
- वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन दिन पूर्व संक्षिप्त आकस्मिक बिल द्वारा आहरित ₹ 209.23 करोड़ की राशि व्यपगत होने से रोकने के लिए बैंक खाते में जमा किया गया। मार्च 2013 के अंत तक व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 2954.43 करोड़ की एक विशाल राशि शेष थी। चालू वर्ष के विधान मंडल द्वारा पारित बजट निधि को अगामी वर्ष में व्यय के लिए व्यक्तिगत जमा खाता में हस्तांतरण करना अनियमित था।

अध्याय-1
राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात् किया गया था, 79,714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, यह देश का 15वाँ सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1* भाग-ए** में दर्शाया गया है। अंतिम दस वर्षों (वर्ष 2003-04 से वर्ष 2012-13) के दौरान राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 19.13 *प्रतिशत* थी। गरीबी सम्पूर्ण-भारत औसत के 21.92 *प्रतिशत* की तुलना में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का *प्रतिशतता* 40.4 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2012-13 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 1,56,781 करोड़ थी। राज्य की साक्षरता दर 44 *प्रतिशत* (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.63 *प्रतिशत* (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 48,752 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य के भीतर दिये हुए समय में उत्पादित सरकारी तौर पर स्वीकृत समस्त सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	53,03,567	61,08,903	72,66,967	83,53,495	94,61,013
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	15.75	15.18	18.96	14.95	13.26
राज्य का स.रा.घ.उ.* (₹ करोड़ में)	87,794	1,00,621	1,25,824 (पी)	1,40,558 (क्यू)	1,56,781 (ए)
स.रा.घ.उ का वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5

**स्रोत: अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी निदेशक, झारखण्ड सरकार*

पी =औपबंधिक अनुमान, क्यू =तीव्र अनुमान, ए=अग्रिम अनुमान

झारखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के 14.5 *प्रतिशत* के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान 11.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। विगत दो वर्षों के दौरान राज्य का स.रा.घ.उ. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में कम था। तथापि, झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

(सी.ए.जी.आर.) (15.5 *प्रतिशत*) वर्ष 2008-13 के दौरान सम्पूर्ण भारत के स.घ.उ. के सी.ए.जी.आर. (15.6 *प्रतिशत*) के लगभग बराबर था।

1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2012-13 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा को ***परिशिष्ट 1.1 भाग-बी*** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को ***परिशिष्ट 1.1 भाग-सी*** में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति को ***परिशिष्ट 1.2 भाग-ए*** में दिया गया है। बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य को ***परिशिष्ट 1.2 भाग-बी*** में दर्शाया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है।

1.1.1 वर्ष 2012-13 के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष (वर्ष 2011-12) के साथ-साथ चालू वर्ष (वर्ष 2012-13) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए*** वर्ष 2012-13 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: 2012-13 के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
खण्ड क: राजस्व					**गैर योजना**	**योजना**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियाँ	22,419.45	24,769.56	राजस्व व्यय	20,991.58	15,656.61	7743.26	23,399.87
कर राजस्व	6953.89	8223.58	सामान्य सेवायें	7845.56	8474.55	221.94	8696.49
गैर कर राजस्व	3038.22	3535.63	सामाजिक सेवायें	7287.03	4238.37	4070.22	8308.59
संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	7169.93	8188.14	आर्थिक सेवायें	5858.99	2943.69	3451.10	6394.79
भारत सरकार से अनुदान	5257.41	4822.21	सहायता अनुदान एवं अंशदान	–	–	–	--
खण्ड ख: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	–	--	पूँजीगत परिव्यय	3159.37	67.38	4151.05	4218.43

प्राप्तियाँ	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
खण्ड क: राजस्व					**गैर योजना**	**योजना**	**कुल**
ऋण एवं अग्रिमों	23.42	43.11	संवितरित की	217.10	57.11	543.70	600.81
की वसूली			गई ऋण एवं अग्रिम				
अंतर्राज्यीय परिशोधन	–	--	अंतर्राज्यीय परिशोधन	75.40	100.00	--	100.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	2671.22	5199.00	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1639.01	2183.06	--	2183.06
आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	–	--	आकस्मिक निधि से व्यय	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	10,813.40	14,494.71	लोक लेखा संवितरण #	9727.77	13,416.31	--	13,416.31
आरंभिक रोकड़ शेष	(-)0.41	116.85	रोकड़ अंत शेष	116.85	704.75	--	704.75
कुल	35,927.08	44,623.23	*कुल*	35,927.08	32,185.22	12,438.01	44,623.23

स्रोत : वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे

**अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर*

#आँकड़े अन्य खाते जैसे कि नगद शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन को शामिल नहीं करते हैं

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये है:

- पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 2350 करोड़ (10 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यत: कर राजस्व में ₹ 1270 करोड़ (18 *प्रतिशत*), कर-भिन्न राजस्व में ₹ 498 करोड़ (16 *प्रतिशत*) तथा संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में ₹ 1018 करोड़ (14 *प्रतिशत*) तक बढ़ोतरी के कारण हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में ₹ 436 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) की कमी की गई।
- ते.वि.आ. द्वारा नियत किए गए कर-राजस्व (₹ 9544 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 3814 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध राज्य का वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ क्रमश: ₹ 8224 करोड़ (86 *प्रतिशत*) एवं ₹ 3536 करोड़ (93 *प्रतिशत*) था। इस प्रकार दोनों मोर्चे पर यह ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक प्रक्षेपण से कम था।
- सामान्य सेवाओं (₹ 850 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 1022 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 536 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के फलस्रूप राजस्व व्यय में ₹ 2408 करोड़ (11 *प्रतिशत*) तक की वृद्धि हुई। तथापि, यह ₹ 27801 करोड़ के बजट अनुमान से कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में ₹ 1059 करोड़ (34 *प्रतिशत*) की बढ़ोतरी हुई। वृद्धि मुख्यत: परिवहन विभाग के अन्तर्गत हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली वर्ष 2011-12 के ₹ 24 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 43 करोड़ हुई।

- पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2528 करोड़ (95 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में ₹ 544 करोड़ (33 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।
- संवितरण में ₹ 3689 करोड़ (38 *प्रतिशत*) की वृद्धि के सापेक्ष लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 3682 करोड़ (34 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।
- इस लेन-देन का निवल प्रभाव के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2012-13 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 587.90 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

झारखण्ड सरकार ने राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन *प्रतिशत* तक सीमित करना था। ते.वि.आ. ने राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की जिससे कि लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को सम्बद्ध किया जा सके।

तदनुसार, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के साथ-साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) में कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2011 एवं 2012 में निर्धारित किये गये संशोधित लक्ष्य (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना, (ii) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन *प्रतिशत* करना और (iii) वर्ष 2012-13 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 27.8 *प्रतिशत* करना था।

तालिका 1.2: मुख्य राजकोषीय विचरण

(प्रतिशत में)

राजकोषीय विचरण	2012-13				
	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. के तहत लक्ष्य	बजट के तहत लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. के अनुमान	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व आधिक्य	शून्य	शून्य	2.95	3.32	0.9
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	3.00	3.00	1.92	2.15	2.2
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	27.8	27.8	बजट में उपलब्ध नहीं	25.0	22.2

राज्य ने राजस्व घाटे से हटकर वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को राजस्व आधिक्य (₹ 946 करोड़) में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और सिवाय वर्ष 2009-10 के, जब राजस्व घाटा ₹ 10 करोड़ था, निरन्तर

सुधार करते हुए वर्ष 2012-13 में राजस्व आधिक्य ₹ 1370 करोड़ हुआ। तथापि, वर्ष 2012-13 में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व अधिक्य का एम.टी.एफ.पी लक्ष्य तथा बजट अनुमान के अनुपात क्रमश: 2.95 *प्रतिशत* एवं 3.32 *प्रतिशत* को प्राप्त नहीं किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे (₹ 3406 करोड़) की प्रतिशतता (2.2 *प्रतिशत*) ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुमानित सीमा तीन *प्रतिशत* के भीतर था। यह एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 2.15 *प्रतिशत* के सन्निकट था।

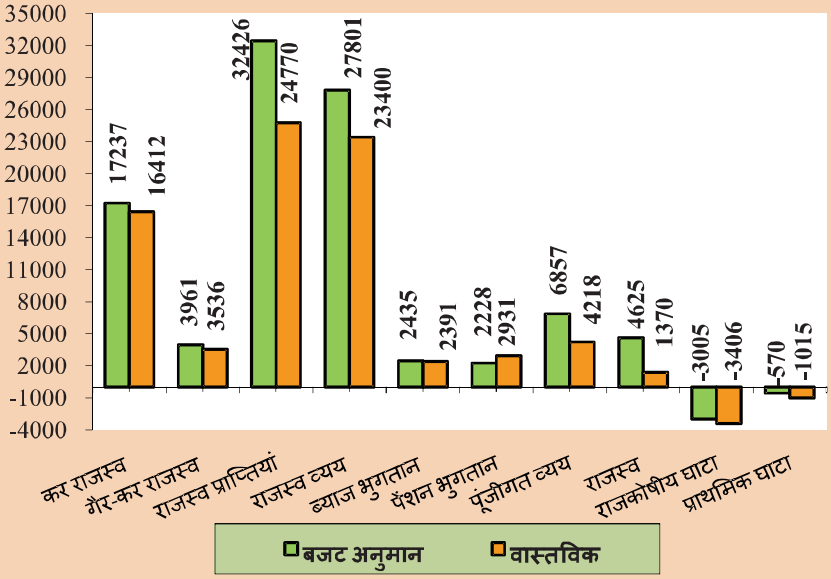
वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 22.2 *प्रतिशत* था जो ते.वि.आ. तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 27.8 *प्रतिशत* के अनुमान के काफी भीतर था। इस वर्ष ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात भी एम.टी.एफ.पी. के 25 *प्रतिशत* के लक्ष्य के काफी भीतर था।

1.1.3 बजट आकलन के साथ वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों में विचलन कई कारणों से होते हैं, जो कई कारणों से इच्छित राजकोषीय लक्ष्य हेतु उत्कृष्ट कार्य नहीं करने को संकेतिक करते हैं।

चार्ट 1.1 वर्ष 2012-13 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड के बजट अनुमान तथा वास्तविक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदंड: बजट अनुमान तथा वास्तविक



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि पेंशन भुगतान को छोड़कर, वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय वर्ष 2012-13 के राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान से कम थी। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 7656 करोड़) का मुख्य कारण राज्य बजट आकलनों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में अपेक्षाकृत कम राशि की प्राप्ति (₹ 6406 करोड़) थी। वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 4401 करोड़) में कमी का कारण सामाजिक सेवाओं (₹ 3302 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1238 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में ह्रास होना था।

सामाजिक सेवाओं (₹ 837 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1669 करोड़) पर व्यय, जो बजट में निर्धारित था, कम होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 2639 करोड़ कम था जो राज्य के लिये ध्यान देने की बात है।

1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजट को राज्य बजट में जोड़ा नहीं गया था। तथापि, राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के राज्य बजट में महिलाओं तथा लड़कियों के लिए प्रावधान किया है जिसका ब्यौरा नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3 बजट प्रस्ताव तथा महिलाओं के लिए व्यय

स्कीम/योजना	बजट आकलन	व्यय	अभ्यर्पण
बिटिया वर्ष	2.00	शून्य	2.00
किशोरी शक्ति योजना	2.20	शून्य	2.20
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम	57.54	8.85	48.69
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	9.00	3.09	5.91
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	15.00	12.83	2.17

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

- राज्य सरकार ने वर्ष 2012 को 'बिटिया वर्ष' मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना नामक एक नई स्कीम की घोषणा की। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान इस स्कीम हेतु प्रदत्त सम्पूर्ण बजट की राशि (₹ दो करोड़) को समर्पित कर दिया गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान किशोरी शक्ति योजना की ₹ 2.20 करोड़ के सम्पूर्ण बजट की राशि को समर्पित कर दिया गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु बजटीय कुल ₹ 15.00 करोड़ की राशि में से ₹ 12.83 करोड़ व्यय हुआ था।

1.1.5 बजट के मुख्य नीति उद्गम

राजस्व में सुधार हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की दरों का पुनरीक्षण किया। वित्त राज्यमंत्री के बजट भाषण के अनुसार इस संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए गए :

- राज्य में वैट के दर को 12.5 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 14 *प्रतिशत* कर दिया गया जिससे राजस्व प्राप्तियों में ₹ 150 करोड़ की वृद्धि का अनुमान किया गया।
- पेशा कर को लागू कर ₹ 50 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया है।
- निजी नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल आदि पर विद्युत सेवा 20 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया जाना था जिससे ₹ 20 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान किया गया।

- वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हेतु तम्बाकू उत्पादों पर कर को 14 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 20 *प्रतिशत* तथा तम्बाकू उत्पादों के संवेदकों पर टी.डी.एस. को दो *प्रतिशत* से बढ़ाकर चार *प्रतिशत* कर दिया गया।

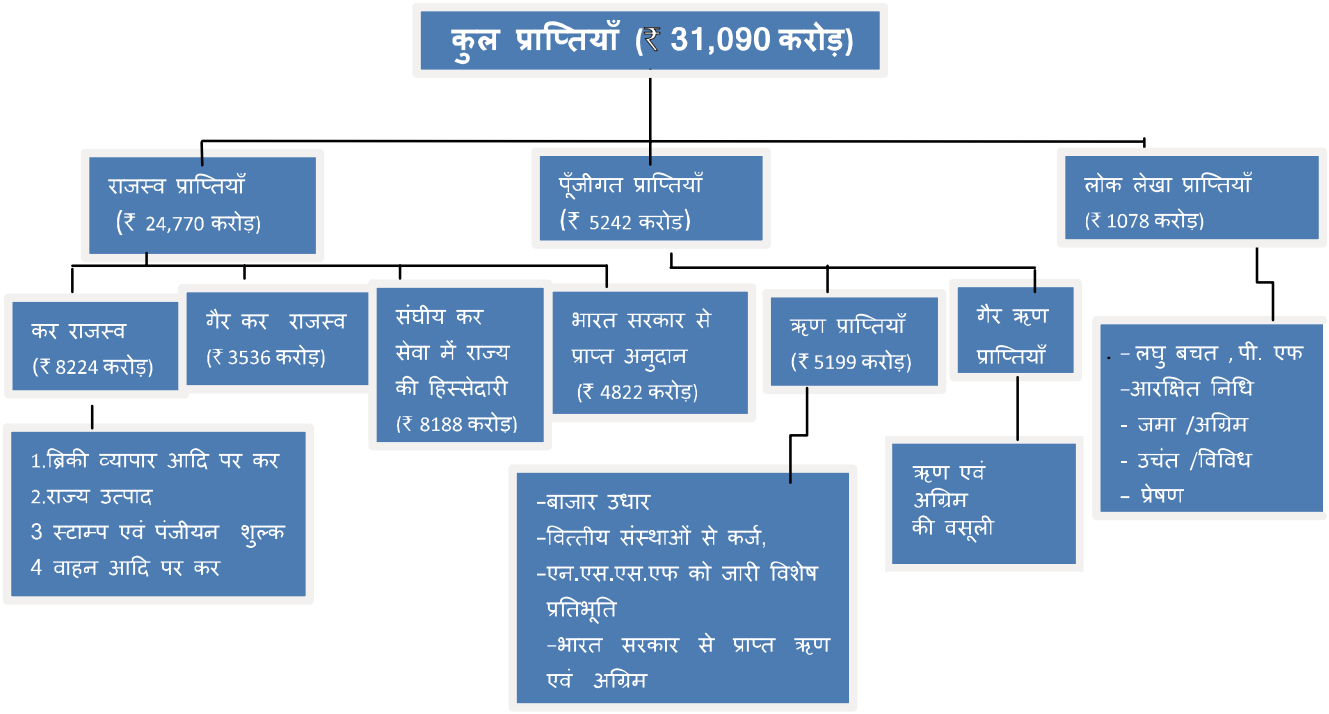
1.2 राज्य के संसाधन

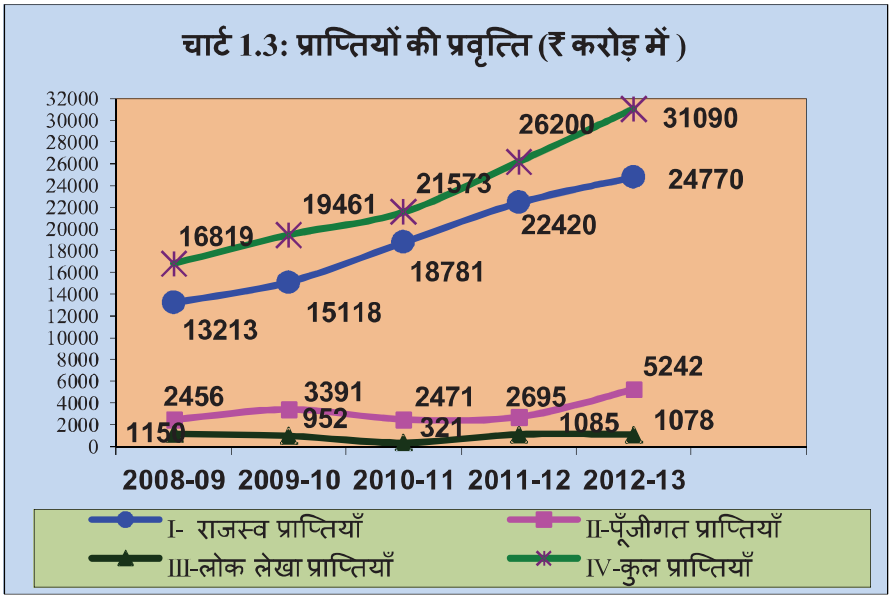
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधन है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा- विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात् लोक खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। **तालिका 1.1** (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण को प्रस्तुत करता है जैसा कि वार्षिक वित्त लेखे में वर्णित है जबकि, **चार्ट 1.2** वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है एवं **चार्ट 1.3** वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के संसाधन की संरचना को चित्रित करता है।

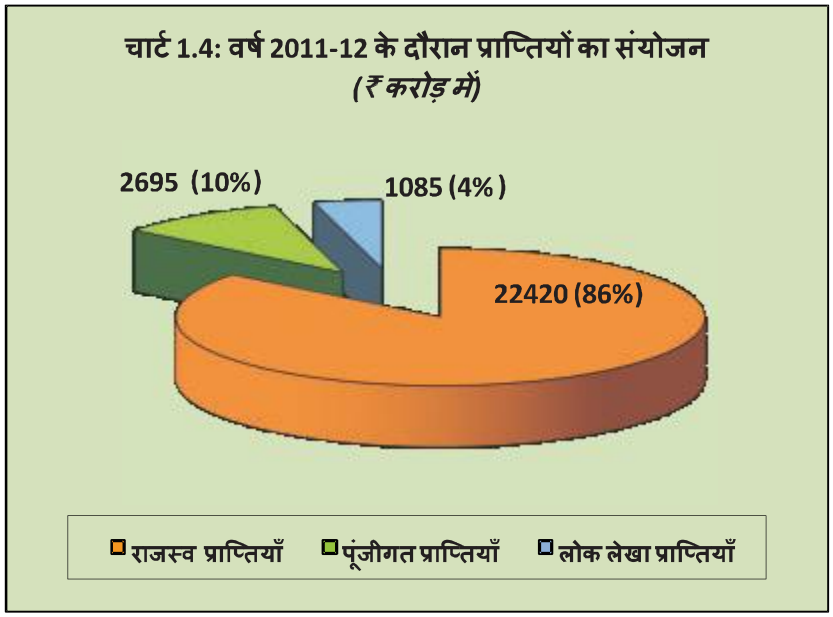
नीचे फ्लो चार्ट के माध्यम से संसाधनों के घटक तथा उप-घटक को दर्शाया गया है।

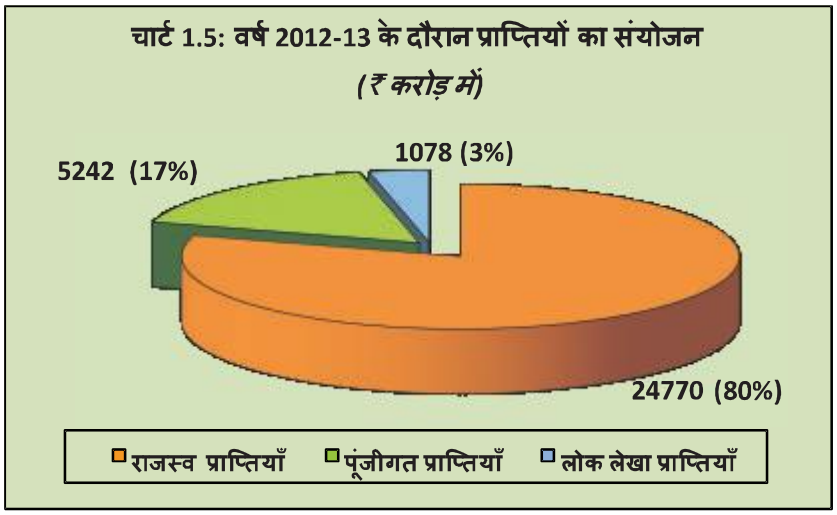
चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





चार्ट 1.4 एवं **चार्ट 1.5** क्रमश: वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते हैं।





- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 के ₹ 16,819 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 31,090 करोड़ हो गयी। कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 19 *प्रतिशत* थी।
- वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 78 *प्रतिशत* से 87 *प्रतिशत* के बीच चलायमान रही। पूँजीगत प्राप्तियों में तुलनात्मक उच्चतर वृद्धि के कारण यह वर्ष 2010-11 के 87 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011-12 में 86 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2012-13 में 80 *प्रतिशत* हो गई।
- ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँजीगत प्राप्तियों से ऋण एवं अग्रिम को घटाकर) वर्ष 2008-09 के ₹ 2437 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 5199 करोड़ हो गयी। आंतरिक ऋण में 91 *प्रतिशत* की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण-पूँजीगत प्राप्तियों में 95 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। वर्ष 2008-13 के दौरान ऋण-पूँजीगत प्राप्तियाँ का सी.ए.जी.आर. की 20.9 *प्रतिशत* था।

- शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 के ₹ 1150 करोड़ (कुल प्राप्तियों का चार *प्रतिशत*) से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1078 करोड़ (कुल प्राप्तियों का तीन *प्रतिशत*) हो गयी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों, जिसे विषम के रूप में पहचान की गई, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों[1] को केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में निधि प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई। वर्तमान प्रक्रिया में यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती है। इस प्रकार, इन निधियों के व्यय का जिक्र राज्य के वित्त लेखे में नहीं किया गया है। अत: वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता का संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, राज्य अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशि को **तालिका 1.4** में दिखाया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 2621.91 करोड़ की केन्द्रीय राशि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित किया गया। भारत सरकार द्वारा सहायक कार्यक्रमों जिसकी राशि हस्तांतरित की गई एवं संबंधित राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को **तालिका 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणो को सीधे हस्तांतरित राशि	
		2011-12	2012-13
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	917.77	0.00
	झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	0.00	809.17
इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	215.48	138.27
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यालय	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	84.67	10.23
सर्व शिक्षा अभियान	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	579.03	561.84
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन: स्वास्थ्य शिक्षा एवं संसार के लिए मानव संसाधन	(i) झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संस्था, टी.बी. नियंत्रण संस्था एवं अंधापन	609.65	281.32

[1] राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वैसे संगठन, (संस्थान, गैर- सरकारी संगठन सहित, जो भारत सरकार से निधि प्राप्त करते है, राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में सम्मिलित है। जैसे एस. एस. ए. के लिए राज्य कार्यान्वयन संख्याएन- आर.एच.एम. के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन।

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणो को सीधे हस्तांतरित राशि	
		2011-12	2012-13
	नियंत्रण संस्था (ii) झारखण्ड एड्स नियंत्रण संस्था		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना	झारखण्ड राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	220.82	307.23
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला अधिकारी	69.00	88.50
गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ	गैर सरकारी संस्थाएं एवं अन्य संस्थाएं	1498.00	425.35
कुल		4194.42	2621.91

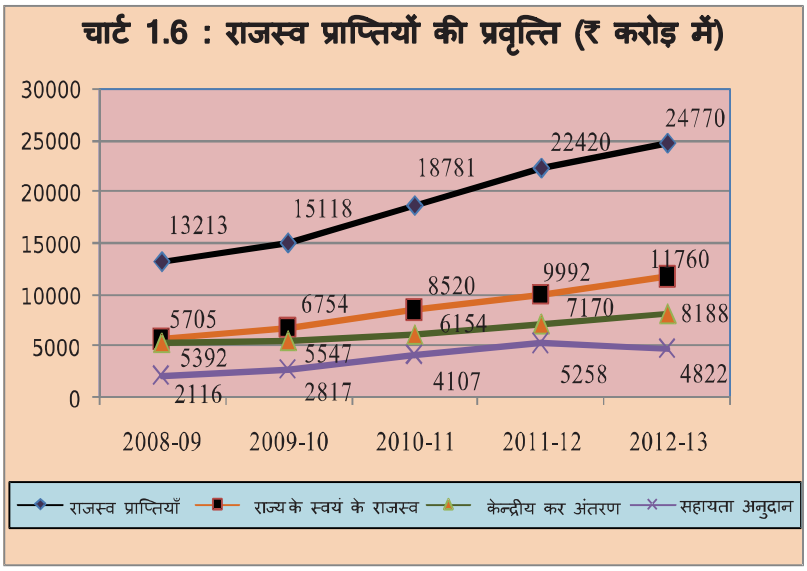
स्रोत: वित्त लेखे का परिशिष्ट VII

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से राशियों का प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण होने के कारण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के अनुचित उपयोग के जोखिम जारी रखा। जब तक इन सभी अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड को व्यय का ससमय प्रतिवेदन एवं उचित दस्तावेज के साथ समरूप रेखांकन पद्धति का अनुसरण नहीं किया, तब तक प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित ऐसी राशियों के पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण मुश्किल होगा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-II सरकार के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2008-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियों को ***परिशिष्ट 1.3*** में दिखाया गया है एवं **चार्ट 1.6** में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.6 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



- वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष के सापेक्ष 10.48 *प्रतिशत* बढ़ी। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7656 करोड़ कम थी। वर्ष 2008-13 के दौरान राजस्व प्रप्तियों का सी.ए.जी.आर. 17.0 *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2008-11 के दौरान स्वयं का कर, कर-भिन्न राजस्व से दोगुना था जो वर्ष 2011-13 के दौरान बढ़कर 2.3 गुना हो गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान से कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 *प्रतिशत* प्राप्त हुआ जबकि राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान शेष 47 *प्रतिशत* रहा।
- वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,770 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) ₹ 8224 करोड़ (33 *प्रतिशत*), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 3536 करोड़ (14 *प्रतिशत*), केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) ₹ 8188 करोड़ (33 *प्रतिशत*) और सहायता अनुदान ₹ 4822 (20 *प्रतिशत*) सम्मिलित था। पिछले वर्ष की अपेक्षा ओ.टी.आर., एन.टी.आर. तथा सी.टी.टी. के तहत में प्राप्तियों में क्रमश: 18 *प्रतिशत*, 16 *प्रतिशत*, तथा 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि सहायता अनुदान के तहत प्राप्त राशि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान घटकर 8 *प्रतिशत* कम हो गई।

  स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5 स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**13,213**	**15,118**	**18,781**	**22,420**	**24,770**
आर.आर. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	9.9	14.4	24.2	19.4	10.5
आर.आर./स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	15.1	15.0	14.9	16.0	15.8
राज्य के स्वयं के कर/स.रा.घ.उ.	4.3	4.5	4.5	4.9	5.2
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5
उत्प्लावकता अनुपात[2]					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	2.15	0.99	0.97	1.66	0.91
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	1.74	1.36	1.08	1.85	1.59
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.24	0.72	0.90	0.90	0.57

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वर्ष 2008-09 के 9.9 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में 24.2 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई। तथापि, यह वर्ष 2011-12

[2] आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे- राजस्व उत्प्लवकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 *प्रतिशत* तक बढ़ेगा।

के दौरान घटकर 19.4 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 10.5 *प्रतिशत* हो गई।

- स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता वर्ष 2008-13 के दौरान 0.91 तथा 2.15 के बीच चलायमान रही। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (9.9 *प्रतिशत*) की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (4.6 *प्रतिशत*) निम्न स्तर पर रहने के कारण यह वर्ष 2008-09 में उच्चतम स्तर (2.15 *प्रतिशत*) पर था। वर्ष 2012-13 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की तुलना में तेजी से घटी जिसके कारण राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2011-12 के 1.66 से गिरकर वर्ष 2012-13 में 0.91 हो गई।
- स्वयं के कर राजस्व तथा स.रा.घ.उ. दोनों की वृद्धि दर में व्यापक विचलन के कारण स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता में वर्ष 2008-13 के दौरान 1.08 और 1.85 के बीच तक का अंतर देखा गया। उत्प्लावकता वर्ष 2008-09 के 1.24 से घटकर वर्ष 2009-10 में 0.72 हो गई, पुन: वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में 0.90 की वृद्धि हुई। तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के स्वयं के कर के वृद्धि दर में कमी के कारण यह अपने निम्नतम स्तर 0.57 पर था जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर समान थी।
- वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 4.6 *प्रतिशत* से 25.0 *प्रतिशत* तक का वृहत् अन्तर दर्ज किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान स.रा.घ.उ. 11.5 *प्रतिशत* बढ़ा। तथापि स.रा.घ.उ. का सी.ए.जी.आर. 15.5 *प्रतिशत* था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने हेतु राज्य के निष्पादन को राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल है के रूप में मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वास्तविक कर तथा कर- भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ 13 वें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) के मूल्यांकन को **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6 कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	13वें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	एम. टी. एफ. पी. अनुमान	वास्तविक
कर राजस्व	9543.88	8734.49	8466 (स.रा.घ.उ. का 5.4 *प्रतिशत*)	8223.58
कर-भिन्न राजस्व	3814.44	3608.66	3136 (स.रा.घ.उ. का 2 *प्रतिशत*)	3535.63

वर्ष 2012-13 के दौरान, ते.वि.आ. के सामान्य अनुमान ₹ 9544 करोड़ तथा एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य ₹ 8446 करोड़ के विरुद्ध राज्य के स्वयं के कर राजस्व का संग्रहण ₹ 8224 करोड़ था। लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण बजट आकलन से बिक्री कर एवं राज्य उत्पाद का कम संग्रहण था। इस वर्ष के दौरान इन शीर्षो के अतंर्गत अनुमानित बजट क्रमश: ₹ 6650 करोड़ तथा ₹ 700 करोड़ के विरुद्ध क्रमश: ₹ 6422 करोड़ तथा ₹ 578 करोड़ का वास्तविक संग्रहण हुआ।

वर्ष 2012-13 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (5.2 *प्रतिशत*) महत्वपूर्ण रूप से ते.वि.आ. के अनुमान 6.50 *प्रतिशत* तथा एम.टी.एफ. पी. के लक्ष्य 5.4 *प्रतिशत* से कम था।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का कर-भिन्न राजस्व (₹ 3536 करोड़) ते.वि.आ. के अनुमान ₹ 3818 करोड़ से कम था, लेकिन एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य ₹ 3136 करोड़ से अधिक था।

1.3.1.1 कर राजस्व

तालिका 1.7 में मुख्य करो तथा शुल्कों के कुल संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में *प्रतिशत* वृद्धि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2996	3597	4473	5522	6422	16.30
राज्य उत्पाद	205	323	388	457	578	26.48
वाहनों पर कर	202	234	312	392	465	18.62
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	192	238	328	401	492	22.69
भूमि राजस्व	53	41	131	53	96	81.13
यात्रियों तथा सामाग्री पर कर	54	13	21	41	1	(-)97.56
अन्य कर	51	54	64	88	170	93.18
कुल कर राजस्व	**3753**	**4500**	**5717**	**6954**	**8224**	**18.26**

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2008-09 के ₹ 3753 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8224 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में इसमें 18 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राज्य के कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2008-13 के दौरान 21.7 *प्रतिशत* रहा। वर्ष 2012-13 में कुल कर राजस्व में बिक्री कर का योगदान 78 *प्रतिशत* रहा, जिसके बाद राज्य उत्पाद कर (सात *प्रतिशत*) स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क (छः प्रतिशत) तथा वाहन कर (छः *प्रतिशत*) का योगदान रहा।

वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2012-13 में वैट/बिक्री कर के कर राजस्व में वृद्धि के लिए वैट की दरों में संशोधन/वृद्धि तथा प्रभावी कर प्रशासन की अनुशंसा की। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में राज्य उत्पाद कर में वृद्धि का कारण खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती तथा विभिन्न प्रकार के शुल्कों की दरों में वृद्धि को बताया गया। इस प्रकार, वर्ष 2012-13 में स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क तथा वाहन कर में वृद्धि का कारण क्रमशः जमीन-जायदाद के मूल्य में वृद्धि तथा निबंधित वाहनों की संख्या में वृद्धि को बताया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान स्थानीय क्षेत्रों में सामान के प्रवेश पर कर की कम वसूली (₹ 40 करोड़) के कारण पिछले वर्ष की तुलना में सामग्री तथा यात्रियों पर कर के संग्रहण में 97.56 *प्रतिशत* की कमी हुई।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

ते.वि.आ. के मानक ₹ 3814 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व ₹ 3536 करोड़ था। कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति को **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: कर भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज प्राप्तियाँ	109.53	153.20	98.74	44.16	72.23
लाभांश एवं लाभ*	0.00	0.00	0.40	1.17	15.00
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	1842.20	2100.95	2703.75	2992.89	3448.40
कुल	**1951.73**	**2254.15**	**2802.89**	**3038.22**	**3535.63**

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

**लाभांश एवं लाभ वर्ष 2008-10 के दौरान शून्य था।*

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.), राजस्व प्राप्तियों का 15 *प्रतिशत* रहा। तथापि, राजस्व प्राप्तियों में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 दोनों में 14 *प्रतिशत* रही। मुख्य रूप से खनन तथा धातुकर्मी उद्योगों में अधिक संग्रहण (₹ 480 करोड़) के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में एन.टी.आर. में 16 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। वर्ष 2008-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 16.0 *प्रतिशत* रहा।

1.3.2 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमोचन की प्रवृत्ति **तालिका 1.9** में दर्शायी गई हैं:

तालिका 1.9: भारत सरकार द्वारा विमोचित घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर-योजना अनुदान	591.91	1145.33	1281.40	1550.77	1483.41
राज्य योजना के लिए अनुदान	1054.18	982.97	1826.99	2404.61	2393.94
केन्द्रीय योजना के तहत अनुदान	31.22	55.05	8.62	66.87	30.81
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	438.57	633.28	990.24	1235.16	914.05
कुल	**2115.88**	**2816.63**	**4107.25**	**5257.41**	**4822.21**
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	15	33	46	28	(-)8
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	16.01	18.63	21.87	23.45	19.47

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 4822.21 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2011-12 के ₹ 5257.41 करोड़ से (आठ *प्रतिशत*) कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में गैर-योजना अनुदान, राज्य योजना अनुदान, केन्द्रीय योजना स्कीम तथा केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदानों में क्रमश: ₹ 67.36 करोड़ (4.34 *प्रतिशत*), ₹ 10.67 करोड़ (0.44 *प्रतिशत*), ₹ 36.06 करोड़ (53.92 *प्रतिशत*) तथा ₹ 321.11 करोड़ (26 *प्रतिशत*) की कमी हुई।
- भारत सरकार से प्राप्त गैर-योजना अनुदान वर्ष 2011-12 के ₹ 1550.27 करोड़ से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1483.41 करोड़ हो गया क्योंकि वर्ष 2011-12 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के फेजिंग आउट के कारण हुये राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त हुआ था।
- वर्ष 2012-13 में राज्य योजना अनुदान वर्ष 2011-12 में प्राप्त अनुदान के लगभग बराबर ही था।
- ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के तहत वर्ष 2012-13 में राज्य को कोई ऋण राहत प्राप्त नहीं हुआ।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2011-12 के ₹ 7170 करोड़ के विरुद्ध केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) वर्ष 2012-13 में ₹ 8188 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में राज्य के केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 1018 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि

मुख्यत: निगम कर (₹ 119 करोड़), निगम कर के अलावे आय-कर (₹ 327 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 118 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 340 करोड़) के अंतर्गत हुई। सी.टी.टी. वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 33 *प्रतिशत* थी।

1.3.4 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने झारखण्ड सरकार को अपने विभिन्न विभागों के कार्यों में सुधार हेतु अनुदान की सिफारिश की। उन अनुदानों में से कुछ अनुदानों की वित्तीय स्थिति **तालिका 1.10** में दी गयी है:

तालिका 1.10: 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अन्तरण	13वें वित्त आयोग के सिफारिश से प्राप्त राशि	संबद्ध लेखा शीर्ष के तहत व्यय	अप्रयुक्त राशि
1	गृह विभाग	74.50	74.50	0.00
2	वित्त संस्थागत तथा कार्यक्रम अनुपालन विभाग	23.28	0.00	23.28
3	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	50.00	47.25	2.75
4	कानून विभाग	40.47	4.96	35.51
5	झारखण्ड उच्च न्यायालय	0.40	0.09	0.31
6	योजना एवं विकास विभाग	9.60	0.00	9.60
7	आपदा प्रबंधन विभाग	291.04	279.24	11.80
8	ग्रामीण विकास विभाग	37.13	37.13	0.00
9	शहरी विकास विभाग	90.60	33.48	57.12
10	जल संसाधन विभाग	24.67	0.00	24.67
11	लघु सिंचाई विभाग	2.33	0.00	2.33
12	खेल, कला, संस्कृति एवं युवा मामलों का विभाग	9.00	9.00	0.00
13	ग्रामीण कार्य विभाग	79.00	72.08	6.92
14	पंचायती राज	357.70	361.96	-4.26
15	प्राथमिक एवं लोक शिक्षा	308.00	308.00	0.00
16	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	108.00	108.01	-0.01
	कुल	**1505.72**	**1335.70**	**170.02**

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

इस प्रकार उपरोक्त **तालिका 1.10** से देखा जा सकता है कि ते.वि.आ. की सिफारिशों के तहत झारखण्ड सरकार को प्राप्त अनुदान की कुल बजटीय राशि (₹ 1505.72 करोड़) में से वर्ष 2012-13 के अन्त तक ₹ 1335.70 करोड़ खर्च की गई तथा ₹ 170.02 करोड़ अप्रयुक्त रही। योजना-वार ब्यौरे ***परिशिष्ट 1.5*** में दिये गये हैं।

1.3.5 त्यक्त राजस्व

1.3.5.1 करों की कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि कर, राज्य उत्पाद कर, भूमि राजस्व, वाहन कर, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, बिजली तथा खनन प्राप्तियों पर शुल्क एवं कर की 130 इकाईयों के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान, हमने ₹ 1532.94 करोड़ से संबंधित कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण के 25,784 मामले पाये। वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने ₹ 568.52 करोड़ के 21,063 मामलों को स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान विभाग ने 1024 मामलों (पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा अवलोकन के विरुद्ध वसूली के साथ) में ₹ 702 करोड़ की वसूली को प्रभावित किया।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2013 तक चार विभागों (वित्त (वाणिज्य कर), राज्य उत्पाद, वाहन कर तथा खनन एवं भू-विज्ञान विभाग) में ₹ 2986.09 करोड़ की बकाया राजस्व की राशि में से ₹ 1343.30 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का मुख्य भाग वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग (₹ 1940.85 करोड़) और खनन तथा भू-विज्ञान विभाग (₹ 763.17 करोड़) से संबंधित था।

31 मार्च 2013 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के कुल राजस्व का 12 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधन का 25 *प्रतिशत* था।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की राजस्व प्रप्तियों के अलावे, राज्य पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त करता है जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम की वसूली, वित्तीय संस्थाओं से सरकार का आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। पूँजीगत प्रप्तियों का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: प्राप्तियों की संरचना तथा वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूँजीगत प्राप्तियाँ *(सी.आर.)*	2456	3391	2471	2695	5242
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	19	22	24	24	43
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2437	3369	2447	2671	5199
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	20.5	38.2	(-)27.4	9.2	94.6
गैर ऋण् पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	(-)56.8	15.6	9.1	0.0	79.2
स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5
पूँजीगत प्राप्तियों का वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	18.8	38.1	(-)27.1	9.1	94.5

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वर्ष 2011-12 के ₹ 2695 करोड़ के सापेक्ष पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 5242 करोड़ की वृद्धि हुई। आगे, बाजार ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 के ₹ 1254 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 3600 करोड़ हो गई। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि झारखण्ड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से ₹ 19.75 करोड़ की वसूली के कारण हुआ। ऋण तथा गैर- ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान विनिवेश से आय 'शून्य' था।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम से वसूली

दिए गए ऋण एवं अग्रिम की तुलना में वसूली काफी कम रही। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त वसूली एवं दिए गए ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋणों का आरंभिक शेष	6016	6415	6713	6997	7190
दिया गया ऋण	418	320	308	21	601
की गई वसूली	19	22	24	24	43
ऋणों का अंतिम शेष	6415	6713	6997	7190	7748

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने वाला मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु, इसके विरुद्ध कोई वसूली नहीं की गई जिससे जे.एस.ई.बी. के विरुद्ध बकाया की राशि ₹ 7125.21 करोड़ हो गई। प्रत्येक

वर्ष प्राप्त किया गया पुनर्भुगतान मुख्य रूप से सरकारी सेवकों को दी गई ऋण एवं अग्रिम के विरुद्ध था। वर्ष 2008-13 दौरान दिये गये ऋण तथा ऋण के अंतिम शेष का सी.जी.ए.आर. क्रमश: 9.5 *प्रतिशत* और 4.8 *प्रतिशत* था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए राज्य ने आंतरिक बाजार से निधि प्राप्त की। आंतरिक बाजार उधार वर्ष 2008-09 के ₹ 2434 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 4960 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान आंतरिक कर्ज में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 3600 करोड़) तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त ऋण (₹ 750 करोड़) का था। वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया अर्थोपाय अग्रिम ₹ 369 करोड़ था।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम वर्ष 2008-09 के ₹ तीन करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2009-10 में घटकर (-) ₹ 10 करोड़ की हो गई जो पुन: वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 132 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में पुन: ₹ 33 करोड़ की कमी हुई जो वर्ष 2012-13 में पुन: बढ़कर ₹ 239 करोड़ हो गयी। भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम मुख्यत: राज्य योजनाओं के लिए प्राप्त किये गये। वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नया ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा - लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते है तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते हैं, के संदर्भ में प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ सरकार साहूकार/महाजन का कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् सरकार के पास उपलब्ध शेष निधि सरकार के उपयोग के लिए होती है। **तालिका 1.13** में लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ *करोड़ में*)

विभिन्न शीर्षों के तहत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियाँ	8335	8242	7721	10813	14495
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	584	687	572	613	668
आरक्षित निधि	86	489	*शून्य*	138	280
जमा तथा अग्रिम	4250	4150	3670	5236	8706
उचंत तथा विविध	96	204	181	306	199
प्रेषण	3319	2612	3298	4520	4642

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

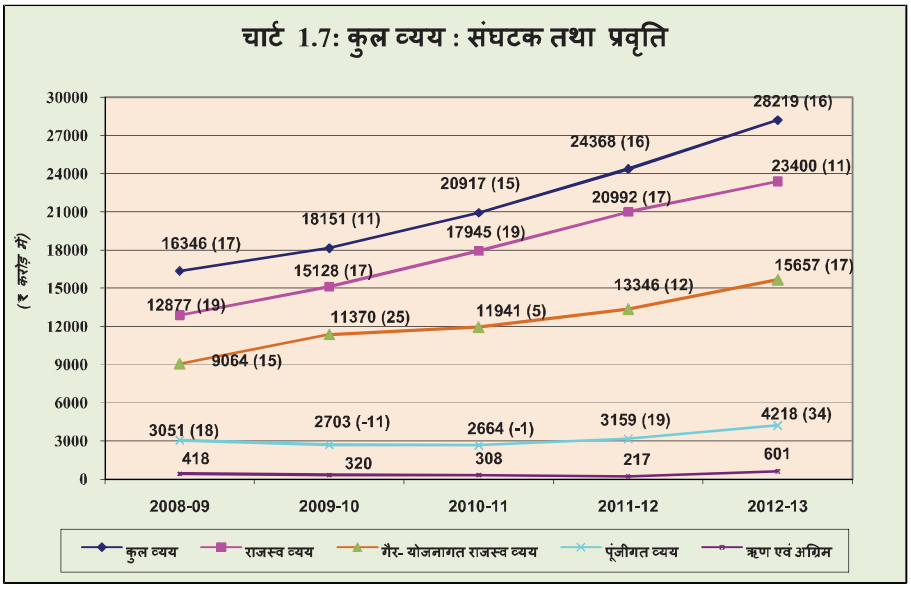
लोक लेखा प्राप्तियों में जमा तथा अग्रिम वर्ष 2011-12 के ₹ 5236 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8706 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि में ₹ 1005 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि तथा बाजार ऋण में ₹ 2346 करोड़ का निक्षेप था। वर्ष 2008-13 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 14.8 *प्रतिशत* था।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन्हें वृहत व्यय करने का कार्यभार सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बढ़ाने में बजटीय बाध्यता होती है। अत: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया लागत व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिये निर्देशित व्यय पर नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2008-13) के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटकों को दर्शाता है।



- विगत पाँच वर्षों से कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. वृद्धि दर 14.60 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय की वृद्धि दर 16 *प्रतिशत* थी।
- कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 83 *प्रतिशत* जबकि पूँजीगत व्यय 15 *प्रतिशत* था। संवितरित ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का केवल दो *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय कुल व्यय का क्रमश: 56 *प्रतिशत* तथा 44 *प्रतिशत* था। यह वर्ष 2011-12 के दौरान क्रमश: 55 *प्रतिशत* तथा 45 *प्रतिशत* था। गैर-योजना व्यय में ₹ 2356 करोड़ तथा योजना व्यय में ₹ 1495 करोड़ की वृद्धि के कारण कुल व्यय में ₹ 3851 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

- वर्ष 2012-13 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 3159 करोड़ से बढ़कर ₹ 4218 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय का बजट वर्ष 2011-12 के ₹ 6353 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6857 करोड़ हो गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 13 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 15 *प्रतिशत* हो गयी। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 2.2 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2012-13 में 2.7 *प्रतिशत* रही।
- शिक्षा क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 75.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 मे ₹ 90.76 करोड़ हो गया। तथापि, पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के बजटीय राशि ₹ 133.60 करोड़ से काफी कम था ।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 422.61 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 487.43 करोड़

हो गया। जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास के लिए वर्ष का बजट ₹ 1035.20 करोड़ था।

1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

राजस्व व्यय वर्ष 2011-12 के कुल व्यय के 86 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2012-13 में कुल व्यय का 83 *प्रतिशत* रहा। राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 के ₹ 12,877 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 23,400 करोड़ (82 *प्रतिशत* की वृद्धि) हो गया। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 16.1 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2012-13 में राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 15 *प्रतिशत* था। स.रा.घ.उ. के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता वर्ष 2011-12 के 1.45 से घटकर वर्ष 2012-13 में 1.00 हो गया, क्योंकि राजस्व व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 17 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में 11 *प्रतिशत* हो गयी जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर लगभग बराबर रही।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 11,254 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) ₹ 7743 करोड़ था। योजना राजस्व व्यय में वर्ष 2011-12 के ₹ 7646 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 7743 करोड़ की अत्यल्प वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय में योजना राजस्व व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 36 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में 33 *प्रतिशत* हो गयी। योजना राजस्व व्यय में स्थिरता सामान्य सेवाओं (₹ 224 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (परिवहन में ₹ 168 करोड़) में कमी के साथ सामाजिक सेवाओं में (₹ 511 करोड़) वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2008-13 दौरान योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 19.4 *प्रतिशत* था।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2012-13 में ₹ 15433 करोड़ के ते.वि.आ. की सिफारिश तथा ₹ 16547 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 15657 करोड़ था। पिछले वर्ष की अपेक्षा गैर-योजना राजस्व व्यय वर्ष 2011-12 के 12 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 17 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2008-13 के दौरान कुल राजस्व व्यय से गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता 64 *प्रतिशत* से 75 *प्रतिशत* के बीच चलायमान रही। वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 67 *प्रतिशत* रहा। राज्य के गैर-योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2008-13 के दौरान 14.6 *प्रतिशत* रहा।

वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यत: शिक्षा (₹ 2863.69 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 550.74

करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 302.54 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास व शहरी विकास (₹ 282.19 करोड़) पर किया गया। आर्थिक सेवाओं के तहत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यत: ऊर्जा (₹ 1102.15 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 691.42 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 611.03 करोड़) तथा परिवहन (₹ 380.73 करोड़) पर किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय शामिल है। **तालिका 1.14** तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2008-13 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.14: वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

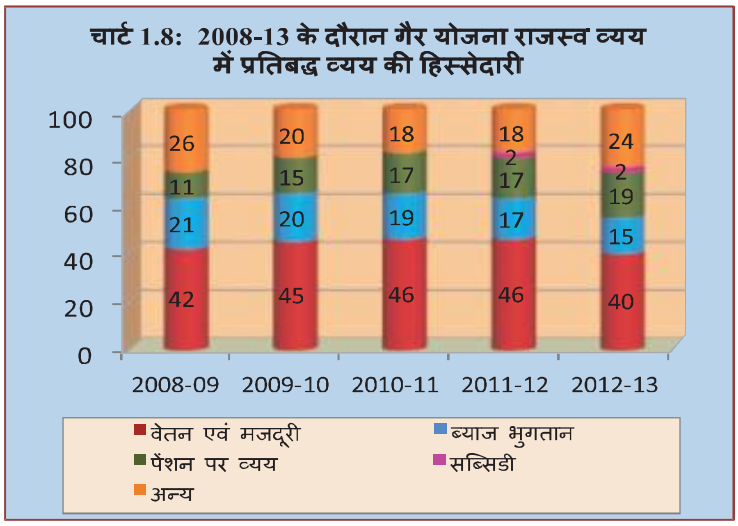
प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट आकलन#	वास्तविक
वेतन* और मजदूरी, जिसमें	3948(30)	5342(35)	5642(30)	6352(28)	8288	6446(26)
गैर योजना शीर्ष	3801(29)	5154(34)	5434(29)	6150(27)	7773	6270(25)
योजना शीर्ष	147(1)	188(1)	208(1)	202(1)	515	176(1)
ब्याज भुगतान	1887(14)	2307(15)	2228(12)	2267(10)	2435	2391(10)
पेंशन पर व्यय	988(7)	1681(11)	2081(11)	2297(10)	2228	2931(12)
सब्सिडी	37(0.3)	41(0.3)	80	286(2)	¥	270(1)
कुल	**6860 (52)**	**9371(62)**	**10031(53)**	**11202(50)**	**12951**	**12054(49)**
(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)						

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

** इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।*

बजट अनुमान के सकल आँकड़ें जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़ें हैं।

¥ बजट उपलब्ध नहीं है।



वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय के सापेक्ष सब्सिडी की प्रतिशतता लगभग नगण्य रही।

वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 6446 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2391 करोड़) और पेंशन (₹ 3961 करोड़) और पेंशन (₹ 2931 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 50 *प्रतिशत* लेखापित था तथा राजस्व प्राप्तियों का 48 *प्रतिशत* था। वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर कुल गैर-योजना व्यय सम्मिलित रूप से गैर-योजना राजस्व व्यय का 74 *प्रतिशत* लेखापित था।

- वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय का 28 *प्रतिशत* से 35 *प्रतिशत* व्यय किया गया। राजस्व व्यय से वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 30 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में 28 *प्रतिशत* हो गयी। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियों से वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशतता भी वर्ष 2011-12 के 28 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में 26 *प्रतिशत* हो गयी। वेतन एंव मजदूरी का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2008-13 के दौरान 13 *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत वेतन पर व्यय (₹ 6270 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 120 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक अनुमान (₹ 5401 करोड़) से ₹ 869 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- पेंशन पर व्यय 31.2 *प्रतिशत* के सी.ए.जी.आर. से बढ़कर वर्ष 2008-09 के ₹ 988 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 2931 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान वृद्धि दर भी पिछले वर्ष के सापेक्ष 28 *प्रतिशत* था। इससे वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान (₹ 2228 करोड़) ₹ 703 करोड़ (32 *प्रतिशत*) तक अधिक हो गया।
- भविष्य में पेंशन तथा पेंशनरी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया है। राज्य ने नयी पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ. के ₹ 3017 करोड़ के मानक प्रक्षेपण के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2391 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पाँच *प्रतिशत* थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 10 *प्रतिशत* ही थी। वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 6.1 *प्रतिशत* था।

- वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक **तालिका 1.15** में दिए गये हैं:

तालिका 1.15: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2011-12	औसत ब्याज दर	2012-13	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	1941.20	8.94	2013.33	8.50
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	165.81	7.23	185.95	8.18
लघु बचत भविष्य निधि	157.76	10.58	186.23	12.09
कुल	**2264.77**	**8.88**	**2390.51**	**8.67**

सब्सिडी

- वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 270 करोड़[3] का भुगतान सब्सिडी के रूप में शीर्ष 2401-फसल उत्पादन (₹ 178.24 करोड़), 2404-डेयरी विकास (₹ 20.44 करोड़) तथा शीर्ष 2852-उद्योग (₹ 56.37 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2011-12 के ₹ 286 करोड़ की सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान सब्सिडी की राशि ₹ 270 करोड़ थी।
- वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे के **परिशिष्ट-III** के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।
- सब्सिडी न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु लोगों को सब्सिडी वाली लोक सेवा प्रदान करने हेतु परोक्ष रूप से भी दी जाती है। वर्ष 2012-13 के लेखाओं की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि विद्यार्थियों को साइकिल वितरण के लिए दिए गये ₹ आठ करोड़ (अनुदान सं. 58) में से ₹ 3.17 करोड़ का ही इस्तेमाल किया गया। पुन: जे.एस.इ.बी. को उसके संसाधन अंतर को पाटने हेतु सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1000 करोड़ की राशि प्रदान की गई।

1.6.4 मुख्य कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फ्लैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुई, जिसके लिए बजट में राज्य योजना (एस.पी.) तथा केन्द्रीय योजना (सी.पी.) के तहत निधियाँ प्रदान की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 17,089 करोड़ का बजट बनाया गया, जिसमें से ₹ 11,279 करोड़ का उपयोग किया गया जबकि केन्द्रीय योजना हेतु किये गये बजट ₹ 2516.35 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1158.92 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर राज्य योजना तथा केन्द्र योजना के

[3] वित्त लेखे के *परिशिष्ट-III*

अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16 मुख्य कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1.	मुख्य सड़कें	1117.23	1006.26
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	382.49	356.49
3.	मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना	488.51	458.21
4.	स्वर्ण रेखा परियोजना	348.82	319.13
केन्द्रीय योजना			
1.	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम	914.61	593.83
2.	समन्वित शिशु विकास कार्यक्रम	323.94	300.52
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	183.85	184.71

मध्याहन भोजन (मिड डे मील) पर कम व्यय होने के कारण प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम पर व्यय (₹ 593.93 करोड़), बजट आकलन ₹ 914.61 करोड़ की तुलना में बहुत ही कम था।

स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना : यह परियोजना वर्ष 1973 में शुरू हुई तथा इसे वर्ष 1987-88 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना की प्रारंभिक लागत ₹ 90 करोड़ थी, जिसे पाँचवें संशोधन के पश्चात् ₹ 4540 करोड़ की लागत से वर्ष 2009-10 में पूरा करने हेतु लक्षित किया गया। परियोजना को त्वरित सिंचाई कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया तथा ₹ 6613.74 करोड़ की अनुमानित राशि के साथ वर्ष 2013-14 तक इसको पूर्ण करने हेतु पुनर्निधारित किया गया। परियोजना का उद्देश्य राज्य के 236846 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के अतिरिक्त प्रदेश के आदिवासी जनसंख्या को लाभ देने के क्रम में औद्योगिक एवं घरेलू उद्देश्यों हेतु 825 मिलियन घन मीटर जलापूर्ति उपलब्ध कराना था।

वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे के अनुसार राज्य योजना, विश्व बैंक सहायता, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से परियोजना हेतु राशियाँ उपलब्ध कराई गयी तथा 31 मार्च 2013 तक इस योजना पर कुल ₹ 1276 करोड़ का व्यय किया गया।

25 वर्ष समाप्त होने तथा ₹ 1278 करोड़ की राशि व्यय होने के पश्चात् भी 31 मार्च 2013 तक परियोजना अपूर्ण ही थी।

1.6.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.17** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.17 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पंचायती राज्य संस्थाएं (पी.आर.आई.)		875.69	581.06	485.85
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	485.14	246.15	25.34	182.43
सार्वजनिक उपक्रम	602.64	491.55	777.00	शून्य
स्वायत्त निकाय	678.31	607.55	677.85	208.26
गैर-सरकारी संस्थाएं	17.87	192.43	209.68	शून्य
अन्य	548.98	708.34	2259.30	550.71[4]
कुल	**2332.94**	**3121.71**	**4530.23**	**1427.25**
राजस्व व्यय, *प्रतिशत* के रूप में	15.42	17.31	21.58	6.09

स्रोत: वित्त लेखे के विवरणी 8 ।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता वर्ष 2009-10 के ₹ 2332.94 करोड़ से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1427.25 हो गयी। ते.वि.आ. ने पी.आर.आई. तथा यू.एल.बी. के लिए क्रमश: ₹ 1516.60 करोड़ तथा ₹ 425.80 करोड़ की अनुशंसा की थी। उपरोक्त तालिका में दिखायी गई पी.आर.आई. तथा यू.एल.बी. को सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय लेखा शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 तथा 198 के अन्तर्गत पंचायती राज्य संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकायों को प्रदत्त (₹ 727 करोड़) की सहायता राशि शामिल नहीं है। वर्ष 2009-13 के दौरान सहायता राशि की वृद्धि दर (-) 68 *प्रतिशत* से 34 *प्रतिशत* के बीच चलायमान रही।

1.6.6 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली

स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यों यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था। पुन: ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को अनुदान, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों

[4] उपायुक्तों को समन्वित क्रिया योजना (आई.ए.पी.) (₹ 510.00 करोड़), (ii) सहकारी संघों (₹147.07 करोड़), उप-सचिव, परिवहन (₹ 486.70 करोड़) तथा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास (₹ 255.81 करोड़) को कम वित्तीय अनुदान के कारण कमी

को अनुदान और 193-नगर पंचायतों को अनुदान के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने ***परिशिष्ट 1.6*** में इंगित सभी 18 कार्यों को समाविष्ट करते हुए फरवरी 2012 में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 को अधिनियमित किया। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी. (नगर निगम-3, नगरपरिषद-14, नगर पंचायत-19, नगरपालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) है।

तालिका 1.18 से देखा जा सकता है कि झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2008-13 के दौरान यू.एल.बी. को कुल ₹ 1674 करोड़ के अनुदानों का भुगतान किया। तथापि, वर्ष 2009-13 के दौरान अनुदानों का विमोचन कम था। मल व्यवस्था, जल निकास, जल आपूर्ति, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का निर्माण, नागरिक सुविधाओं, भवन निर्माण, भू-अधिग्रहण इत्यादि हेतु सहायता राशि में कम विमोचन के कारण वर्ष 2011-12 में सहायता राशि घटकर ₹ 25 करोड़ हो गयी। यू.एल.बी. को दी गई निधियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.18: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	13213	15118	18781	22420	24770	94302
राज्य का राजस्व व्यय (रा. व्यय)	12877	15128	17945	20992	23400	90342
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	736	485	246	25	182	1674
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का *प्रतिशत*	5.58	3.21	1.31	0.11	0.73	1.78
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की *प्रतिशतता*	5.72	3.21	1.37	0.12	0.78	1.85
स्वयं के संग्रह[5]	-	-	3.23	18.84	शून्य	22.07

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2013 तक स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुन:

[5] अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग को नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों (वर्ष 2010-11 : नगर पंचायतें - वासुकीनाथ, चास, गुमला, खूँटी, सिमडेगा और नगरपालिका परिषद् लोहरदगा तथा वर्ष 2011-12 नगर पंचायतें - विश्रामपुर, चकुलिया, कोडरमा, राजमहल, नगरपालिका - जुगसलाई और रॉची नगर निगम) के लेखापरीक्षा के दौरान उदभेदित हुआ कि इस अवधि के दौरान ₹ 22.07 करोड़ एकत्रित किए गए।

स्थानीय निकायों को कार्यों तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2013)। उनका जवाब अभी तक अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का कार्यभार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत् राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रदत तकनीकी दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा करने संबंधी प्रावधान अंतर्निहित है । राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) किया परन्तु डी.एल.एफ.ए. को अभी तक परिचालित नहीं की गई है और परीक्षक- स्थानीय लेखा अप्रैल 2012 से तकनीकी दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार जाँच परीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, लघु-शीर्षों 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमोचित निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4706 पंचायती राज संस्थाएँ[6] हैं। **तालिका 1.19** के अनुसार, वर्ष 2009-10 तक सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को कोई अनुदान नहीं दिया। वर्ष 2010-13 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 1943 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

[6] 24 जिला परिषद, 259 पंचायत समिति, 4423 ग्राम पंचायत

तालिका 1.19 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	13213	15118	18781	22420	24770	94302
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्यय)	12877	15128	17945	20992	23400	90342
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता*	-	-	876	581	486	1943
आर.आर. से वित्तीय सहायता की *प्रतिशतता*	-	-	4.66	2.59	1.96	2.06
आर.ई. से वित्तीय सहायता की *प्रतिशतता*	-	-	4.88	2.77	2.08	2.15
स्वयं संग्रह **	-	-	-	-	-	-

*पी.आर.आई. का चुनाव दिसम्बर 2010 में हुआ था।

**राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2013 तक पंयायती राज संस्थानों को राशियाँ सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों (अनुदानों/कार्यक्रम निधियों के अलावे) के राजस्व स्रोतों की पहचान नहीं की है, क्योंकि पंचायती राज संस्थानों द्वारा अधिरोपित की जाने वाली करों, पथ करों तथा शुल्कों आदि की दर को निर्धारित व अधिसूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2013)।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2012' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा तदनुसार पंचायती राज संस्थानों का लेखांकन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है (नवम्बर 2013)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यत: तीन पहलू यथा-पर्याप्तता (अर्थात् सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

राज्य के कुल व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में 16.5 *प्रतिशत* एवं वर्ष 2012-13 के दौरान 15.8 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 63 *प्रतिशत* था, जबकि गैर-विकास व्यय 37 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2012-13 के दौरान विकास व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष के सापेक्ष 12 *प्रतिशत* था, जबकि गैर-विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष 11 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह अपने क्रम के सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम है।

वर्ष 2009-10 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2012-13 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में **तालिका 1.20** राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.20: वर्ष 2009-10 और वर्ष 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2009-10	18.03	62.22	35.75	14.89	18.01	3.77
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2012-13	17.99	68.49	33.15	14.95	15.95	3.39

* स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में

ए.ई.: सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई.:विकास पर व्यय

एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी.ई.:पूँजीगत व्यय

विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूँजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित अग्रिम सम्मिलित है।

स्रोत: स.रा.घ.उ. के के आँकड़े राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दिये गये हैं।

सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2012-13 में झारखण्ड सरकार ने सकल व्यय पर अपने स.रा.घ.उ. का एक बड़ा भाग खर्च किया।

झारखण्ड में सकल व्यय के एक भाग के रूप में पूँजीगत व्यय के साथ-साथ विकास पर व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में वर्ष 2009-10 में कम रहा जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड द्वारा इस मद में सामान्य श्रेणी के राज्यों तुलना में अधिक खर्च किया गया।

वर्ष 2012-13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी गयी। इन क्षेत्रों में व्यय वर्ष 2009-10 में इसके अपने सकल व्यय के अनुपात की तुलना में कम हो गया है।

1.7.2 व्यय के इस्तेमाल की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स[7] के प्रावधान पर जोर दिया जाय। विकास व्यय[8] हेतु आबटन के अलावा कुल व्यय (और/या स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय के उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी बेहतर होगी।

तालिका 1.21 वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के कुल व्यय के तुलना में विकास योजनाओं की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

---

[7] कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे:- कानून और आदेश का प्रवर्त्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स वे सामग्री हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लोगों को मुफ्त या कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि व्यक्ति या समाज के पास ये सामग्री आवश्यकता, योग्यता और सरकार को भुगतान करने की इच्छा के आधार पर होनी चाहिए और उनके उपयोग को बढ़ाने की इच्छुक हों, इन सामग्रियों के उदाहरण है, पोषण हेतु गरीबों को कम दर पर खाद्यान्न का प्रावधान, जीवन स्तर सुधारने और मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, सभी को आधारभूत शिक्षा का प्रावधान, पेयजल और स्वच्छ इत्यादि ।

[8] व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्चयित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए है। हमारे ऑकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर विकासात्मक व्यय है।

तालिका 1.21: विकास व्यय

(₹ *करोड़ में*)

विकास पर व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय (अ से स)						
अ. विकास पर राजस्व व्यय	7918 (48)	8523(47)	10954(52)	13146(54)	19244	14704(52)
ब. विकास पर पूँजीगत व्यय	2875(18)	2591(14)	2544(12)	3003(12)	6548	4042(14)
स. विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	411 (3)	308(2)	296(1)	199(1)	704	582(2)
कुल	**11204**	**11422**	**13794**	**16348**	**26496**	**19328**
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्यय+पू. व्यय+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़े है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान विकास व्यय की वृद्धि दर 18.23 *प्रतिशत* थी।
- उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से काफी कम था। सामान्य सेवाओं (गैर-विकास) पर व्यय इस वर्ष के ₹ 8890 करोड़ के बजट के सापेक्ष ₹ 8892 करोड़ हुआ।
- वर्ष 2008-13 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 47 *प्रतिशत* एवं 54 *प्रतिशत* के बीच थी। वर्ष 2008-13 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी. आर. 16.7 *प्रतिशत* था।
- कुल व्यय में विकासात्मक पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) की हिस्सेदारी वर्ष 2008-09 के 21 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 प्रत्येक में 13 *प्रतिशत* हो गयी। फिर भी, इसमें वर्ष 2012-13 के दौरान 16 *प्रतिशत* से बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2008-13 के दौरान विकासात्मक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 8.4 *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9357 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9971 करोड़) का हिस्सा कुल विकास व्यय (₹ 19,328 करोड़) का क्रमश: 48 *प्रतिशत* एवं 52 *प्रतिशत* था।

चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हुए पूँजीगत व्यय के ब्यौरे तथा व्यय के घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

समाजिक/आर्थिक ढाँचा	2011-12			2012-13		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर. ई. में, हिस्सा		टी.ई. से सी.इ. का अनुपात	आर. ई में, हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम. *		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवायें (एस. एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.45	54.43	0.00	0.86	47.35	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.57	54.96	0.10	15.38	57.50	0.02
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	48.12	25.80	2.43	43.14	19.16	3.66
कुल (एस.एस)	**10.75**	**40.91**	**0.29**	**11.03**	**34.49**	**0.35**
आर्थिक सेवायें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	7.10	30.99	0.38	1.59	32.92	0.03
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	58.59	98.23	0.00	67.78	97.76	0.00
विद्युत और ऊर्जा	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	49.08	10.72	11.41	67.43	12.83	35.41
कुल (ई. एस.)	**28.40**	**17.05**	**2.92**	**32.02**	**16.34**	**3.24**
कुल (एस.एस.+ ई. एस.)	19.59	30.28	3.21	23.93	26.60	1.60

टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर. ई.: राजस्व व्यय;
एस. और डब्लू: वेतन एवं मजदूरी; ओ.और एम.: संचालन और रख-रखाव;
वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मति के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- कुल विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकासात्मक पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के 19.59 *प्रतिशत* से उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में 23.93 *प्रतिशत* हो गया।
- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन घटक वर्ष 2011-12 के 40.91 *प्रतिशत* एवं 17.05 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में क्रमश: 34.49 *प्रतिशत* एवं 16.34 *प्रतिशत* हो गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष '05-सार्वजनिक सम्पत्ति के रख-रखाव के लिए अनुरक्षण एवं मरम्मति' के अन्तर्गत ₹ 408.83 करोड़ का व्यय किया।

- जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास पर अधिक व्यय के कारण समाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 0.29 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 0.35 *प्रतिशत* हो गयी।
- सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन पर हुए व्यय में वृद्धि के कारण आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 2.92 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 3.24 *प्रतिशत* हो गयी।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न हीं केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रीम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और अस्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2012-13 के परिशिष्ट-IX के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

मार्च 2013 तक या उससे पहले पूर्ण होने वाले अपूर्ण परियोनाओं पर बाधित निधि व्यय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मार्च 2013 तक कुल 189 पूँजीगत कार्य, प्रत्येक 10 लाख से अधिक लागत वाले, अपूर्ण थे। इन योजनाओं में कुल ₹ 1972.03 करोड़ बाधित थी। 31 मार्च 2013 तक अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 1.23** में दिया गया है।

तालिका 1.23 : अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(*₹ करोड़ में*)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं* की सं.	आरंभिक अनुमानित लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	31.3.2013 का समुच्चयित कुल व्यय
पथ निर्माण विभाग	134	137.68	22.69	628.05
पेयजल एवं स्वच्छता	11	611.48	24.57	290.35
जल संसाधन	14	1028.82	267.77	884.74
भवन निर्माण	30	131.52	24.55	168.89
कुल	**189**	**1909.50**	**339.58**	**1972.03**
* ₹ 10 लाख से अधिक की लागत वाली योजनाएँ				

स्रोत : वित्त लेखे के परिशिष्ट x

अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या मार्च 2012 में 182 के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के अंत तक 189 थी।

तालिका 1.23 में दिए गए अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने की लक्षित तिथि जून 2000 से मार्च 2013 के बीच थी। अधिकांश परियोजनाओं के पूर्ण करने की पुनरीक्षित तिथियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई। उपरोक्त अपूर्ण परियोजनाओं के लिए अनुमानित राशि (मूल) ₹ 1909.50 करोड़ थी जिसके विरुद्ध मार्च 2013 के अंत तक प्रोग्रेसिव व्यय ₹ 1972.03 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान इन परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय ₹ 339.58 करोड़ था।

1.8.3 निवेश एवं वापसी

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2013 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 11 सरकारी कम्पनियाँ[9] (₹ 31.55 करोड़) एवं 17 सहकारी, कॉरपोरेशन एवं समितियों में (₹ 110.54 करोड़) कुल ₹ 187.82 करोड़ का निवेश किया (**तालिका 1.24**)। निवेश से वापसी (लाभांश) वर्ष 2011-12 के ₹ 1.17 करोड़ (0.64 *प्रतिशत*) के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 15 करोड़ (7.99 *प्रतिशत*) हुआ। तथापि, सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान 7.42 *प्रतिशत* से 8.76 *प्रतिशत* के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में निवेश (**₹** करोड़ में)	**112.47**	**128.73**	**135.18**	**182.57**	**187.82**
लाभांश (**₹** करोड़ में)	शून्य	शून्य	**0.40**	**1.17**	**15.00**
लाभांश (*प्रतिशत* में)	शून्य	शून्य	**0.3**	**0.64**	**7.99**
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर (*प्रतिशत* में)	**7.42**	**8.03**	**7.98**	**7.64**	**8.76**
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (*प्रतिशत* में)	**7.42**	**8.03**	**7.68**	**7.00**	**0.77**

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 14

[9] सरकारी कम्पनियों के संबंध में किये गये निवेशों, संग्रहित लाभ/हानि इत्यादि का विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (लोक उपक्रम) वर्ष 2012-13 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी कम्पनियाँ (₹ 2.50 करोड़) एवं समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं (₹ 2.75 करोड़) में केवल ₹ 5.25 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) का निवेश किया गया। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश पर लाभांश 7.99 *प्रतिशत* था।

पुन: 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

1.8.4 सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) सरकार को सार्वजनिक लाभ के लिए निजी क्षेत्रों के संसाधनों एवं दक्षताओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है। यह व्यवसायिक तौर पर एक नियत समयावधि के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से आधारभूत संरचना के सृजन और/अथवा प्रबंधन हेतु निजी क्षेत्र के निकाय (एक सांविधिक निकाय जिसमें 51 *प्रतिशत* या अधिक का इक्विटी निजी साझेदारी/साझेदारों के पास होता है) और सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय के बीच एक साझेदारी होती है और जिसमें निजी साझेदारों को पारदर्शी एवं खुली प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किया जाता है।

सड़क निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित पाँच सा.नि.सा. परियोजनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान संग्रहित सूचनाएँ **तालिका 1.25** में दी गयी है:

तालिका 1.25: सार्वजनिक -निजी साझेदारी परियोजनाएँ

योजना	अनुबंध की तिथि	प्रारंभ होने की तिथि	समाप्त हाने की निर्धारित तिथि	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि	वार्षिकी प्रारंभ होने की तिथि	कुल योजना लागत (₹ करोड़ में)	वार्षिक भुगतान की जाने वाली वार्षिकी * (₹ करोड़ में)
राँची रिंग रोड (सेक्टर III, IV, V और VI)	25.09.09	25.03.10	21.09.12	21.09.12	22.03.13	620.10	117.82
राँची पतरातू बाँध रोड	14.10.09	13.04.10	12.10.12	12.10.12	12.04.13	263.86	50.13
पतरातू बाँध रामगढ़ रोड	14.10.09	13.04.10	31.12.13	आरंभ नहीं	30.06.14	326.84	62.10
चाईबासा कान्द्रा चौक रोड	28.05.11	27.11.11	26.05.14	आरंभ नहीं	26.11.14	432.99	82.27
आदित्यपुर कान्द्रा रोड	06.08.11	02.02.12	31.01.13	31.01.13	31.07.13	241.15	45.82
कुल						**1884.94**	**358.14**

** परियोजना के समाप्त होने के पश्चात् 15 वर्षों तक वार्षिकी का भुगतान किया जाना है।*

चुँकि, सड़क निर्माण विभाग द्वारा संविदा प्रावधान के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि को परियोजनाओं के अनंतिम रूप से पूर्ण होने की तिथि माना गया, इससे राँची रिंग रोड़

(रा.रि. रो.) को अनंतिम रूप से पूर्ण हुआ मान लिया गया जिसके लिए वर्ष 2012-13 में ₹ 55.65 करोड़ का वार्षिकी भुगतान किया गया।

1.8.5 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2013 तक बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को **तालिका 1.26** प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26 : राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(*₹ करोड़ में*)

अग्रिम /ब्याज प्राप्ति /उधार की लागतों की प्रमात्रा	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	6016	6415	6713	6997	7190
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि (₹ करोड़ में)	418	320	308	217	601
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतित राशि (₹ करोड़ में)	19	22	24	24	43
बकाया ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत के रूप में पुनर्भुगतान	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6
अंतशेष	**6415**	**6713**	**6997**	**7190**	**7748**
निवल योग (₹ करोड़ में)	399	298	284	193	558
ब्याज प्प्तियों (₹ करोड़ में)	0.48	7.64	7.26	2.12	0.95
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	*	0.12	0.12	*	0.01

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

**नगण्य*

- राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2008-09 के ₹ 418 करोड़ से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गयी जो पुन: वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 601 करोड़ हो गयी। वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि मुख्यत: बिजली (शक्ति) परियोजनाओं के अन्तर्गत हुआ (₹ 376.75 करोड़)।
- वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 541.70 करोड़ का ऋण दिया गया जिसमें से ₹ 58.89 करोड़ संचरण के लिए ₹ 17.27 करोड़ त्वरित शक्ति विकास परियोजना के लिए एवं ₹ 120.00 करोड़ वार्षिक विकास कार्यक्रम के लिये दिया गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में 8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। मार्च 2013 के अंत तक प्रमुख बकाया राशि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 7125 करोड़) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 545 करोड़) के पास था।

- 31 मार्च 2013 तक कुल ₹ 1112.44 करोड़ (₹ 341.28 करोड़ मूलधन एवं ₹ 771.16 करोड़ का ब्याज) के ऋण एवं अग्रिम की वसूली किया जाना शेष था। वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम की शेष बकाया राशि ₹ 77.94 करोड़ थी जिसमें ₹ 32.05 करोड़ मूलधन के रूप में तथा ₹ 45.89 करेाड़ ब्याज के रूप में था।

1.8.6 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण **तालिका 1.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2012 को	31 मार्च 2013 को
रोकड़ शेष	116.85	704.75*
रोकड़ शेष से निवेश (अ से स)	4.41	746.57
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	शून्य	742.16
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	4.41
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	42.02	71.27
रिजर्व बैंक में जमा	93.85	(-)56.50
विभागीय रोकड़ शेष	18.59	14.68

**31 मार्च 2013 तक भा. रि. बै. के पास ऋणात्मक शेष होने के कारण रोकड़ शेष निवेश से कम था।*

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के ₹ 116.85 करोड़ के रोकड़ शेष के सापेक्ष 31 मार्च 2013 के अंत तक राज्य का रोकड़ शेष ₹ 704.75 करोड़ था।

मार्च 2012 के अंत में ₹ 4.41 करोड़ के रोकड़ शेष निवेश के सापेक्ष मार्च 2013 के अंत में सरकार के पास रोकड़ शेष निवेश ₹ 746.57 करोड़ था। ₹ 746.57 करोड़ के कुल रोकड़ शेष निवेश में से वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 742.16 करोड़ का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

महालेखाकार (लेखा एवं ह.), झारखण्ड द्वारा 31 मार्च 2013 तक का लेखा जोखा करने पर भा.रि.बै. के पास ₹ 56.50 करोड़ (क्रेडिट) का रोकड़ शेष उपलब्ध था। तथापि, भा.रि.बै. द्वारा सूचित किया गया 31 मार्च 2013 तक का रोकड़ शेष ₹ 57.06 करोड़ (डेबिट) था। 31 मार्च 2013 को ₹ 0.56 करोड़ के अंतर का समाशोधन प्रक्रियाधीन था।

वर्ष 2012-13 के दौरान भा.रि.बै. में न्यूनतम शेष बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को दो दिनों के लिये विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं 11 दिनों के लिये सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा।

1.9 परिसम्पत्तियों एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पतियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

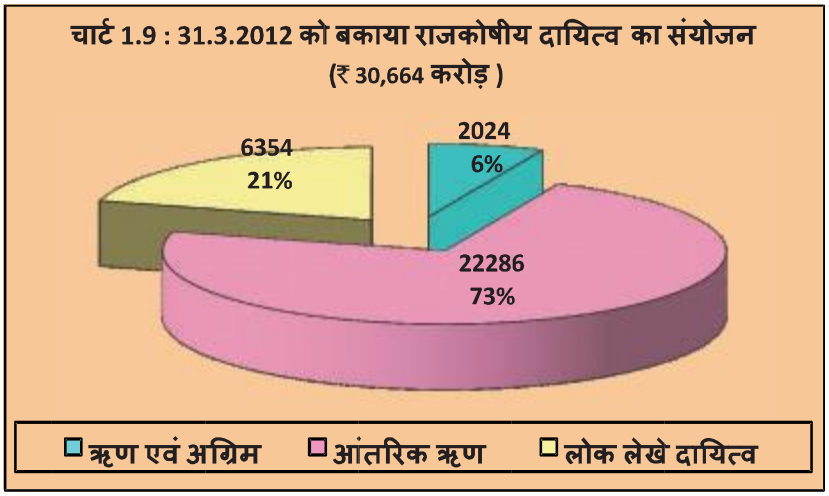
सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकार द्वारा अधिकृत परिसम्पत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहित करते हैं। ***परिशिष्ट 1.4 भाग-बी*** 31 मार्च 2013 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2012 की तदनुरूपी स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यत: आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यत: पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

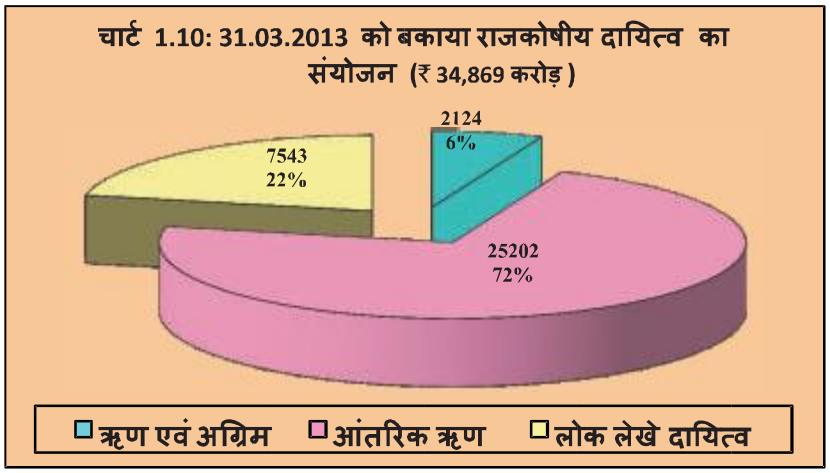
झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य की संचित निधि और लोक लेखे जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमश: **चार्ट 1.9** एवं **चार्ट 1.10** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.9 : 31.3.2012 को बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन
(₹ 30,664 करोड़)





तालिका 1.28 : राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹करोड़ में)

अवयव	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आंतरिक ऋण	17,568	19,880	21,131	22,286	25,202
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2404	2272	2167	2024	2124
लोक लेखे दायित्व	4112	5013	5357	6354	7543
कुल राजकोषीय दायित्व	**24,084**	**27,165**	**28,655**	**30,664**	**34,869**
कुल दायित्वों में वृद्धि	11.4	12.8	5.5	7.0	13.7
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व	27.4	27.0	22.8	21.8	22.2

- जैसा कि **तालिका 1.28** दर्शाया गया है, वर्ष 2008-09 के ₹ 24,084 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व (रा.दा.) 45 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 34,869 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के सात *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में 14 *प्रतिशत* था। तथापि, वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान रा.दा. का सी.ए.जी.आर. 9.7 *प्रतिशत* था।

- राज्य के राजकोषीय दायित्व में ₹ 319.67 करोड़ का आरक्षित निधि (₹ 316.20 राज्य आपदा आरक्षित निधि के रूप में तथा ₹ 3.47 करोड़ सरकारी व्यावसायिक उपक्रमों/विभागों की सामान्य आरक्षित निधि के रूप में) शामिल था।

- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2008-09 के 27.4 *प्रतिशत* से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2011-12 में 21.8 *प्रतिशत* हो गया। यह

अनुपात पुन: वर्ष 2012-13 में बढ़कर 22.2 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, रा.दा./स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता ते.वि.आ. की सिफारिशों के 27.8 *प्रतिशत* से कम थी।

- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा के अलग सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हेतु एक मर्जित निधि, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, सितम्बर 2013 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (सितम्बर 2013) नहीं किया गया।

1.9.3 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 (I) एवं धारा 48 (I) (ए) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्त तक एक राज्य आपदा आरक्षित निधि (एस.डी.आर.एफ.) गठित करने की अनुशंसा की। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. का गठन किया गया (2010-11) एवं आपदा राहत निधि की शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में हस्तांतरित कर दी गयी एवं आपदा राहत निधि समाप्त हो गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान, एस.डी.आर.एफ. में 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष ₹ 440 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियाँ एवं संवितरण क्रमश: ₹ 280 करोड़ एवं ₹ 403 करोड़ था फलस्वरूप मार्च 2013 के अन्त में अंतिम शेष ₹ 317 करोड़ था।

1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति विस्तृत है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार झा.रा.वि.बोर्ड के विरुद्ध ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था जिसमें से ₹ 77.78 करोड़ की प्रत्याभूति वर्ष 2012-13 के दौरान दी गई थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता[10] को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण[11], गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[12], उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता[13], ब्याज भुगतान का भार (के साथ राजस्व प्राप्ति अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूप रेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.29 वर्ष 2008-09 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.29 : ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्रथामिक घाटा)*	(-)2018	(+)647	(+)4753	(+)1509	(+)285
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	(-)1171	103	899	188	(-)39
उधार निधि की निवल उपलब्धता	583	773	(-)737	(-)238	1814
ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	27.4	27.0	22.8	21.8	22.2

[10] समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

[11] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर व्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण * दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवत: सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात संभवत: गिरेगा।

[12] बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेख्नीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

[13] कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों की विस्तार को इंगित करता है।

ऋण धारणीयता के संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	14	15	12	10	10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	775(4)	1183(5)	1868(8)	1449(6)	1381
1 - 3	2508(13)	2885(13)	2977(13)	3080(13)	3031
3 - 5	2829(14)	3263(15)	2872(12)	2623(11)	3358
5 - 7	2635(13)	2569(12)	3284(14)	4302(17)	5009
7 और आगे	11225(56)	12252(55)	12298(53)	12856(53)	14547
कुल	**19972**	**22152**	**23299**	**24310**	**27326**

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

**फार्मूला परिशिष्ट 1.2 पार्ट-ए में है।*

- जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2008-09 के 4.6 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2009-10 में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 14.6 *प्रतिशत* होने के कारण प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार वर्ष 2008-09 में (-) ₹ 2018 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 647 करोड़ हो गया। आगे, वर्ष 2010-11 के दौरान स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर में 25 *प्रतिशत* का सुधार हुआ और प्राथमिक घाटा भी ₹ 116 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष में बदल गया जिससे ऋण संतुलन की स्थिति (प्र.वि+प्रा.धा.) ₹ 4753 करोड़ हो गई। तथापि, प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमश: ₹ 1509 करोड़ एवं ₹ 285 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, 22.2 *प्रतिशत* का एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (25 *प्रतिशत*) एवं ते.वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक (27.8 *प्रतिशत*) से कम था। वर्ष 2011-12 के ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात की (21.8 *प्रतिशत*) तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान यह आंशिक सुधार के साथ बढ़कर 22.2 *प्रतिशत* हो गया।
- वर्ष 2008-09 के (-) ₹ 1171 करोड़ का संसाधन अन्तराल वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 899 करोड़ हो गया जो सरकार के राजकोषीय स्थिति में सुधार का सूचक था। तथापि, भारी गिरावट के साथ यह वर्ष 2011-12 में ₹ 188 करोड़ एवं वर्ष 2012-13 में (-) ₹ 39 करोड़ हो गया।
- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2008-09 के ₹ 583 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 773 करोड़ हो गयी जो वर्ष 2010-11 में घटकर (-) ₹ 737 करोड़ एवं वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 238 करोड़ हो गयी। तथापि, यह वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 1814 करोड़ हो गयी।
- राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान के अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2009-10 के 15 *प्रतिशत* से स्थिरतार्पूवक घटकर वर्ष 2012-13 में 10 *प्रतिशत* हो गयी।
- राज्य-ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा दर्शाती है कि ऋण दायित्व प्रत्येक अवधि खंड के लिए बढ़ रही थी।

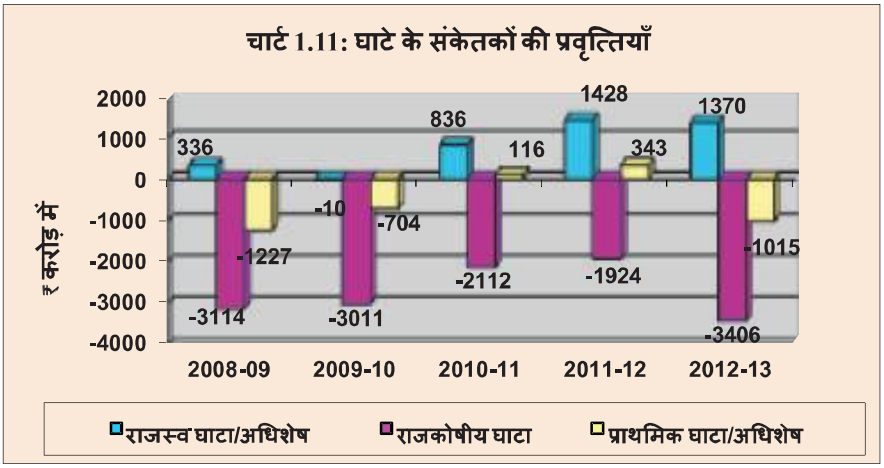
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को बतलाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण व तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

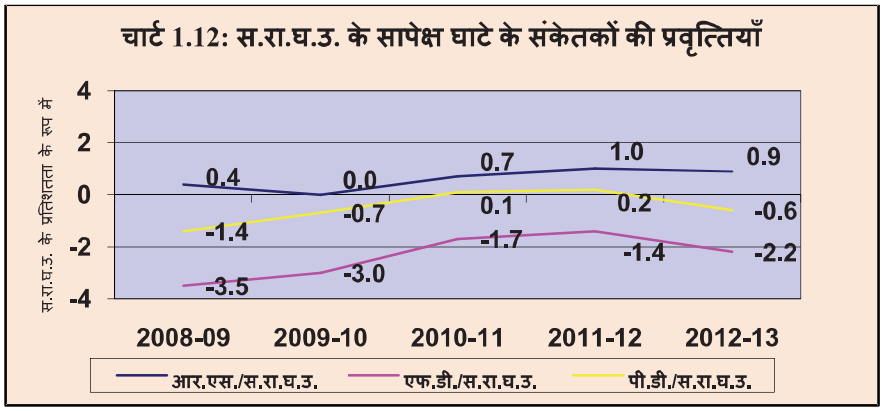
1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12, वर्ष 2008-13 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.11: घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.12: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



- केवल वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटे को छोड़कर, वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। तथापि राजस्व अधिशेष वर्ष 2011-12 में ₹ 1428 करोड़ से आंशिक रूप से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1370 करोड़ हो गया।
- राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं ते.वि.आ. द्वारा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 के अन्त तक पूरा कर लिया था। तथापि, अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 32,426 करोड़) प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व अधिशेष से स.रा.घ.उ. का अनुपात एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये लक्ष्य 3.32 *प्रतिशत* के सापेक्ष 0.87 *प्रतिशत* था।
- राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 में ₹ 3144 करोड़ से क्रमिक रूप से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 1924 करोड़ हो गया, पुन: कम राजस्व प्राप्तियों के कारण वर्ष 2012-13 में यह बढ़कर ₹ 3406 करोड़ हो गया।
- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता में सुधार दर्ज किया गया, क्योंकि यह मार्च 2009 के अंत तक 3.5 *प्रतिशत* से लगातार घटकर मार्च 2012 के अंत तक 1.4 *प्रतिशत* हो गया जो मार्च 2013 के अंत में क्रमिक रूप से बढ़कर 2.2 *प्रतिशत* हो गया। स.रा.घ.उ. से राजस्व घाटा की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के लिए एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये 2.15 *प्रतिशत* के अनुमान के लगभग समतुल्य थी। तथापि, यह ते.वि.आ. के तीन *प्रतिशत* की सिफारिश के भीतर था।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2008-13 के दौरान प्राथमिक घाटा में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2008-09 के ₹ 1227 करोड़ से घटकर वर्ष 2009-10 में ₹ 704 करोड़ हो गया एवं वर्ष 2010-11 में यह ₹ 116 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष और वर्ष 2011-12 में ₹ 343 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया जो पुन: वर्ष 2012-13 में ₹ 1015 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया।
- वर्ष 2012-13 के एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 0.50 *प्रतिशत* के सापेक्ष प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का 0.65 *प्रतिशत* था।

1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली

वित्तीय घाटे के वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा की **तालिका 1.30** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.30: वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		
वित्तीय घाटे का बिखराव		**3114**	**3011**	**2112**	**1924**	**3406**		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	336	(-)10	836	1428	1370		
2	निवल पूँजीगत व्यय	3051	2703	2664	3159	4218		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	399	298	284	193	558		
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रणाली*						**प्राप्तियाँ**	**संवितरण**	**शुद्ध**
1	बाजार उधार	1238	1674	198	785	3600	455	3145
2	भारत सरकार से ऋण	(-)136	(-)133	(-)104	(-)122	239	139	100
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	54	670	957	(-)73	221	421	(-)200
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	418	(-)32	96	442	1139	1169	(-)30
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	200	273	104	70	668	646	22
6	आरक्षित निधि	(-)48	313	(-)223	(-)105	280	403	(-)123
7	जमा एवं अग्रिम	799	273	464	1030	8706	7416	1290
8	उचंत एंव विविध	208	132	(-)27	74	200	169	31
9	प्रेषण	(-)10	(-)39	6	(-)17	4643	4784	(-)141
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)146	0	0	(-)76	शून्य	(-)100	(-)100
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/कमी (-)	(-)537	120	(-)641	117	117	705	588

** ये सभी अंक वर्ष 2012-13 के दौरान सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।*

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 3406 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यत: बाजार उधार (₹ 3145 करोड़) एवं जमा और अग्रिम (₹ 1290 करोड़) से किया गया।

1.11.3 घाटा/अधिशेष के गुण

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) की भरपाई करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की भरपाई उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुन: यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय[14] का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। **तालिका 1.31** में घटकों का विभाजन दिया गया है

[14] राजस्व, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय, लेकिन ब्याज भूगतान पर नही

तालिका 1.31: राज्य में प्राथमिक घाटे / अधिशेष - घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटे (-) /अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटे (-) /अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	13232	10990	3051	418	14459	(+)2242	(-)1227
2009-10	15140	12821	2703	320	15844	(+)2319	(-)704
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य के गैर ऋण- प्राप्तियाँ, प्राथमिक राजस्व व्यय एवं प्राथमिक व्यय में समतुल्य उच्च वृद्धि के सापेक्ष, ₹ 13232 करोड़ से बढ़कर ₹ 24813 करोड़ हो गया । वर्ष 2008-13 के दौरान पूँजीगत व्यय में उतार चढ़ाव आया ।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के गैर ऋण प्राप्तियाँ 11 *प्रतिशत* बढ़ी जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान प्राथमिक व्यय 17 *प्रतिशत* बढ़ा फलस्वरूप वर्ष के दौरान प्राथमिक घाटा रहा ।

1.12 झारखण्ड सरकार का बाजार उधार

1.12.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार द्वारा माँग को प्रस्तुत करता है। उधार के मुख्य प्रभाग केन्द्र सरकार द्वारा ऋण एंव अग्रिम तथा राज्य सरकार के आंतरिक ऋण हैं। आंतरिक ऋण को बाजार ऋण एवं प्राकाम्य ऋण में विभाजित किया जाता है। बाजार उधार केन्द्र द्वारा नियंत्रित एवं भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। केन्द्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार कोई कर्ज नहीं ले सकती यदि वे केन्द्र सरकार से ऋणित है (अनुच्छेद 293)।

राज्य के राजकोषीय घाटे (उधार के बराबर) की उच्चतम सीमा की सिफारिश केन्द्रीय वित्त आयोग (भारत सरकार) द्वारा की जाती है। वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2010-11 के लिए यह सीमा स.रा.घ.उ. का 3.5 *प्रतिशत,* वर्ष 2009-10 के लिए स.रा.घ.उ. का चार *प्रतिशत* तथा वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिए स.रा.घ.उ. का तीन *प्रतिशत* था। उपरोक्त अनुसार, राज्य सरकार ने भी राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में समान सीमा निश्चित की। इस अधिनियम ने उधार का प्रयोग उत्पादक सम्पत्ति के सृजन के लिए किये जाने की अनुशंसा की।

वित्त आयोग (भारत सरकार) वार्षिक योजना को वित्त प्रदान करने एवं उधार की आवश्यकताओं को अनुमोदित करती है। सरकार राज्य बजट में बाजार ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों एवं अदायगी के लिए आकलन भी तैयार करती है। वर्ष 2008-13 के दौरान, राज्य सरकार ने भा.रि.बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि वाले सभी बाजार ऋण को प्राप्त किया।

हमने वित्त विभाग के अभिलेखों की जाँच परीक्षा के माध्यम से मई से जून 2012 के दौरान झारखण्ड सरकार के बाजार उधार की समीक्षा, यह जाँचने के लिये कि क्या बाजार उधार की आवश्यकता का मूल्यांकन दक्षतापूर्वक किया गया है तथा क्या उधार माँगी गई धनराशि उत्पादक सम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रयोग किये गए हैं। 10 सितम्बर 2013 को सचिव, वित्त विभाग के साथ एक एक्जिट कान्फ्रेंस की गई, जहाँ राज्य के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों एवं समग्र ऋण धारणीयता संकेतको पर परिचर्चा हुई।

1.12.2 झारखण्ड में बाजार उधार की स्थिति

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान ली गयी बाजार उधार की राशि एवं वर्ष के अंत तक बकाया राशि को **तालिका 1.32** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.32: बाजार उधार की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	उगाहे गए बाजार ऋण	कुल	पुनर्भुगतित बाजार ऋण	अंत शेष	निवल वृद्धि(+)/ ह्रास(-) (*प्रतिशत*)
2008-09	4735.75	1486.00	6221.75	248.26	5973.49	(+)1237.74 (26.14)
2009-10	5973.49	1843.98	7817.47	170.20	7647.27	(+)1673.78 (28.02)
2010-11	7647.27	500.00	8147.27	302.03	7845.24	(+)197.97 (2.59)
2011-12	7845.24	1254.05	9099.29	468.73	8630.56	(+)785.32 (10.01)
2012-13	8630.56	3600.00	12230.56	454.98	11775.58	(+)3145.02 (27.14)

स्रोत: 2008-13 के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार।

1.12.3 ऋण धारणीयता संकेतक - बाजार ऋण के सापेक्ष कुल दायित्व

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य में कुल दायित्व एवं लोक ऋण के सापेक्ष बाजार उधार की स्थिति **तालिका 1.33** में दी गई है:

तालिका 1.33 : ऋण धारणीयता - कुल दायित्व के सापेक्ष बाजार ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत मे कुल दायित्व	24084.00	27165.00	28655.00	30664.00	34869.00
कुल दायित्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.4	12.8	5.5	7.00	13.7
कुल लोक ऋण (बकाये)	17568.15	19880.00	21131.39	22285.78	25201.58
लोक ऋण का वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.78	13.16	6.29	5.46	13.08

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल बाजार ऋण (बकाये)	5973.49	7647.27	7845.24	8630.56	11775.58
बाजार उधारी की वृद्धि	26.14	28.02	2.59	10.01	36.44
कुन दायित्व के सापेक्ष बाजार ऋण की प्रतिशतता	24.80	28.15	27.37	28.14	33.77
लोक ऋण के सापेक्ष बाजार ऋण की प्रतिशतता	34.00	38.47	37.12	38.72	46.73
बाजार ऋण पर भुगतित ब्याज	384.79	527.84	609.23	618.65	687.76
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात	0.14	0.15	0.12	0.10	0.09
वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार ऋण पर औसत ब्याज दर	7.42	8.27	8.28	8.96	8.79
ब्याज दर से स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर का अनुपात	0.55	1.62	3.13	1.53	1.58
राजस्व अधिक्य /घाटा	(+) 336	(-) 10	(+) 836	(+) 1428	(+) 1370
राजकोषीय घाटा	(-) 3114	(-) 3011	(-) 2112	(-) 1924	(-) 3406
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता	3.5	2.90	1.68	1.37	2.17
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल दायित्व की प्रतिशतता	27.43	27.00	22.77	21.82	22.24
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष लोक ऋण की प्रतिशतता	20.01	19.76	16.79	15.86	16.07
बकाये गारंटी	500.00	500.00	-	-	77.78
स.रा.घ.उ.	87794	100621	125824	140558	156781
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.6	14.6	25	11.7	11.5

स्रोतः 2008-13 के वित्त लेखे एवं प्रतिवेदन, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार।

- स.रा.घ.उ. से कुल दायित्वों का प्रतिशत वर्ष 2008-09 में 27.43 *प्रतिशत* से उल्लेखनीय कमी के साथ वर्ष 2011-12 में 21.82 *प्रतिशत* हो गई और फिर 2012-13 में आंशिक रूप से बढ़कर 22.24 प्रतिशत हो गई । इसी प्रकार स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल लोक ऋण की प्रतिशतता वर्ष 2008-09 के 20.01 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में 16.07 *प्रतिशत* हो गई। इसके अनुपात में ह्रास मुख्यतया पूर्ण अवधि में कुल दायित्व एवं लोक ऋण की तुलना में स.रा.घ.उ. में उच्चतर वृद्धि के कारण हुआ।
- कुल दायित्वों की तुलना में, बाजार ऋण वर्ष 2008-09 के 24.80 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 33.77 *प्रतिशत* हो गई, जबकि बाजार ऋण से कुल लोक ऋण का अनुपात वर्ष 2008-09 के 34.00 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 46.73 *प्रतिशत* हो गई। यह राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के लिए बाजार उधार पर इसके अधिक विश्वास को इंगित करता है।
- स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 1.37 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 2.17 *प्रतिशत* हो गई क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में ह्रास हुआ और वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा में उच्च वृद्धि हुई।

- वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान बाजार उधार का औसत दर 7.42 *प्रतिशत* एवं 8.96 *प्रतिशत* के बीच रहा जो भारत सरकार के प्रतिभूति के ब्याज दर (14 दिनों के कोषागार विपत्र) की तुलना में उच्चतर था।
- ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2008-09 के 0.14 से क्रमिक रूप से घटकर 2012-13 में 0.09 हो गई जो राज्य के ऋण धारणीयता एवं संसाधनों में सुधार को इंगित करता है।

1.12.4 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

वर्ष 2013-23 की अवधि के लिए 31 मार्च 2013 तक लंबित बाजार ऋण परिपक्वता की प्रवृत्ति का वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका 1.34** मे दी गई है:

तालिका 1.34 : बाजार ऋणों की परिपक्वता की प्रवृत्ति

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि (₹ करोड़ में)	बकाया बाजार ऋण के प्रतिशत के रूप में
2013-14	415	3.52
2014-15	462	3.92
2015-16	594	5.04
2016-17	428	3.63
2017-18	1192	10.12
कुल (2013-18)	3091	26.25
2018-19	1486	12.62
2019-20	1844	15.66
2020-21	500	4.25
2021-22	1254	10.65
2022-23	3600	30.57
कुल (2018-23)	8684	73.75
कुल	**11775**	**100.00**

स्रोत : वित्त लेखे 2012-13

उपरोक्त आँकडों से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2013-18 के दौरान बाजार ऋण का विमोचन-दायित्व बकाया बाजार ऋण के सापेक्ष ₹ 3091 करोड़ (26 *प्रतिशत*) होगा। तथापि, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक विमोचन-भार में वृद्धि होगी क्योंकि ₹ 8684 करोड़ (74 *प्रतिशत*) के बकाये बाजार ऋण का भुगतान राज्य द्वारा किया जाना है। हमने आगे पाया कि वर्ष 2008-10 के दौरान नवीन रूप से 10 वर्षीय ऋण लेने के कारण ₹ 523 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान-भार बढ़ गया।

1.12.5 ब्याज दर की रूपरेखा

वर्ष 2008-13 के दौरान लिये गये बाजार ऋण पर ब्याज दर **तालिका 1.35** में दी गई है।

तालिका 1.35: ब्याज दर की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान लिये गये बाजार ऋण					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
5 से कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5-5.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6-6.99	443.55	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	443.55
7-7.99	400.00	517.45	शून्य	शून्य	शून्य	917.45
8-8.99	642.45	1326.53	500.00	500.00	3100.00	6068.98
9-9.99	शून्य	शून्य	शून्य	754.05	500.00	1254.05
10-10.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1486.00	1843.98	500.00	1254.05	3600.00	8684.03
वर्ष के दौरान उगाहे गये बाजार ऋण पर औसत ब्याज दर	7.42	8.27	8.28	8.96	8.79	

स्रोत: वर्ष *2008-13 के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार।*

उपरोक्त आँकड़ों से यह पाया गया कि वर्ष के दौरान लिये गए बाजार ऋण का औसत ब्याज दर वर्ष 2008-09 के 7.42 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 8.96 *प्रतिशत* हो गया एवं वर्ष 2012-13 के दौरान आंशिक रूप से घटकर 8.79 *प्रतिशत* हो गया।

1.12.6 पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार ऋण की उगाही किया गया

तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि अधिक रोकड़ शेष वाले राज्यों को नए उधार का अनुसरण करने से पहले वर्त्तमान रोकड़ शेष का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए तथा उधार का अनुसरण उपलब्धता के आधार के बजाय आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए। आगे, राज्य मासिक/त्रैमासिक रोकड़ की आवश्यकता को केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), नागपुर, भा.रि.बैं. द्वारा भेजे गए दैनिक रोकड़ शेष विवरणी के आधार पर आकलित करता है।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के दौरान औसतन 8.08 *प्रतिशत* की ब्याज दर से पाँच बार कुल ₹ 2343.89 करोड़ का बाजार ऋण उधार लिया। राशि की नितांत आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 31 मार्च को छोड़कर सम्पूर्ण राशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक '14 दिनों का कोषागार विपत्र' के अंश के रूप में पड़ा रहा। हमलोगों ने अवलोकन किया कि राज्य के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष ₹ 0.45 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2009-10 एवं

वर्ष 2010-11 की पूरी अवधि में न्यूनतम रोकड़ शेष (कोषागार विपत्र में निवेश) क्रमश: ₹ 696.54 करोड़ एवं ₹ 779.29 करोड़ था। इस प्रकार पर्याप्त रोकड़ शेष रहने के बावजूद भी सरकार ने वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में क्रमश: ₹ 1843.98 करोड़[15] एवं ₹ 500 करोड[16] के बाजार ऋण की उगाही की।

सचिव, (वित्त विभाग) वि.वि. ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उन वर्षों में रोकड़ की कमी के कारण बाजार उधार की आवश्यकता पड़ी। आगे, आहरण सम्पूर्ण त्रैमासिक या माह के लिए था जिसमें आहरित किया गया था, न कि उस दिन के लिये था जिस दिन आहरित किया गया। बाजार उधार का सहारा दैनिक आवश्यकता के आधार पर प्रतिदिन नहीं किया जा सकता है। जवाब सुसंगत नहीं था क्योंकि सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय रोकड़ की वास्तविक आवश्यकता से अत्यधिक ऋण लिया एवं वर्ष 2010-11 के दौरान ऋण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।

आगे, हमलोगों ने अवलोकन किया कि सरकार ने पाँच *प्रतिशत* की वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया जबकि 8.08 *प्रतिशत* की उच्चतर ब्याज दर से बाजार ऋण लिया। फलस्वरूप, उस अवधि के लिए सरकार को 3.08 *प्रतिशत* अतिरिक्त ब्याज की दर से ₹ 51.22 करोड़ के ब्याज के दायित्व का निर्वहन करना पड़ा। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में दिया गया है।

1.12.7 बाजार उधार के लिए अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों से मुक्त बाजार उधार के लिए सांकेतिक कैलेंडर अपनाने की वकालत की थी (जून 2006) जिससे किसी वित्तीय वर्ष के आगामी तिमाही में राज्यों द्वारा मुक्त बाजार उधार की संभावित राशि एवं समय को पूर्व में ही जाना जा सके। झा.स. द्वारा इस पर सहमति (अगस्त 2006) दी गई। संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2008-13 के दौरान, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, झारखण्ड सरकार ने राज्य के रोकड़ आवश्यकता के आधार पर मुक्त बाजार उधार के लिए अग्रिम सांकेतिक कैलेण्डर नहीं तैयार किया। वर्ष 2012-।3 में भी वास्तविक बाजार उधार प्रस्तावित अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर से भिन्न था। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.8*** में दिया गया है।

1.12.8 भा.स. द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक का उधार

संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋण की उगाही से पहले भा.स. का अनुमोदन आवश्यक है। उधार का उपयोग ऋण के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए अर्थात भा.स. द्वारा पूर्व में अनुमोदित वार्षिक योजना अंतराल को समर्थन प्रदान करना चाहिए।

---

[15] 17.04.2009: ₹ 517 करोड़, 05.08.2009: ₹ 474 करोड़, 09.09.2009: ₹ 600 करोड़, एवं 30.10.2009: ₹ 252 करोड़

[16] 12.05.2010: ₹ 500 करोड़

संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि भा.स. ने वर्ष 2008-09 के दौरान झा.स. को निधि प्राप्त करने हेतु पाँच चरणों में मुक्त बाजार से ₹ 1273 करोड़ उधार लेने की अनुमति प्रदान की थी। तथापि, अधिसूचना जारी कर राज्य द्वारा ₹ 1486 करोड़ (दिसम्बर 2008 से मार्च 2009 तक) के बाजार ऋण की उगाही की गई। हमलोगों ने अवलोकन किया कि ₹ 322 करोड़ के ऋण उगाही हेतु भा.स. के अनुमति (10 फरवरी 2009) के आधार पर झा.स. ने भा.रि.बैं. को ऋण की उगाही के लिए कहा (27 फरवरी 2009)। तथापि, झारखण्ड सरकार ₹ 538.53 करोड़ के ऋण उगाहने के भा.रि.बैं. की इच्छा (02 मार्च 2009) पर सहमत हुआ (04 मार्च 2009)। भा.रि.बैं. ने 12 मार्च 2009 को ₹ 535 करोड़ के ऋण की उगाही की। इस प्रकार, राज्य ने ₹ 213 करोड़ का अधिक बाजार ऋण प्राप्त किया जिस पर अनुच्छेद 293 (3) के अन्तर्गत भा.स. की सहमति नहीं थी।

जवाब में सचिव, वि.वि. ने कहा (अक्टूबर 2013) कि बाजार उधार की आवश्यकता वर्ष 2008-09 में रोकड़ की कमी के कारण पड़ी। जवाब सुसंगत नहीं था क्योंकि 1 फरवरी से 11 मार्च 2009 तक न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2030 करोड़ था (राशि 12 मार्च 2009 को आहरित की गई)। इसके अतिरिक्त, 12 मार्च से 31 मार्च 2009 तक राज्य का न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 974.58 करोड़ था जो विनिर्दिष्ट किया कि भा.स. द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक उगाही गई बाजार ऋण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि, मूल रूप से संस्वीकृत राशि ₹ 322 करोड़ के आहरण की भी आवश्यकता नहीं थी।

1.12.9 बाजार उधार की उपयोगिता की निगरानी प्रणाली

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2007 उत्पादक परिसम्पतियों के सृजन के लिए उधार के उपयोग को विहित किया। सरकार ने ऋणों के प्रत्येक वितांश के उद्देश्य वार्षिक योजना को समर्थन प्रदान करने के रूप में अधिसूचित किया। हमलोगों ने अवलोकन किया कि वि.वि. द्वारा उगाहे गए बाजार ऋणों की उपयोगिता के अनुवीक्षण के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं किया गया था। फलस्वरूप, अभीष्ट उद्देश्य के लिए बाजार ऋण की उपयोगिता/अनुप्रयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2008-13 में पूरी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय (संवितरित ऋणों सहित) की राशि निवल उधार की राशि से अधिक थी। पूँजीगत व्यय का विस्तृत चर्चा उपरोक्त कंडिका 1.6.1.1 में पहले ही किया जा चुका है।

जवाब में, सचिव, वि.वि. ने कहा कि पूँजीगत व्यय बाजार उधार एवं जरूरत के आनुपातिक था। बाजार ऋण की उपयोगिता राज्य के पूँजीगत व्यय से सुनिश्चित किया जा सकता है जो बाजार ऋणों के तुलना में अधिक था।

वि.वि. का जवाब झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं था क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया

जा सका कि क्या उत्पादक परिसम्पत्तियाँ सृजित की गई एवं किन विकासात्मक योजनाओं का वित्तीयन बाजार ऋणों से किया गया।

1.13 अनुपालन

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009-10 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.3.5 (पिछले वर्ष से संबंधित आधिक्य प्रावधान) पर चर्चा वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में की थी। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.3 (बिना प्रावधान का व्यय), कंडिका 2.4.4 (पिछले वर्षों से संबंधित आधिक्य प्रावधान), कंडिका 2.4.5 (वर्ष 2010-11 के दौरान आधिक्य प्रावधान), कंडिका 2.4.9 (वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण) एवं कंडिका 2.5.2 (असमाशोधित व्यय) की चर्चा अक्टूबर 2012 में की गयी थी।

1.14 निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2012-13 के दौरान स.रा.घ.उ. की वृद्धि उस वर्ष के ते.वि.आ. की अनुशंसा 14.5 *प्रतिशत* के विरुद्ध 11.5 *प्रतिशत* था।
- राज्य के पास वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1370 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। वर्त्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 3406 करोड़ बढ़ा। यह स.रा.घ.उ. का 2.2 *प्रतिशत* था, जो ते.वि.आ. द्वारा की गई अनुशंसा (तीन *प्रतिशत*) की सीमा के भीतर था।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अंतरण

- राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से परे भा.स. से निधियों का सीधा अंतरण के कारण, वार्षिक लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराती है।

राजकोषीय असंतुलन एवं संसाधनों के संचालन का प्रबंधन

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 24,770 करोड़) वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 10.5 *प्रतिशत* बढ़ी, वहीं यह बजट आकलन से कम (₹ 7656 करोड़ से) था।

पूँजीगत व्यय

- पूँजीगत व्यय (पूं.व्य.) वर्ष 2011-12 में ₹ 3159 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 4218 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में पूँ.व्य. में कमी आई। राज्य सरकार ने अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को कम प्राथमिकता दिया है।

सरकारी निवेशों की समीक्षा

- वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी कम्पनियों, सहकारियों, बैंकों एवं समितियों इत्यादि में निवेश पर लाभांश कुल निवेश का 7.99 *प्रतिशत* रहा जो उधार ली गई राशि से कम (8.76 *प्रतिशत*) था।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹34.869 करोड़) पिछले वर्ष से 14 *प्रतिशत* बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 22.2 *प्रतिशत* था जो ते.वि.आ. की अनुशंसा 28.7 *प्रतिशत* से बेहतर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए मर्जित निधि (सिंकिंग फण्ड) का गठन नहीं किया है।

बाजार उधार

- कुल दायित्वों में बाजार ऋण की हिस्सेदारी वर्ष 2008-09 के 24.80 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 33.77 *प्रतिशत* हो गई। पर्याप्त रोकड़ रहने के बावजूद, राज्य सरकार ने रोकड़ की नितांत आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना ऋण की उगाही की। सरकार के पास विकासात्मक क्रियाकलाप के सृजन हेतु उधार ली गई राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं है।

1.15 अनुशंसाएँ

- सरकार मध्यकालीन राजकोषीय योजना में परियोजित अपने राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
- राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशियों के अनुप्रयोग के उचित लेखांकन एवं अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
- बेहतर लाभांश पाने के लिए सरकार को उच्च लागत वाली उधार ली गई निधियों को विवेकपूर्वक निवेश करना चाहिए।
- सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए मर्जित निधि का गठन करना चाहिए।
- मुक्त बाजार उधार उपलब्धता के बजाय आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। अधिशेष रोकड़ की उपयोगिता के बाद बाजार ऋण की उगाही की जानी चाहिए एवं उधार लिए गए निधियों का विकासात्मक क्रियाकलाप के सृजन में उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का विकास किया जाय।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारित व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उदेश्यों लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशियों के साथ तुलना की जाती है। यह लेखे, वास्तविक बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और बजट के भारित और दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत व्यय के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। अत: विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को आसान बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 विनियोगों की लेखा परीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्दर है और जब कभी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 52 के अनुसार, राज्य के बजट प्राक्कलन को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाना हैं। इस नियमावली के नियम 78 के अनुसार प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा तैयार प्राक्कलन की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण उपस्थापन हेतु संकलित की जाती है। व्यय के नियंत्रण हेतु नियम बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) में समाहित हैं। राज्य के बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार समस्त अनुमानित बचतों को सरकार को तुरन्त अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के अधिकाई व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित अधिकाई हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित अधिकाई को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए। वर्ष 2012-13 के दौरान अनेक अनुदानों में विशाल बचत एवं आधिक्यों को

देखा गया जो बजट प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2012-2013 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 2.1** में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2012-13 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय*	बचत(-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	25310.32	1074.89	26385.21	20965.76	(-)5419.45
	II पूँजीगत	6856.83	149.20	7006.03	4245.12	(-)2760.91
	III ऋण एवं अग्रिम	829.37	141.00	970.37	700.81	(-)269.56
कुल दत्तमत		**32996.52**	**1365.09**	**34361.61**	**25911.69**	**(-)8449.92**
भारित	IV राजस्व	2490.23	15.15	2505.38	2437.34	(-)68.04
	V पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI लोकऋण पुनर्भुगतान	1627.05	0.00	1627.05	2183.06	(+)556.01
कुल भारित		**4117.28**	**15.15**	**4132.43**	**4620.40**	**(+)487.97**
सकल योग		**37113.80**	**1380.24**	**38494.04**	**30532.09**	**(-)7961.95**

(स्त्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2012-13)

*व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 26.70 करोड़) तथा पूँजीगत दत्तमत व्यय (₹ 3.23 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।

नोट- वर्ष 2012-13 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 584 करोड़ का व्यय अधिवर्णित था जिनके विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 30 जून 2013 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल मिलाकर ₹ 7961.95 करोड़ का बचत तीन अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 9225.13 करोड़ के बचत (राजस्व संभाग के अन्तर्गत 53 अनुदानों एवं चार विनियोगों में कुल ₹ 6191.00 करोड़ एवं पूँजीगत संभाग के अधीन 22 अनुदानों में ₹ 3034.13 करोड़) तथा ₹ 1263.18 करोड़ आधिक्य के प्रतितुलन का परिणाम था। ₹ 1380.24 करोड़ का अनुपूरक उपबंध प्राप्त किया गया जबकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से कम (18 *प्रतिशत*) था।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा मासिक सिविल लेखा एवं विनियोग लेखा के माध्यम से शीर्षवार व्यय की स्थिति माहवार राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, विशाल बचत एवं अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकारी विभागों द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। झारखण्ड सरकार के

विनियोग लेखे 2012-13 में वर्णित कुल 1260 उप-शीर्षों में से 796 उप-शीर्षों में बचत का कारण एवं 195 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

2.4.1 आबंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से स्पष्ट हुआ कि 38 मामलों (30 अनुदानों) में कुल ₹ 7969.92 करोड़, प्रत्येक मामला में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* या उससे अधिक की बचत हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में दर्शाया गया है। ₹ 9225.13 करोड़ की कुल बचत में, 20 अनुदानों से संबंधित 22 मामलों में ₹ 7866.77 (85 *प्रतिशत*)[1] की बचत हुई जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व दत्तमत						
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	604.29	106.44	710.73	446.48	264.25
2	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	890.65	210.45	1101.01	793.20	307.90
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1105.87	19.66	1125.53	799.40	326.13
4	22-गृह विभाग	2487.24	19.82	2507.06	2374.90	132.16
5	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	860.53	52.62	913.15	680.72	232.43
6	35-योजना एवं विकास विभाग	679.05	0.19	679.24	84.86	594.38
7	39-आपदा प्रबंधन विभाग	444.29	0.07	444.36	285.29	159.07
8	42-ग्रामीण विकास विभाग	770.96	61.88	832.84	515.52	317.32
9	47-परिवहन विभाग	449.92	0.07	449.99	333.44	116.55
10	48-नगर विकास विभाग	575.15	6.75	581.90	404.81	177.09
11	51-कल्याण विभाग	765.94	50.55	816.49	566.23	250.26
12	56-पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	1505.89	4.21	1510.10	1248.05	262.05
13	58-माध्यमिक शिक्षा	702.94	22.54	725.48	487.10	238.38
14	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	4592.65	63.39	4656.04	3162.76	1493.28
15	60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	1112.28	2.01	1114.29	812.22	302.07

[1] प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
पूँजीगत-दत्तमत						
16	3-भवन निर्माण विभाग	181.08	0.00	181.08	66.11	114.97
17	10-ऊर्जा विभाग	653.00	141.00	794.00	541.70	252.30
18	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	352.55	54.80	407.35	146.84	260.51
19	41-पथ निर्माण विभाग	1639.45	34.00	1673.45	1498.90	174.55
20	48-नगर विकास विभाग	689.92	0.00	689.92	198.93	490.99
21	49-जल संसाधन विभाग	1632.71	23.00	1655.71	422.86	1232.85
22	50-लघु सिचाई विभाग	356.09	6.01	362.19	194.91	167.28
कुल		**23052.45**	**879.55**	**23932.00**	**16065.23**	**7866.77**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

आगे, उपरोक्त अनुदानों के अंतर्गत 68 उप-शीर्षों/योजनाओं में कुल ₹ 5386.36 करोड़ (कुल बचत का 58 *प्रतिशत*) की बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ एवं उससे अधिक) हुई। विनियोग लेखे 2012-13 में प्रदर्शित बचत के कारण सहित बचत के ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

विशाल बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

2.4.2 सतत बचत

16 मामलों में (15 विभागों) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामलों में कुल अनुदान का 10 *प्रतिशत* या उससे अधिक की सतत बचत थी **(तालिका 2.3)**।

तालिका 2.3 : वर्ष 2008-13 के दौरान सतत बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	राजस्व -दत्तमत					
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	499.65(70)	178.10(44)	181.21(39)	228.82(35)	264.25(37)
2	2-पशुपालन विभाग	58.61(29)	54.21(27)	46.11(22)	31.52(23)	35.50(22)
3	17-वित्त (व्यावसायिक कर) विभाग	6.11(20)	3.79(11)	8.27(17)	11.24(18)	27.17 (38)
4	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	34.17(18)	98.68(28)	84.27(13)	168.00(15)	307.90(28)
5	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	40.34(16)	61.60(23)	68.35(23)	52.20(19)	48.17(15)
6	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	184.31(23)	480.56(45)	178.41(21)	277.93(25)	326.13(53)
7	23-उद्योग विभाग	83.42(42)	73.27(32)	31.89(18)	157.41(45)	82.94(29)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	राजस्व -दत्तमत					
8	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	187.81(25)	162.39(23)	148.44(19)	193.07(23)	232.43(25)
9	35-योजना एवं विकास विभाग	129.49(87)	72.02(82)	14.00(46)	291.78(58)	594.38(88)
10	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	32.11(13)	47.00(17)	27.94(11)	79.15 (24)	77.17(23)
11	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	76.74(50)	66.06(59)	51.83(41)	40.29(42)	37.03(40)
12	49-जल संसाधन विभाग	17.52(09)	57.85(22)	30.98(13)	83.77(27)	92.55(29)
13	51-कल्याण विभाग	219.46(23)	304.76(28)	208.83(16)	309.14(33)	250.26(31)
	पूँजीगत-दत्तमत					
14	10- ऊर्जा विभाग	68.92 (17)	383.67 (61)	132.56 (32)	1130.05 (87)	252.30 (32)
15	41-पथ निर्माण विभाग	88.05(14)	230.19(31)	146.70(18)	899.94(53)	174.55(10)
16	49- जल संसाधन विभाग	254.29(48)	277.49(56)	153.71(40)	714.70(78)	1232.85(74)

स्रोत: विनियोग लेखे

(कोष्ठक के आँकड़े कुल अनुदान के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विशाल बचत वर्षों से जारी रही जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती है। आगे, उपरोक्त तालिका में वर्णित पाँच विभाग जो आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं से संबद्ध है के कुछ मुख्य स्कीमों में बचत के ब्यौरों की चर्चा नीचे की गई है:

अनुदान सं. 1-कृषि एवं गन्ना विभाग

राज्य में कृषि के विकास के लिए चलाये गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम एवं ग्रामीण बीज कार्यक्रम में विशाल बचत हुई जो नीचे तालिका में दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-109-28 (योजना)	4.14	4.14 (100)	6.90	4.82 (70)	4.52	1.28 (28)
राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-796-28 (योजना)	0.00	0.00	8.10	1.60 (20)	6.01	1.53 (26)
राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-109-28 (सी.एस.एस)	23.46	22.06 (94)	39.10	39.10 (100)	20.63	20.63 (100)
राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-796-28 (सी.एस.एस.)	27.54	27.29 (99)	45.90	45.90 (100)	27.54	27.54 (100)
ग्रामीण बीज कार्यक्रम 2401-00-796-49 (सी.पी.एस.)	11.00	5.38 (49)	2.97	2.93 (99)	7.70	6.55 (85)
ग्रामीण बीज कार्यक्रम 2401-00-800-49 (योजना)	9.00	4.68 (52)	2.53	2.34 (93)	7.15	5.90 (82)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)

स्रोत: वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।

अंतिम तीन वर्षों के 18 में से 16 मामलों में, बचत के कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया। तथापि, वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा निधियों के विमोचन नहीं किए जाने के कारण शीर्ष 2401-00-796-28-राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अधीन बचत हुई।

अनुदान सं. 10- ऊर्जा विभाग

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की साख तथा झा.रा.वि.बो. को उत्पादन के लिए दिए गए ऋण में महत्वपूर्ण बचत हुई। ब्यौरे नीचे की तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2801-01-789-02 (योजना)	13.35	7.29 (55)	9.90	9.90 (100)	6.00	4.85 (81)
राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2801-01-796-02 (योजना)	43.47	23.73 (55)	38.50	38.50 (100)	13.00	10.51 (81)
राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2801-01-800-02 (योजना)	51.18	27.95 (55)	61.60	61.60 (100)	31.00	25.08 (81)
पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-789-01 (सी.एस.एस.)	4.20	4.20 (100)	5.85	2.50 (43)	18.60	15.26 (82)
पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-796-01 (योजना)	13.68	13.68 (100)	22.75	9.70 (43)	40.30	33.06 (82)
पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-800-01 (सी.एस.एस.)	16.11	16.11 (100)	36.40	15.54 (43)	96.10	78.83 (82)
उत्पादन के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-800-05 (योजना)	90.00	40.00 (44)	150.00	150.00 (100)	108.00	108.00 (100)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)

स्रोत: वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के *विनियोग लेखे।*

छः मामलों (21 मामलों में से) में, बचत के कारण नहीं बताए गए। तथापि, शीर्ष '6801-00-800-05- उत्पादन हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण' के अंतर्गत वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान बचत का कारण क्रमशः झा.रा.वि.बो. से प्रस्तावों की अप्राप्ति एवं स्वर्णरेखा पनबिजली परियोजना के निरीक्षण रिपोर्ट की अप्राप्ति बताई गई।

अनुदान सं. 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य उप-केंद्र योजना में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसे नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
स्वास्थ्य उप-केन्द्र 2211-00-101-01-(सी पी एस)	149.98	102.26 (68)	170.80	125.56 (74)	193.64	141.55 (73)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)

स्रोत: वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।

उपरोक्त मामलों में बचत के कारण भारत सरकार द्वारा कमतर निधियों के अनुमोदन के रूप में सूचित किये गये।

अनुदान सं. 49- जल संसाधन विभाग

स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत) में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण बचत पायी गयी। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13	
	बजट	बचत	बजट	बचत
स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 4700-80-789-09	30.00	7.81 (26)	48.78	26.07 (53)
स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 4700-80-796-09	30.00	16.35 (54)	70.00	19.06 (27)
स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 4700-80-796-10	300.00	241.07 (80)	600.00	424.95 (71)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)

स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।

उपरोक्त बचतों के लिए कोई कारण नहीं बताए गए।

अनुदान सं. 51- कल्याण विभाग

आदिम जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम एवं सूक्ष्म-आर्थिक सामाजिक संगठन (मेसो) परियोजना के प्रशासन में महत्वपूर्ण बचत हुई। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
2225-02-796-04-आदिम जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम (सी.पी.एस.)	59.76	49.92 (84)	71.32	71.32 (100)	71.32	64.42 (90)
2225-02-796-17-मेसो कार्यक्रम का प्रशासन	7.50	3.17 (42)	7.50	2.33 (31)	14.11	12.17 (86)

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)

स्रोत: वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।

2010-11 एवं 2012-13 के दौरान जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई बचतों के लिये कारण भारत सरकार द्वारा निधियों के अविमोचन बताये गये। मेसो परियोजना के अंतर्गत क्रमश: 2010-11 एवं 2012-13 के लिए बचत के कारण अतिरिक्त निधि का प्रावधान एवं गलत उप-शीर्ष में विनियमन को बताया गया। उपरोक्त शीर्षों में 2011-12 के दौरान बचतों के लिये कोई कारण नहीं दिए गए।

2.4.3 आकस्मिक निधि से अग्रिम

राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम 2001 की धारा-4 के अधीन की गई है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जिनका निरस्तीकरण विधान मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने तक अनैच्छिक होगा, को पूरा करने हेतु ही दिया जायेगा। संगत अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि आकस्मिक निधि से अग्रिमों का आहरण उन व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के। राज्य में इस निधि की धनराशि ₹ 150 करोड़ है। 33 मौकों पर ₹ 231.21 करोड़ वर्ष 2012-13 के दौरान आहरित किए गए। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान इस निधि से आहरित कुल राशि की क्षतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान की गई। कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)
1	2052-00-090-24	मुख्यमंत्री के लिए कार की खरीद	26.50
2	2052-00-090-25	यात्रा छुट्टी रियायत	12.00
3	2013-00-105-02	मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान	18.00
3	2013-00-101-01	कार की खरीद	5.77
4	2049-01-200-02	नाबार्ड से प्राप्त ऋणों के ब्याज का भुगतान	1400.00
5	2203-00-001-01	कार की खरीद	7.69
6	2801-80-101-12	झा.रा.वि..बो. को सहायता अनुदान	10000.00
कुल			11469.96

उपरोक्त वर्णित व्यय आकस्मिक निधि से आहरण के मापदण्डों को पूरा नहीं करता क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित हैं और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के हैं। अतएव, ये व्यय राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए थे।

2.4.4 वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य का राज्य विधायिका द्वारा नियमित करवाना अनिवार्य है।

तालिका 2.5 में वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा राज्य के संचित निधि से अनुमोदन के विरुद्ध एक विनियोग एवं दो अनुदानों में कुल ₹ 1263.18 करोड़ के आधिक्य का सारांश अन्तर्विष्ट है जिसे संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 2.5 : वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग के नाम व संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित	**विनियोग**			
1	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	1627.05	2183.06	556.01
दत्तमत अनुदान				
1	7-सतर्कता	11.48	11.55	0.07
2	15-पेंशन	2227.75	2931.19	703.44
3	42-ग्रामीण विकास विभाग	478.42	482.08	3.66
	कुल	**4344.70**	**5607.88**	**1263.18**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखे

उपरोक्त अनुदानों में कुल ₹ 1263.18 करोड़ का अधिक्य अनुदान के विभिन्न उपशीर्षो के अन्तर्गत या तो बिना बजट के या बजट से अधिक्य के कारण हुआ।

2.4.5 विगत वर्षो से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2011-12 तक प्रावधान से अधिक की गई व्यय ₹ 8540.79 करोड़ की राशि को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार नियमित किया जाना अभी भी शेष है जिसे ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। अनुदानों/विनियोगों हेतु नियमित की जाने वाली लंबित वर्ष-वार आधिक्य व्यय की राशि का सारांश **तालिका 2.6** में दिया गया है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का नियमित नहीं होना विनियोगों पर वित्त-विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

तालिका 2.6: विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	3, 25, 32		0.04
2002-03	10, 32	13,14	1241.49
2003-04	10, 39, 46	13,14	937.25
2004-05	23, 39, 40	13,14	576.07
2005-06	10, 29	13	3121.47
2006-07	38	13,14	1245.87
2007-08	15	14	334.44
2008-09	12	14	228.89
2009-10		14	116.71
2010-11		13, 15, 32	318.40
2011-12	15, 25	14	420.16
कुल			**8540.79**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

2.4.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 47 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) प्राप्त कुल ₹ 1082.11 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल आबंटन समाप्त नहीं हुए और इन उपशीर्षो के अन्तर्गत विशाल बचत हुई।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, से दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आावश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोजन है। वर्ष 2012-13 के दौरान 18 उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है, अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। आठ योजनाओं/उपशीर्षों में ₹ 22.94 करोड़ की बचत के बावजूद उक्त योजनाओं/ उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.30 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गयी जबकि छः योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 1.47 करोड़ की राशि अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई जिसके फलस्वरूप उन योजनाओं में ₹ 2.29 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। यह भी पाया गया कि ₹ 16.92 करोड़ की राशि चार योजनाओं/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजित की जो उन योजनाओं में ₹ 1.50 करोड़ के आधिक्य व्यय को देखते हुए अपर्याप्त साबित हुए।

2.4.8 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी बचत प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगो या उसके किसी भाग का अभ्यर्पण वित्त विभाग को किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9225.13 करोड़ के कुल बचत में से 27 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत कुल ₹ 7581.47 करोड़ के महत्वपूर्ण बचत (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ और अधिक) हुए। इनमें से कुल ₹ 1496.77 करोड़ (कुल बचत का 20 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं किये गये, जिसके ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.6*** में दिये गये है।

इसके अलावा, 123 मामलों, जहाँ अभ्यर्पण की राशि प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक थी, ₹ 4479.51 करोड़ की राशि मार्च 2013 के अंतिम दो कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई (***परिशिष्ट 2.7***), जिससे अन्य विकास परक उद्देश्यों में इन निधियों के उपयोग का कोई अवसर नहीं मिला। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.5 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की जल्दबाजी से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिये कि, बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का रख-रखाव किया जाता है, व्यय का समरूप प्रवाह आवश्यक है। तथापि, ***परिशिष्ट 2.8*** में सूचीबद्ध 18 लेखा शीर्षों में वर्ष 2012-13 के अंतिम तिमाही एवं अन्तिम महीने में किया गया व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था।

यह देखा गया कि मुख्य शीर्षों '2810- उर्जा का अपरंपरागत स्रोत' 'नये एवं नवीकरणीय उर्जा' के लिए और '3075- परिवहन' 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजनाओं' के अधीन 'लाभांश राहत एवं अन्य आकस्मिक व्यय के तहत रेलवे को सब्सिडी' हेतु सम्पूर्ण निधियों का व्यय मार्च 2013 के महीने में किया गया।

2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

यद्यपि महालेखाकर (लेखा एवं हक.) की बही से नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से बतलाया गया, तथापि वर्ष 2012-13 के दौरान विसंगतियाँ सतत रूप से जारी रहीं। यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 30011.67 करोड़ के कुल प्राप्तियों हेतु 73 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कुल ₹ 14641.32 करोड़ (48.78 *प्रतिशत*) का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 30502.17 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 23400.20 करोड़ (76.71 *प्रतिशत*) के व्यय का समाशोधन 73 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (ले. एवं ह.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं

किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल ₹ 17051.81 करोड़, प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक का असमाशोधित व्यय, ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

महालेखाकार (ले. एवं ह.) के बही से विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन के कारण, प्राप्तियों एवं व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है।

2.7 अनुदान सं.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान सं.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा की गयी। इस अनुदान में छः[2] राजस्व मुख्य लेखा शीर्ष एवं एक[3] पूँजीगत मुख्य लेखा शीर्ष हैं। महत्वपूर्ण अवलोकनों का सारांश निम्नानुसार है:

➢ बजटीय प्रकिया का अनुसरण न होना

वित्त विभाग (वि.वि.) के निर्देशानुसार (18 नवम्बर 2011) कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट आकलन (ब.आ.) एवं बजटीय लेन-देन के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) की एक प्रति वित्त विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2011 तक प्रेषित किया जाना है। हम लोगों ने अवलोकन किया कि योजना व्यय का ब.आ. एवं सी.ओ.बी.टी. दिनांक 4 फरवरी 2012 को वित्त विभाग को सौंपा गया। इस प्रकार, विभाग ने उपस्थापन सारणी का अनुसरण नहीं किया।

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर निदेशालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित सूचनाओं की प्राप्ति एवं आकलन तैयार करने के आधार के विषय में कोई सूचना जमा नहीं किया। आगे, जिला कृषि कार्यालय (जि.कृ.का.) राँची के अभिलेखों की जाँच परीक्षा के दौरान हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2012-13 के लिए विभाग द्वारा योजना बजट आकलन तैयार नहीं किया गया। जि.कृ.का. ने बताया (19 जुलाई 2013) कि उनसे योजना बजट आकलन नहीं माँगा गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निदेशालय द्वारा तैयार किये गये योजना बजट आकलन में सभी क्षेत्रीय इकाइयों के इनपुट शामिल नहीं किये गये।

➢ बढ़ाया हुआ बजट प्रावधान

हमलोगों नें अवलोकन किया कि वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 718.73 करोड़[4] के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 454.48 करोड़[5] (63 *प्रतिशत*) का व्यय विभाग द्वारा किया गया। ₹ 264.25 करोड़[6] के कुल बचत में से ₹ 19.95 करोड़ व्यपगत् हो गया एवं ₹ 249.76 करोड़ अभ्यर्पित की गयी।

---

[2] प्रमुख शीर्ष 2401, 2402, 2415, 2435, 3451 एवं 3475

[3] प्रमुख शीर्ष 4401

[4] राजस्व : ₹ 710.73 करोड़, पूँजी: ₹ 8.00 करोड़

[5] राजस्व : ₹ 446.48 करोड़, पूँजी: ₹ 8.00 करोड़

[6] (-) ₹ 5.46 करोड़ के अधिक व्यय सहित

हमलोगों ने यह भी अवलोकन किया कि विभाग के पास वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान क्रमश: ₹ 180.61 करोड़, ₹ 182.41 करोड़ एवं ₹ 229.82 करोड़ का सतत बचत था।

इस विषय में पूछे जाने (अगस्त 2013) पर, विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2013) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 446.47 करोड़ के पुनरीक्षित परिव्यय के सापेक्ष ₹ 349.65 करोड़ का योजना व्यय प्रतिवेदित की गई जबकि दिया गया जवाब वास्तविक व्यय और आकलन के बीच वृहत् अंतर को इंगित किया, गैर-योजना व्यय आकलनों के विषय में विभाग ने कुछ नहीं बताया।

➢ परिहार्य/अनियमित बजट प्रावधान

- विनियोग लेखे 2012-13 के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 20 उप-शीर्षों (कुल 124 में से) के अन्तर्गत कुल ₹ 100 करोड़ के सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा (***परिशिष्ट 2.10***) एवं सभी को अभ्यर्पित कर दिया गया। केन्द्रीय योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विस्तार सुधार, एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए राशियाँ भा.स. द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को आर.टी.जी.एस. (इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निधि अंतरण की एक प्रणाली) के माध्यम से अंतरित की जाती है। हमलोगों ने यह अवलोकन किया कि वर्ष 2012-13 के दौरान इन तीन योजनाओं के लिए ₹ 76.68 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया जैसे कि नीचे दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

योजना	प्रमुख शीर्ष / लघु शीर्ष	बजट प्रावधान
राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	2401- कृषि- पशुपालन /00/109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण / 28-राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	20.63
	2401- कृषि- पशुपालन /00/796-जनजाति क्षेत्र- उपयोजना / 28-राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	27.54
एक्सटेंशन सुधार	2401- कृषि- पशुपालन /00/796- जनजाति क्षेत्र- उपयोजना / 19-विस्तार सुधार	22.50
सूक्ष्म सिंचाई योजना	2401- कृषि- पशुपालन /00/109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण /29-सूक्ष्म सिंचाई योजना	2.61
	2401- कृषि- पशुपालन /00/796- जनजाति क्षेत्र- उपयोजना /29- सूक्ष्म सिंचाई योजना	3.40
	कुल	**76.68**

चूंकि, तत्पश्चात भा.स. द्वारा राशि राज्य के तीन[7] कार्यान्वयन अभिकरणों को बाद में उपलब्ध करायी गयी, परिणामस्वरूप राज्य बजट में उपलब्ध

[7] 1. निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची, 2. निदेशक राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान राँची और 3. क्षेत्रीय नोडल अधिकारी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन ,राँची

करायी गयी राशि पूरे साल अप्रयुक्त रही जिससे ₹ 76.68 करोड़ का बचत हुआ। सम्पूर्ण बचत राशि 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित कर दी गयी।

- जि.कृ.का. राँची के अभिलेखों के जाँच परीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि प्रमाणित धान के बीज की खरीद दर (पिछले वर्ष से) में पुनरीक्षण के कारण अंतर राशि की क्षतिपूर्ति हेतु जि.कृ.का, राँची को वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 61.68 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी। हमलोगों ने अवलोकन किया कि सम्पूर्ण राशि 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित कर दी गयी। जि.कृ.का. ने कहा कि पिछले वर्ष 2011-12 में प्रमाणित धान के बीज के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गई ₹ 448.62 लाख में से मात्र ₹ 197.78 लाख ही व्यय किया गया। इस तरह वर्ष 2012-13 के लिए कोई माँग नहीं की गई।

➢ परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 15 उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9.70 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान किया गया यद्यपि, इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 36.27 करोड़ का बचत हुआ (***परिशिष्ट 2.11***)। इस प्रकार, इन 15 उप-शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

➢ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 229.01 करोड़[8] का अभ्यर्पण किया गया जिससे इन निधियों को किसी अन्य योजनाओं पर व्यय करने के लिए सरकार के पास कोई अवसर ही नहीं रहा।

➢ बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय

बिहार बजट संहिता (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 138 के अनुसार, आधिक्य व्यय से दृढ़तापूर्वक बचा जाना चाहिए।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि मुख्य शीर्ष 2401, 2402, 2415 एवं 3451 (***परिशिष्ट 2.12***) के अन्तर्गत 31 उप-शीर्षों (अनुदान संख्या-1 के कुल 124 में से) में ₹ 5.47 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जो व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को इंगित करता है।

➢ व्यय का वेग

कुल व्यय ₹ 454.48 करोड़ में से ₹ 244.68 करोड़ (53.84 *प्रतिशत*) का व्यय मार्च 2013 में हुआ। 60 उप-शीर्षों (कुल 124 में से) में 60 *प्रतिशत* से अधिक व्यय मार्च 2013 में हुआ। वर्ष के अंतिम माह में विशाल व्यय बजट संहिता के नियम 113 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

---

[8] राज्य योजना ₹ 95.20 करोड़, राज्य गैर योजना ₹ 16.89 करोड़ एवं केन्द्र अंश ₹ 116.92 करोड़

➢ निधि का अनियमित आहरण

जि.कृ.का. राँची के अभिलेखों से यह अवलोकन किया गया कि शीर्ष 2401-00-796-49 (ग्रामीण बीज योजना) के अंतर्गत जि.कृ.का. को ₹ 15.15 लाख उपलब्ध कराया गया। यह राशि बीज प्रसाधन संयंत्र के क्रय हेतु 31 मार्च 2013 को आहरित किया गया एवं इसे जि.कृ.का. के चालू खाते में रख लिया गया। जुलाई 2013 तक बीज प्रसाधन भवन, जिसमें मशीन अधिष्ठापित किया जाना था, का निर्माण नहीं किया गया था। बिना नितांत आवश्यकता के निधि का आहरण, जो इसे व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया, राज्य के वित्तीय नियमों के विरुद्ध था। जुलाई 2013 में इंगित करने पर जि.कृ.का, राँची ने कहा (जुलाई 2013) कि उक्त राशि कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

➢ विस्तृत आकस्मिक विपत्र (वि.आ.वि.) का अप्रस्तुतीकरण

हमलोगों ने अवलोकन किया कि 34 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 60 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 34.08 करोड़ की राशि आहरित की गई जिसके विरुद्ध ₹ 6.11 करोड़ (18 *प्रतिशत*) का डी.सी. विपत्र जमा किया गया जिससे ₹ 27.97 करोड़ (82 *प्रतिशत*) की राशि का 57 ए.सी. विपत्र जून 2013 तक बकाया रहा (***परिशिष्ट 2.13***)।

इस प्रकार की विशाल राशियों के लिए डी. सी. विपत्र समय पर नहीं जमा किया जाना राज्य के नियमों/प्रावधानों के विरुद्ध था। इससे सरकारी धन के दुरूपयोग की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। बकाया ए.सी. विपत्र के कारण, इस वर्ष के लिए विभाग का व्यय इस सीमा से अधिक बताया गया।

2.8 निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9225.13 करोड़ का विशाल बचत था जो अनुचित बजट आकलन को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षो के अन्तर्गत विशाल बचत राज्य के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से जुड़े 15 विभागों में विगत 5 वर्षों से सतत् बचत भी देखी गयी।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधानों से₹ 1263.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित करने की आवश्कता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-12 के दौरान हुए अधिक व्यय को भी नियमित करना शेष था।

वर्ष 2012-13 के दौरान नियंत्रक अधिकारियों ने विभागों के व्यय एवं प्राप्तियों का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं ह.) के बही के साथ नहीं किया।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने बजट संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जो विभाग में बजटीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.9 अनुशंसाएँ

- सरकारी विभागों में विशाल बचत को रोकने के लिये, खासकर जहाँ सतत बचत हुई एवं अनुपूरक अनुदान लेने के लिये, जो अप्रयुक्त रह जाती है, बजटीय नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- चालू वर्ष एवं विगत वर्षों में हुए अधिक व्यय के नियमन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
- नियंत्रक अधिकारी को आय एवं व्यय के आँकड़ों का समाशोधन प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं ह.) के बही के साथ कर लेना चाहिए।
- कृषि एवं गन्ना विकास विभाग को बजट अनुवीक्षण प्रणाली अपनाकर विभाग में बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण करना चाहिए।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्ष्णों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 भुगतित अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

बिहार वित्तीय नियम (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 341 के अनुसार, जब तक सरकार किसी संदर्भ में अन्यथा निर्देशित न करे, अनुदान की स्वीकृति के प्रत्येक आदेश में उद्देश्य जिसके लिए वह दिया गया और अनुदान से जुड़े सभी शर्तों, यदि कोई हो, का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। नियमावली के नियम 342 के नीचे टिप्पणी 2 के अनुसार यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिये गये हो, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरांत उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2012 तक भुगतित कुल ₹ 4640.48 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 4299 उ.प्र.प. 30 जून 2013 तक अप्राप्त थे जैसा **तालिका 3.1** में दिखाया गया है। इन उ.प्र.प. का एक बड़ा भाग चार विभागों यथा शहरी विकास विभाग (कुल ₹ 1070.10 करोड़ के 2905 उ.प्र.प.), उद्योग विभाग (कुल ₹ 575.68 करोड़ के 82 उ.प्र.प.), मानव संसाधन विकास विभाग (कुल ₹ 252.95 करोड़ के 47 उ.प्र.प.) एवं सहकारिता विभाग (कुल ₹ 157.03 करोड़ के 100 उ.प्र.प.) के नामे था। बकाया उ.प्र.प. का विभागवार विभाजन ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (30.06.2012 को)

वर्ष जिसमें अनुदान वितरित हुए	वर्ष जिसमें उ.प्र.प बकाये थे	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2008-09 तक	2009-10 तक	1342	1061.66
2009-10	2010-11	997	675.48
2010-11	2011-12	1080	1349.00
2011-12	2012-13	880	1554.34
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या		4299	4640.48

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2012-13)

वृहत राशि के उ.प्र.प. की अप्राप्ति, निर्धारित उद्देश्यों हेतु अनुदानों की उपयोगिता ससमय सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुपालन में, विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखापरीक्षा एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.2.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. का डी.पी.सी.अधिनियम) की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 बतलाता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष, जो संस्थाओं/प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ दस लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, की एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को सौंपेगें। अगस्त 2013 तक, सरकार के किसी विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, राज्य के वार्षिक लेखों से एकत्रित सूचना के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा पहचान किये गये 85 निकायों/संस्थानों में से 67 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों में की गई (2011-12 तक 37 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई), जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के अप्रस्तुतीकरण के कारण विधानमंडल/सरकार को उन तरीकों जिनमें उनके द्वारा स्वीकृत/भुगतित अनुदानों का उपयोग किया गया, के बारे आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को विरल बनाता है।

3.2.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे तीन स्वायत्त निकाय[1] है जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं का परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबंद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

8 अप्रैल 2013 को वर्ष 2008-09 के 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) जारी किये गये। विधानमंडल में इसके उपस्थापन को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के लेखाओं का लेखापरीक्षा किया गया एवं सितम्बर 2013 में एस.ए.आर. मसौदा सदस्य सचिव, झालसा को जारी किया गया।

प्राप्त जवाबों (अक्टूबर 2013) के आधार पर एस.ए.आर. मसौदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है (नवम्बर 2013)। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लेखे प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2013)।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) के लेखाओं का लेखापरीक्षा पूरा किया जा चुका है एवं वर्ष 2011-12 तक एस.ए.आर. जारी किया जा चुका है। तथापि, वर्ष 2003-04 से वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के सम्मुख उनके (एस.ए.आर.) उपस्थापन की स्थिति नवम्बर 2013 तक सूचित नहीं की गयी है। वर्ष 2012-13 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम के अनुच्छेद 22 के अनुसार रिम्स का लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा किया जाना है। तदनुसार, रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा का दायित्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सौपा गया जिसे अक्टूबर 2009 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, सक्रिय अनुनय के बावजूद नवम्बर 2013 तक वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को नहीं सौपें गए।

---

[1] (i) झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित, (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) एवं (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड कोषागार संहिता (झ.को.स.) खण्ड-1 एवं खण्ड-2 के नियम 318 एवं प्रपत्र संख्या-38 के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र में यह सत्यापित करना होता है कि उनके द्वारा वर्तमान माह की प्रथम तारीख से पहले आहरित किए गए सभी आकस्मिक अधिशेषों के विस्तृत विपत्रों को नियंत्री अधिकारी के पास प्रतिहस्ताक्षर हेतु एवं वहाँ से आगे महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची को आगे के संचरण हेतु भेजा जा चुका है। 11 नवम्बर 2013 तक ₹ 5243 करोड़ मूल्य के बकाया विस्तृत विपत्रों को छोड़कर वर्ष 2000-13 के दौरान आहरित कुल ₹ 14468 करोड़ के आकस्मिक संक्षिप्त विपत्रों के विरूद्ध कुल ₹ 9225 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त हुए। वर्ष-वार ब्यौरे **तालिका 3.2** में दिये गये है।

तालिका 3.2 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.सी. विपत्रों की सं0	ए.सी.विपत्रों की राशि	सौंपे गए डी.सी.विपत्रों की सं0	डी.सी.विपत्रों की राशि	ए.सी.विपत्र की *प्रतिशतता* में डी.सी. विपत्र	बकाया ए.सी. विपत्रों की सं0	डी.सी. विपत्रों की बकाया राशि
2010-11	52473	11943	29100	7720	65	23373	4223
2011-12	1052	1600	282	1164	73	770	436
2012-13	544	925	104	341	37	440	584
कुल	**54069**	**14468**	**29486**	**9225**	**64**	**24583**	**5243**

तालिका 3.2 में दिये अनुसार, वर्ष 2000-13 के दौरान आहरित कुल ए.सी. विपत्रों के विरूद्ध प्राप्त हुए डी.सी. विपत्रों की राशि 11 नवम्बर 2013 तक 64 *प्रतिशत* थी। प्रमुख गैर-जिम्मेवार विभाग ग्रामीण विकास विभाग (₹ 1237 करोड़), मानव संसाधन विकास विभाग (₹ 534 करोड़), कल्याण विभाग (₹ 760 करोड़) तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 399 करोड़) थे। पिछले वर्ष के 73 *प्रतिशत* की तुलना में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण 2012-13 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा आहरित राशि का केवल 37 *प्रतिशत* था। विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संबंधित वर्ष के दौरान राज्य का व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा प्राप्त अग्रिम की सीमा से अधिक बताया गया।

3.4 दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, इस क्षति के लिए जिम्मेदार दलों द्वारा क्षतिपूर्ति कर लिये जाने की स्थिति में भी, कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारियों, वित्त विभाग

सहित प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए, जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जानी चाहिए।

जून 2013 में लेखापरीक्षा द्वारा इस संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के लिए किए गए अनुरोध के जवाब में, वित्त विभाग ने जुलाई 2013 में सभी विभागों को एक पत्र लिखा, जिसमें सभी डी.डी.ओ. को तत्संबंधी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया। इस संदर्भ में 18 डी.डी.ओ. ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को निरंक (शून्य) रिपोर्ट भेजा एवं एक डी.डी.ओ. (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडु) ने ₹ 21.90 लाख (2008 में हुए ₹ 1.50 लाख एवं 2010 में हुए ₹ 20.40 लाख) के दुर्विनियोग का रिपोर्ट भेजा। ये मामले न्यायालय में लंबित है।

3.5 निधि आहरित कर बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने का निषेध करती है।

(i) यह देखा गया कि मार्च 2013 के अंतिम तीन कार्य दिवस को ₹ 209.23 करोड़ की राशि बिना किसी उप-विपत्र के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों एवं पूर्ण व्हाउचर आकस्मिक विपत्रों के द्वारा आहरित किये गए तथा बैंक खातों में रखे गए। ए.सी.विपत्रों द्वारा हुए इन आहरणों के समायोजन में विस्तृत आकस्मिक विपत्र एवं पूर्ण व्हाउचर आकस्मिक विपत्रों पत्र के समर्थन में उप-विपत्र संबंधित विभागों द्वारा जून 2013 तक महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्राप्त नहीं कराये गये हैं। ग्रामीण विकास (₹ 102.22 करोड़), कृषि (₹ 21.72 करोड़), मानव संसाधन विभाग (₹ 16.03 करोड़), गृह (₹ 8.32 करोड़) एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹ 6.28 करोड़) विभाग प्रमुख गैर-जिम्मेदार विभाग हैं।

(ii) वर्ष 2012-13 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देनों से संबंधित वाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकरण (वी.एल.सी.) के आँकड़ों तथा वित्त लेखे की समीक्षा से पता चला कि राज्य में 95 व्यक्तिगत बही खाता था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पी.एल.खाते के अधीन अंत शेष सतत रूप से बढ़ती जा रही थी, जैसा कि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: व्यक्तिगत बही खाता निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2010-11	1457.58	1940.34	1670.78	1727.14
2011-12	1727.14	2248.95	1782.95	2193.14
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43

अतएव, सरकारी धनराशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल.खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा, बैंक में रखे गए धनराशि के गलत प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता।

3.6 खुफिया सेवा निधि के प्रशासनिक लेखा परीक्षा का बकाया प्रमाणपत्र

बिहार वित्तीय नियमावली, यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत, के अनुलग्नक-'क' के परिशिष्ट-5 में दिए प्रावधानों के अनुसार, खुफिया सेवा व्यय हेतु अधिकृत अधिकारी के लिये सरकार एक नियंत्रक अधिकारी को नामित करेगा जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार किये गये व्यय का प्रशासनिक लेखापरीक्षा करेगा एवं उस वर्ष के अनुवर्ती वर्ष में 31 अगस्त तक एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार को सौंपेगा।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेखों से यह पाया गया कि वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 के दौरान पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक ने खुफिया सेवाओं के अंतर्गत ₹ 21.70 करोड़ खर्च किए, जिसके विरूद्ध वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक के ₹ 6.40 करोड़ के प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय में प्राप्त थे जबकि वर्ष 2005-06 (₹ 8.30 करोड़), वर्ष 2007-08 (₹ 4.50 करोड़), एवं वर्ष 2008-09 (₹ 2.50 करोड़) से संबंधित ₹15.30 करोड़ के प्रमाण-पत्र अक्टूबर 2013 तक बकाये थे। इस संदर्भ में महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के द्वारा सतत पत्राचार किए जाने के बावजूद, संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं प्रदान किए गए। अतएव, ₹ 15.30 करोड़ के व्यय की वैधता नहीं बतायी जा सकी है।

3.7 निष्कर्ष

राज्य संस्थानों/निकायों द्वारा ₹ 4640.48 करोड़ के सहायता अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जो राज्य सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं कार्यदक्षता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने से बाधित किया।

सरकारी विभागों ने अनुदान ग्राही निकायों के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किया। स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के सम्मुख ससमय प्रस्तुत नहीं किये गये।

वर्ष 2000-13 की अवधि के ₹ 5243 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र 11 नवम्बर 2013 तक बकाये थे क्योंकि इनके विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन दिनों में ए.सी. विपत्रों द्वारा आहरित ₹ 209.23 करोड़ की राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए बैंक खाते में रखा गया। मार्च 2013 के अंत में व्यक्तिगत बही खाता में एक विशाल अंतशेष (₹ 2954.43 करोड़) था। चालू वर्ष के लिए विधानमंडल द्वारा पास किये गए बजटीय निधि का अगले वर्ष/वर्षों के व्यय के लिए पी.एल. खाते में हस्तांतरण अनियमित था।

3.8 अनुशंसाएँ

- अनुदानग्राही संस्थाओं को जारी किये गये अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ससमय प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए।
- संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा आहरणों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र राज्य के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- बैंक खातों तथा पी.एल. खातों में निधियों के एकत्रीकरण से बचा जाना चाहिए एवं निधियों का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**

दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

शशी कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 पार्ट- ए

(संदर्भ: कंडिका झारखण्ड की रूप रेखा; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय				
ए.	**सामान्य आँकड़ा**			
क्र.सं.	**विवरण**			**आँकड़ा**
1	क्षेत्रफल			79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार		2.69 करोड़
	(बी)	2010-11		3.30 करोड़
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार (अखिल भारतीय धनत्व=325 व्यक्ति प्रति कि.मी.)		338 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व= 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		414 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का संख्या* (आखिल भारतीय अनुपात 21.92 प्रतिशत)			40.4 प्रतिशत
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80%)		44 प्रतिशत
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय 74.04%)		67.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर**(प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय= 42 प्रति 1000 जीवित जन्म)			41
7	गिनी गुणांक***			
	(ए)	ग्रामीण(अखिल भारत-0.29)		0.24
	(बी)	शहरी (अखिल भारत-0.38)		0.36
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2012-13			₹ 156781 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.सी.ए.जी.आर. (2003-04 से 2012-13)		झारखण्ड	13.95 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.94 प्रतिशत
10	(प्रति व्यक्ति) स.रा.घ.उ.सी.ए.जी.आर. (2003-04 से 2012-13)		झारखण्ड	15.62 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	16.37 प्रतिशत
11	जन संख्या वृद्धि (2003-04 से 2012-13)		झारखण्ड	14.01 प्रतिशत
			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.22 प्रतिशत

ब.	**वित्तीय आँकड़ा**				
क्र.सं.	**विवरण**		**आँकड़ा (प्रतिशत में)**		
	सी.ए.जी.आर.		**2003-04 से 2011-12**		**2003-04 से 2012-13**
			सामान्य श्रेणी राज्य	**झारखण्ड**	**झारखण्ड**
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	17.48	18.83	17.88
2.	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	17.44	16.96	17.10
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	12.64	13.46	13.78
4.	डी.	कुल व्यय का	14.15	17.92	17.69
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	16.83	15.81	17.66
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85	19.01	17.71
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.35	17.85	15.45
8	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	14.18	@	@
9.	आई.	पेंशन का	18.36	19.29	20.19

*सामान्य आँकड़ा का स्रोत: बी.पी.एल.(योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा,61वें दौर)

**शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन जनवरी 2011), वित्तीय आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित है एवं

***गिनी गुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा का अनौपचारिक आकलन, 61वें दौर 2004-05 एम.आर.पी.), गिनी गुणांक जनसंख्या पर आधारित आय के असमानता की माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आंका जाता है, शून्य के नजदीक होने पर असमानता कम तथा एक के नजदीक होने पर असमानता अधिक होगी।

@ वर्ष 2003-04 के लिए वेत्तन एवं भत्ते के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.1 पार्ट-बी
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिक निधि और (3)लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग-2: आकस्मिक निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग-3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियॉ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

पार्ट-सी: वित्त लेखे की अभिन्यास

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियॉ प्राय: वित्तीय सम्पतियॉ होती है जिनका पूँजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियों ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरणी सं.2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियॉ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं.3	यह विवरणी राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियॉ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं.4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं.5	यह प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं.6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं.7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों(खंड एवं उधारकर्त्ता के ग्रुप के अनुसार) जिसे विवरणी 1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियॉ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं.8	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्त्ता संस्थान के ग्रुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं.9	सामविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.12	लघु शीर्षों द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी सं.13	वर्ष2012-13 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.14	वर्ष 2012-13 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाईल को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2013 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.17	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2 पार्ट - ए
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम (***परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी***) एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्यअर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्यराजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चलों का उत्पलावकता को-एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैर्टन आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके। पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रूझान नीचे दर्शाया गया है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृति (स.रा.घ.उ.)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	87794	100621	125824(पी.)	140558(क्यू)	156781(ए)
स.रा.घ.उ. की विकास दर	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5
स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार					

पी-औपबंधिक अनुमान, क्यू-तीव्र अनुमान, ए-अग्रिम अनुमान

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष-ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियॉ-विविध पूँजीगत प्राप्तियॉ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा **घटाव** सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्तियॉ **घटाव** बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज व्यय प्राप्तियॉ

परिशिष्ट 1.2 पार्ट- बी

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,2007 का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व घाटे का क्रमिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधति विषयों पर अधिनियम के संबंध में दूरदर्शिता सुनिश्चित करना है जो एफ.आर.बी.एम. अधिनिमय, 2012 के रूप में संशोधित की गई।

- राजस्व घाटे के लिए लक्ष्य: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के अंत में शून्य
- राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य: स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत 2011-12 से 2014-15

(प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
शेष ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात	28.50	27.8	27.3	26.9
ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	25.00	25.00	25.00	
स.रा.घ.उ.वृद्धि (ते.वि.आ.)	14.14	14.50		
स.रा.घ.उ. वृद्धि (एम.टी.एफ.पी.)	14.00	14.00		
स्वयं के कर- स.रा.घ.उ. अनुपात	5.4	5.4		
गैर ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	2	2		
ब्याज भुगतान	10 वर्षों का बकाया दायित्व			
स.रा.घ.उ. में पूँजीगत परिव्यय की प्रतिशतता	3.15	3.5		

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े

(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 11 एवं 41)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**13213(84)**	**15118(82)**	**18781(88)**	**22420(89)**	**24770(83)**
(i) कर राजस्व	**3753(28)**	**4500(30)**	**5717(30)**	**6954(31)**	**8224(33)**
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री,व्यापार आदि पर कर	2996(80)	3597(80	4473(78	5522(79)	6422(78)
राजस्व उत्पाद	205(6)	323(7)	388(7)	457(7)	578(7)
वाहनों पर कर	202(6)	234(5)	312(6)	392(6)	465(6)
मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क	192(5)	238(5)	328(6)	401(6)	492(6)
भू-राजस्व	53(1)	41(1)	131(2)	53(1)	96(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	54(1)	13	21	41(0)	1(0)
अन्य कर	51(1)	54(2)	64(1)	88(1)	170(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	**1952(15)**	**2254(15)**	**2803(15)**	**3038(14)**	**3536(14)**
(iii)संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	**5392(41)**	**5547(37)**	**6154(33)**	**7170(32)**	**8188(33)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**2116(16)**	**2817(18)**	**4107(22)**	**5258(23)**	**4822(20)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**शून्य**	**शून्य**
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**19**	**22**	**24**	**24**	**43**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**13232**	**15140**	**18805**	**22444**	**24813**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**2437(16)**	**3369(18)**	**2447(12)**	**2671(11)**	**5199(17)**
आंतरिक ऋण(अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	2434	3379	2315	2409	4591
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	229	369
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3	-10	132	33	239
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**15669**	**18509**	**21252**	**25115**	**30012**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**शून्य**	**शून्य**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**8335**	**8242**	**7721**	**10813**	**14495**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**24004**	**26751**	**28973**	**35928**	**44507**
भाग-ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**12877(79)**	**15128(83)**	**17945(86)**	**20992(86)**	**23400(83)**
योजना	3813(30)	3758(25)	6004(33)	7646(36)	7743(33)
गैर योजना	9064(70)	11370(75)	11941(67)	13346(64)	15657(67)
सामान्य सेवाएँ(ब्याज भुगतान सहित)	4924(38)	6605(44)	6991(39)	7846(37)	8696(37)
सामाजिक सेवाएँ	5385(42)	5610(37)	6707(37)	7287(35)	8309(36)
आर्थिक सेवाएँ	2533(20)	2913(19)	4247(24)	5859(28)	6395(27)
सहायता अनुदान एवं अंश दान	35	-	-	-	शून्य

परिशिष्ट 1.3 क्रमशः ...

11. पूँजीगत व्यय	**3051(19)**	**2703(15)**	**2664(13)**	**3159(13)**	**4218(15)**
योजना	3015(99)	2682(99)	2621(98)	3111(98)	4151(98)
गैर योजना	36(1)	21(1)	43(2)	48(2)	67(2)
सामान्य सेवाएँ	176(6)	112(4)	120(4)	156(5)	176(4)
सामाजिक सेवाएँ	1355(44)	825(31)	682(26)	866(27)	1030(25)
आर्थिक सेवाएँ	1520(50)	1766(65)	1862(70)	2137(68)	3012(71)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	**418(3)**	**320(2)**	**308(1)**	**217(1)**	**601(2)**
13. कुल (10+11+12)	**16346**	**18151**	**20917**	**24368**	**28219**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**863**	**1190**	**1299**	**1639**	**2183**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	716(83)	1068(90)	1063(82)	1406(86)	1525(70)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	9(1)	-	-	78(5)	520(24)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	138(16)	123(10)	236(18)	155(9)	138(6)
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	शून्य	शून्य
16. समेकित निधि से कुल संवितरण(13+14+15)	**17209**	**19341**	**22216**	**26007**	**30402**
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	7185	7290	7400	9728	13417
19.राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	**24394**	**26631**	**29616**	**35735**	**43819**
भाग-ग. घाटा					
20.राजस्व घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य(+)(1-10)	(+)336	(-)10	(+)836	(+)1428	(+)1370
21.राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	(-)3114	(-)3011	(-)2112	(-)1924	(-)3406
22.प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य(+)(21-23)	(-)1227	(-)704	(+) 116	(+)343	(-)1015
भाग-घ. अन्य ऑकड़े					
23.ब्याज भुगतान(राजस्व व्यय में सन्निहित)	1887	2307	2228	2267	2391
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2366	2333	3122	4530	1427
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट(दिन)	-	-	-	6	13
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	-	-	6	13
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	0.03	0.32
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	87794	100621	125824	140558	156781
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	24084	27165	28655	30664	34869
29. बकाया प्रतिभूतियॉ(वर्षके अंत में) (ब्याज सहित)	500	500	-	-	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (`एक करोड़ तथा उससे अधिक)	247	262	167	182	189
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	1797	1466	1503	573	1972
भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					

परिशिष्ट 1.3 क्रमश: ...

स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.3	4.5	4.5	4.9	5.2
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ.	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3
केंद्रीय अंतरण/ स.रा.घ.उ.	8.6	8.3	8.2	8.8	8.3
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	18.6	18.0	16.6	17.3	18.0
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	123.7	120.1	111.4	108.7	113.9
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.8	83.3	85.8	86.1	82.9
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	41.7	35.8	35.4	33.5	33.2
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	26.9	27.2	30.6	33.6	35.3
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	18.7	14.9	12.7	13.0	14.9
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.6	14.3	12.2	12.3	14.3
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) /स.रा.घ.उ.	0.4	0.0	0.7	1.0	0.9
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	-3.5	-3.0	-1.7	-1.4	-2.2
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-1.4	-0.7	*	*	-0.6
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-10.8	*	-39.6	-74.2	-40.2
प्राथमिक राजस्व संतुलन/ स.रा.घ.उ.	2.5	2.3	2.4	2.6	2.4
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/ स.रा.घ.उ.	27.4	27.0	22.8	21.8	22.2
राजकोषीय दायित्व/ रा.प्रा.	182.3	179.7	152.6	136.8	140.8
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(-)2018	(+)647	(+)4753	(+)1509	(+)285
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/ कुल ऋण प्राप्ति	5.4	3.1	4.3	3.9	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	0.4	1.17	15.00
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2625	2077	4014	6855	5782
वित्तीय परिसम्पति / दायित्व	84	85	89	95	98

* राज्य में राजस्व आधिक्य होने के कारण प्रासंगिक नहीं है।

@ स.रा.घ.उ. का अंक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

कोष्ठ में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से अनुपात (पूर्णांक) दर्शाता है।

परिशिष्ट 1.4 पार्ट- ए
वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

भाग-क: वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					**संवितरण**				
2011-12			2012-13	2011-12		गैर योजना	योजना	कुल	2012-13
	अनुभाग क: राजस्व								
22419.45	I.राजस्व प्राप्तियाँ		**24769.56**	20991.58	I.राजस्व व्यय	15656.61	7743.26	23399.87	**23399.87**
6953.89	कर राजस्व	8223.67		7845.56	सामान्य सेवाएँ	8474.55	221.94	8696.49	
				7287.03	सामाजिक सेवाएँ	4238.37	4070.22	8308.59	
3038.22	कर भिन्न राजस्व	3535.63		4055.89	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2911.93	1499.35	4411.28	
				825.66	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	550.74	258.00	808.74	
7169.93	संघीय करों में राज्य के हिस्से	8188.05		468.72	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	282.19	359.87	642.06	
				47.66	सूचना एवं प्रसारण	34.39	11.88	46.27	
1550.77	गैर योजना अनुदान	1483.41		623.99	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	95.69	468.19	563.88	
2404.61	राज्य योजना हेतु अनुदान	2393.94		127.44	श्रम एवं श्रम कल्याण	43.44	106.99	150.43	
				1119.63	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	302.54	1365.94	1668.48	
1302.03	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	944.86		18.04	अन्य	17.45	-	17.45	
				5858.99	आर्थिक सेवाएँ	2943.69	3451.10	6394.79	
				980.60	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	381.41	611.03	992.44	
				1688.61	ग्रामीण विकास	691.43	1076.74	1768.17	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				282.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	281.29	0.11	281.40	
				859.83	उर्जा	1102.15	458.05	1560.20	
				211.16	उद्योग एवं खनिज	42.26	177.85	220.11	
				829.98	परिवहन	380.73	345.13	725.86	
					विज्ञान, तकनीकि एवं पर्यावरण				
				1006.73	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	64.42	782.19	846.61	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान				

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए क्रमश: ...

				20991.58	**कुल**	15656.61	7743.26	23399.87	**23399.87**
	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			1427.87	**II.** खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य			1369.79	**1369.69**
22419.45	**कुल**		**24769.56**	**22419.45**	**कुल**				**24769.56**
अनुभाग ख									
-0.41	**III.**आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		**116.85**		**III.**रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV.विविध पूँजीगत **प्राप्तियाँ**			3159.37	**IV.** पूँजीगत परिव्यय	67.38	4151.05	4218.43	**4218.43**
				155.56	सामान्य सेवाएँ	67.38	108.53	175.91	
				866.31	सामाजिक सेवाएँ		1029.78	1029.78	
				75.98	शिक्षा,क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		90.76	90.76	
				163.53	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		146.84	146.84	
				422.61	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास		487.42	487.42	
					सूचना एवं प्रसारण				
				204.20	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		194.39	194.39	
अनुभाग ख अन्य (क्रमश:)									
					सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार		110.37	110.37	
					अन्य				
				2137.49	आर्थिक सेवाएँ		3012.74	3012.74	
				55.28	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप		16.39	16.39	
				849.88	ग्रामीण विकास		886.85	886.85	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				399.31	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		591.08	591.08	
					उर्जा				
					उद्योग एवं खनिज		1.00	1.00	
				799.85	परिवहन		1503.45	1503.45	
				33.18	सामान्य आर्थिक सेवाएँ		13.97	13.97	
				3159.37	**कुल**	67.38	4151.05	4218.43	
23.42	**V** ऋण एवं अग्रिम का वसूली		**43.11**	217.10	**V** ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	57.11	543.70	600.81	**600.81**
	विद्युत परियोजना से			164.95	विद्युत परियोजना को	-	541.70	541.70	

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए क्रमशः ...

21.83	सरकारी सेवकों से	22.07		18.11	सरकारी सेवकों को	18.74	-	18.74	
1.59	अन्य से	21.04		34.04	अन्य को	38.37	2.00	40.37	
1427.87	**VI.** नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		**1369.69**		**VI.** नीचे लाया गया राजस्व घाटा				
2671.23	**VII.** लोक ऋण प्राप्तियाँ		**5199.00**	1639.01	**VII.** लोक ऋण पुर्नभुगतान			2183.06	**2183.06**
	बाह्य ऋण	-	-		बाह्य ऋण				
2409.51	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	4591.56		1406.36	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1524.50	
229.19	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	368.79		77.94	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन			520.04	
	ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-							
32.53	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	238.65		154.71	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुर्नभुगतान			138.52	
	VIII आकस्मिक निधि विनियोग				**VIII** आकस्मिक निधि विनियोग				
	IX आकस्मिक निधि विनियोग				**IX** आकस्मिक निधि विनियोग				
10813.40	**X** लोक लेखा प्राप्ति		**14494.71**	9727.77	**X**लोक लेखा संवितरण			13416.31	**13416.31**
613.38	लघु बचत एवं भविष्य निधि	667.69		543.74	लघु बचत एवं भविष्य निधि			645.53	
138.58	रक्षित निधि	279.80		243.71	रक्षित निधि			403.23	
305.76	उचन्त एवं विविध	199.00		231.63	उचन्त एवं विविध			167.60	
4520.03	प्रेषण	4642.57		4502.89	प्रेषण			4784.27	
5235.65	जमा एवं अग्रिम	8705.65		4205.80	जमा एवं अग्रिम			7415.68	
	अन्तर्रा-ज्यीय समायोजन			75.40	अन्तर्राज्यीय समायोजन			100.00	100.00
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			116.85	**XI** वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			704.75	704.75
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				93.85	रिजर्व बैंक में जमा			-56.50	
				18.59	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			14.68	
					चिन्हित निधि का निवेश				
				4.41	रोकड़ का निवेश			746.57	
37354.96	**कुल**		**45992.92**	**37354.96**	**कुल**				**45992.92**

परिशिष्ट 1.4 पार्ट- बी

31 मार्च 2013 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

31.03.12 को	दायित्व		31.03.13 को
22285.78	**आन्तरिक ऋण**		**25201.59**
8630.39	ब्याज वाले बाजार ऋण	11775.40	
0.17	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.18	
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30	
3513.94	अन्य संस्थाओं से ऋण	3635.54	
151.25	अर्थोपाय अग्रिम	शून्य	
9983.73	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियॉ	9784.16	
शून्य	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	शून्य	
2024.41	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**2124.55**
शून्य	1984-85 के पूर्व के ऋण	शून्य	
8.79	गैर योजना ऋण	6.38	
2015.62	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2118.17	
	केन्द्र योजनागत हेतु ऋण	शून्य	
	केन्द्र प्रायोजित हेतु ऋण	शून्य	
	अन्य अर्थोपाय अग्रिम	शून्य	
शून्य	**अन्तर्राज्यीय समायोजन**	**शून्य**	
150.00	**आकस्मिक निधि**		**150.00**
1527.70	**लघु बचत भविष्य निधि**		**1549.86**
4382.78	**जमा**		**5673.32**
443.10	**रक्षित निधि**		**319.67**
	अंतरण शेष	शून्य	
78.47	**उचंत एवं विविध शेष**		109.87
30892.24	**कुल**		**35128.85**
	सम्पति		
21530.92	**अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**25749.35**
101.86	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	107.11	
21429.06	अन्य पूँजीगत परिव्यय	25642.24	
75.40	**अन्तर्राज्यीय समायोजन**		**100.00**
7190.15	**ऋण एवं अग्रिम**		**7747.85**
6583.51	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	7125.21	
612.17	अन्य विकास ऋण	631.50	
-5.53	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-8.86	
12.14	**अग्रिम**		**12.72**
शून्य	**उचंत एवं विविध शेष**	**शून्य**	
116.85	**नगद**		**704.75**
-	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	शून्य	

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-बी क्रमश: ...

93.85	रिजर्व बैंक में जमा	-56.50	
	जमा निधि का निवेश	शून्य	
18.59	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	14.68	
4.41	नगद शेष निवेश	746.57	
270.17	**प्रेषण शेष**		**411.86**
1696.61	**सरकारी लेखे में घाटा**		**402.32**
1427.87	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा	1369.69	
	(ii) विविध घाटा		
3124.48	वर्ष के शुरूआत में संचय घाटा/आधिक्य	1772.01	
30892.24	**कुल**		**35128.85**

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्त्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणयिों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यत: रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि ***परिशिष्ट 1.4*** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरित रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतेय या प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार आँकड़ों में विचलन या ह्रास वाली मदें इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। लेखे में प्रतिविम्बित आँकड़ों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत सूचित आँकड़े जो 31 मार्च 2013 को समाशोधन की प्रक्रिया में था, के बीच ₹ 56.13 लाख (निवल क्रेडिट) का अंतर था। अंतर अभी भी समाशोधन के अंतर्गत है।

परिशिष्ट 1.5

13वें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे

(संदर्भ: कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 17)

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
22 गृह विभाग	2055-00-796-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	11.00	11.00	शून्य
	2055-00-800-69	13वें वित्त आयोग की सिफारिश	63.50	63.50	शून्य
	उप योग		74.50	74.50	शून्य
25 संस्थानिक वित्त एवं योजना कार्यान्वयन विभाग	2203-00-001-61	विशिष्ट पहचान योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नियोजन सुविधा	11.64	शून्य	(-)11.64
	2203-00-796-61	विशिष्ट पहचान योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नियोजन सुविधा	11.64	शून्य	(-)11.64
	उप योग		23.28	शून्य	(-)23.28
26 श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-003-43	20 आई.आई.टी. का निर्माण	30.00	30.00	शून्य
	2230-03-796-43	20 आई.आई.टी. का निर्माण	20.00	17.25	(-) 2.75
	उप योग		50.00	47.25	(-) 2.75
27 विधि विभाग	2014-00-105-04	जिला न्यायधीश की सहायता हेतु न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति	4.39	0.78	(-) 03.61
	2014-00-105-05	प्रात:/सायं न्यायालय का गठन	16.52	शून्य	(-) 16.52
	2014-00-105-06	न्यायालय भवन स्मारक	2.98	शून्य	(-) 2.98
	2014-00-114-08	आरबिट्रेटर का प्रशिक्षण	5.98	0.13	(-)5.85
	2014-00-114-09	न्यायिक अकादमी को आधारभूत संरचना	5.97	2.97	(-)3.00
	2014-00-114-10	न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण	2.64	1.08	(-)1.56
	2014-00-114-11	वृहत लोक अदालत एवं विधि सहायता	1.99	शून्य	(-) 1.99
	उप योग		40.47	4.96	(-)35.51
28 झारखण्ड उच्च न्यायालय	2014-00-102-02	माननीय उच्च न्यायालय के सहायतार्थ नियुक्त न्यायालय प्रबंधक	0.40	0.09	(-) 0.31
35 योजना एवं विकास विभाग	2053-00-094-02	जिला नवीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान	2.00	शून्य	(-)2.00
	2053-00-796-19	जिला नवीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान	2.80	शून्य	(-)2.80
	3454-02-205-02	राज्य सांख्यिकीय तंत्र के लिए अनुदान	4.80	शून्य	(-)4.80
	उप योग		9.60	शून्य	(-)9.60

परिशिष्ट 1.5 क्रमश: ...

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-05-101-05	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को केन्द्रीय सहायता	214.53	209.43	(-)5.10
	2245-05-101-06	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को राज्य द्वारा सहायता	71.51	69.81	(-)1.70
	2245-80-101-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	2.00	शून्य	(-)2.00
	2245-80-789-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	0.50	शून्य	(-)0.50
	2245-80-796-02	आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का विकास	2.50	शून्य	(-)2.50
		उप योग	291.04	279.24	(-)11.80
42ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-796-21	ब्लाक स्तर पर भवन निर्माण	37.13	37.13	शून्य
48 शहरी विकास विभाग	2217-80-191-29	नगर निगम को अनुदान	12.00	7.02	(-)9.98
	2217-80-191-30	नगर निगम को अनुदान	10.00	शून्य	(-)10.00
	2217-80-192-08	नगर निकाय को अनुदान	22.74	15.08	(-)7.66
	2217-80-192-09	नगर निकाय को अनुदान	14.86	3.05	(-)11.81
	2217-80-193-08	नगर पंचायत को अनुदान	19.00	8.33	(-)10.67
	2217-80-193-09	नगर पंचायत को अनुदान	12.00	शून्य	(-)12.00
		उप योग	90.60	33.48	(-)57.12
49 जल संसाधन विभाग	2701-03-001-08	वृहत् सिंचाई योजना को मदद	24.67	शून्य	(-)24.67
50 लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-05	लघु सिंचाई योजना को मदद	2.33	शून्य	(-)2.33
52 कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	2205-00-106-01	13वें वित्त आयोग (पुरातत्व सर्वेक्षण)	9.00	9.00	शून्य
55 ग्रामीण कार्य विभाग	3054-04-105-01	ग्रामीण सड़कों एवं भवनों का जीर्णोद्वार एवं रखरखाव	27.00	20.08	(-)6.92
	3054-04-105-02	ग्रामीण सड़कों एवं भवनों का जीर्णोद्वार एवं रखरखाव	52.00	52.00	शून्य
		उप योग	79.00	72.08	(-)6.92
56 पंचायती राज	2515-00-196-01	जिला परिषद् को आधारभूत अनुदान	38.28	38.55	(+)0.27
	2515-00-196-02	जिलापरिषद को विशेष क्षेत्र अनुदान	7.00	7.12	(+)0.12
	2515-00-196-03	जिला परिषद को निष्पादन अनुदान	26.26	25.29	(-)0.97
	2515-00-197-01	प्रखंड पंचायत को आधारभूत अनुदान	38.28	40.41	(+)2.13

परिशिष्ट 1.5 क्रमश: ...

अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
56 पंचायती राज	2515-00-197-02	प्रखंड पंचायत को विशेष क्षेत्र अनुदान	7.00	6.84	(-)0.16
	2515-00-197-03	प्रखंड पंचायत को निष्पादन अनुदान	26.26	26.54	(+)0.28
	2515-00-198-01	ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	114.84	118.85	(+)4.01
	2515-00-198-02	ग्राम पंचायत को विशेष क्षेत्र के लिए आधारभूत अनुदान	21.00	20.52	(-)0.48
	2515-00-198-03	ग्राम पंचायत को सामान्य क्षेत्र के लिए निष्पादन अनुदान	78.78	77.84	(-)0.94
		उप योग	357.70	361.96	(+)4.26
59 प्राथमिक व लोक शिक्षा	2202-01-111-33	सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	136.84	136.84	शून्य
	2202-01-789-33	सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	46.76	46.76	शून्य
	2202-01-796-33	सर्व शिक्षा अभियान को राज्य द्वारा विशेष अंशदान	124.40	124.40	शून्य
		उप योग	308.00	308.00	शून्य
60 सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	4235-02-103-59	13वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	54.00	54.12	(+) 0.12
	4235-02-796-59	13वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	54.00	53.89	(-)0.11
		उप योग	108.00	108.01	(+)0.01
		कुल	**1505.72**	**1335.70**	**(-)170.02**

परिशिष्ट 1.6

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 1.6.6; पृष्ठ 29)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औधोगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी. वातावरण का संरक्षण और परिस्थितीकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षाणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.7

बाजार ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज उत्तरदायित्व

(संदर्भ: कंडिका 1.12.6; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण का विवरण-झारखण्ड सरकार स्टॉक	कब उगाही किया गया	राशि	अवधि जब ब्याज देय है	उपार्जित ब्याज	रोकड़ शेष निवेश लेखे से प्राप्त ब्याज@ 5%	अन्तर
1.	7.54% 2019	17.04.2009	517.45	17.04.09 से 31.03.10	37.26	24.71	12.55
2.	8.01% 2019	05.08.2009	474.40	05.08.09 से 31.03.10	24.98	15.59	9.39
3.	8.37% 2019	09.09.2009	599.80	09.09.09 से 31.03.10	28.13	16.81	11.32
4.	8.19% 2019	30.10.2009	252.24	30.10.09 से 31.03.10	8.72	5.32	3.40
5.	8.28% 2020	12.05.2010	500.00	12.05.10 से 31.03.11	36.75	22.19	14.56
		कुल	**2343.89**		**135.84**	**84.62**	**51.22**

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दैनिक रोकड़ शेष

परिशिष्ट 1.8

अग्रिम सांकेतिक कैलेन्डर के अनुसार सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण

(संदर्भ: कंडिका 1.12.7; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बाजार उधार	पहली तिमाही		दूसरी तिमाही		तीसरी तिमाही		चौथी तिमाही	
		सांकेतिक कैलेन्डर के अनुसार	वास्तविक	सांकेतिक कैलेन्डर के अनुसार	वास्तविक	सांकेतिक कैलेन्डर के अनुसार	वास्तविक	सांकेतिक कैलेन्डर के अनुसार	वास्तविक
2008-09	1486.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	195.45	शून्य	1290.55
2009-10	1843.98	शून्य	517.45	शून्य	1074.29	शून्य	252.24	शून्य	शून्य
2010-11	500.00	शून्य	500.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2011-12	1254.05	शून्य	शून्य	शून्य	500.00	शून्य	500.00	शून्य	254.05
2012-13	3600.00	200.00	200.00	1000.00	300.00	1000.00	500.00	1165.47	2600.00
कुल	**8684.03**								

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट 2.1

₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
		राजस्व			
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	710.74	264.25	37
2	2	पशुपालन विभाग	160.71	35.50	22
3	8	नागर विमानन विभाग	100.58	60.12	60
4	9	सहकारिता विभाग	77.65	21.73	28
5	17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	71.02	27.17	38
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1101.10	307.90	28
7	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1125.53	326.13	29
8	23	उद्योग विभाग	287.73	82.94	29
9	24	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	58.40	12.89	22
10	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	913.15	232.43	25
11	27	विधि विभाग	222.12	52.33	24
12	35	योजना एवं विकास विभाग	679.24	594.38	88
13	39	आपदा प्रबंधन विभाग	444.36	159.06	36
14	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	338.47	77.18	23
15	42	ग्रामीण विकास विभाग	832.84	317.32	38
16	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	92.08	37.03	40
17	45	सुचना प्रावैधिकी विभाग	62.20	42.16	68
18	47	परिवहन विभाग	449.99	116.55	26
19	48	शहरी विकास विभाग	581.90	177.09	30
20	49	जल संसाधन विभाग	317.55	92.55	29
21	50	लघु सिंचाई विभाग	77.14	16.24	21
22	51	कल्याण विभाग	816.49	250.26	31
23	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग	75.97	27.47	36
24	53	मत्स्य	61.20	18.39	30
25	54	डेयरी	95.42	27.00	28
26	58	माध्यमिक शिक्षा	725.48	238.38	33
27	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	4656.04	1493.28	32
28	60	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	1114.29	302.08	27

परिशिष्ट 2.1 क्रमशः ...

		पूँजीगत			
29	9	सहकारिता विभाग	18.80	16.05	85
30	10	उर्जा विभाग	794.00	252.30	32
31	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	407.35	260.52	64
32	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	122.49	30.95	25
33	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	65.73	30.49	46
34	47	परिवहन विभाग	54.05	49.51	92
35	48	नगर विकास विभाग	689.91	490.99	71
36	49	जल संसाधन विभाग	1655.71	1232.85	74
37	50	लघु सिंचाई विभाग	362.19	167.28	46
38	51	कल्याण विभाग	132.01	29.17	22
		कुल	**20551.63**	**7969.92**	**39**

परिशिष्ट 2.2

वर्ष 2012-13 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 62)

(₹ **करोड़ में**)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1	1.कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-796-56	119.00	28.16	कारण नहीं बताये गये हैं ।
2	3. भवन निर्माण विभाग	4059-00-796-53	56.70	50.08	32 लाख का कारण तकनिकी मंजूरी एवं योजना के मंजूरी में प्रक्रियात्मक विलम्ब को बताया गया।
3	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-13	235.83	84.47	केन्द्र सरकार से आवंटन अप्राप्त।
4		3456-00-796-13	335.36	88.51	केन्द्र सरकार से अनाजों के लिए आबंटन अप्राप्त।
5	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परविार कल्याण विभाग	2211-00-001-03	79.51	69.29	केन्द्र सरकार से निधि की कम मंजूरी ।
6		2211-00-101-01	193.64	141.55	निधि की मंजूरी ।
7		4210-02-796-48	60.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
8	22-गृह विभाग	2055-00-104-04	103.66	29.43	पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण ।
9		2055-00-110-01	173.70	46.53	कारण नहीं बताये गये हैं ।
10	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-789-03	80.63	27.49	कारण नहीं बताये गये हैं ।
11		2235-03-796-03	212.19	41.87	कारण नहीं बताये गये हैं ।
12	35- योजना एवं विकास विभाग	2235-02-102-01	143.87	118.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
13		2235-02-796-01	144.00	118.35	कारण नहीं बताये गये हैं ।
14		2053-00-796-11	35.00	35.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
15		2053-00-796-24	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
16		2053-00-796-25	100.00	100.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
17		2053-00-800-11	45.95	45.95	कारण नहीं बताये गये हैं ।
18		3454-02-204-14	21.56	21.56	कारण नहीं बताये गये हैं ।
19	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-796-02	48.05	20.99	कारण नहीं बताये गये हैं ।
20	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-01	162.95	24.60	कारण नहीं बताये गये हैं ।
21	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-01	452.14	61.06	कारण नहीं बताये गये हैं ।
22		5054-03-796-01	700.00	84.82	कारण नहीं बताये गये हैं ।
23		5054-03-796-08	220.00	68.06	कारण नहीं बताये गये हैं ।
24		5054-03-796-03	105.00	74.34	कारण नहीं बताये गये हैं ।
25	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-800-01	35.78	28.26	कारण नहीं बताये गये हैं ।
26		2501-06-800-05	36.26	36.26	कारण नहीं बताये गये हैं ।
27		2505-01-702-02	73.50	35.02	कारण नहीं बताये गये हैं ।

परिशिष्ट 2.2 क्रमशः ...

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
28	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-03	40.00	40.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
29		3075-60-796-03	60.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
30	48- नगर विकास विभाग	2215-02-191-11	25.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
31		2215-02-796-09	35.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं ।
32		4217-60-191-28	178.00	115.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
33		4217-60-191-29	40.00	34.49	कारण नहीं बताये गये हैं ।
34		4217-60-191-30	103.00	99.91	कारण नहीं बताये गये हैं ।
35		4217-60-796-42	40.00	36.78	कारण नहीं बताये गये हैं ।
36		4217-60-796-43	40.00	28.40	कारण नहीं बताये गये हैं ।
37	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	125.85	22.23	कारण नहीं बताये गये हैं ।
38		2701-03-001-08	24.67	24.67	कारण नहीं बताये गये हैं ।
39		4700-80-789-09	48.78	26.07	कारण नहीं बताये गये हैं ।
40		4700-80-796-10	600.00	424.95	कारण नहीं बताये गये हैं ।
41		4701-80-796-73	100.16	97.58	कारण नहीं बताये गये हैं ।
42		4700-80-789-10	467.12	467.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
43		4700-80-796-11	168.00	107.77	कारण नहीं बताये गये हैं ।
44	50- लघु सिचाई विभाग	4702-00-101-33	100.29	57.94	कारण नहीं बताये गये हैं ।
45		4702-00-796-30	160.00	49.23	कारण नहीं बताये गये हैं ।
46	51-कल्याण विभाग	2225-02-796-73	31.25	31.25	केन्द्र सरकार से आबंटन की अप्राप्ति ।
47		2225-02-796-04	71.32	64.41	केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का अविमोचन ।
48	55-ग्रामीण कार्य विभाग	4515-00-796-04	209.42	28.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
49		4515-00-103-04	183.25	44.02	कारण नहीं बताये गये हैं ।
50	56-पंचायती राज एवं एन.	2515-00-001-03	107.81	28.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
51	आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-15	150.00	64.19	कुल जिलों को निधियों की पहली खेप/किस्त की एवं सभी जिलों को दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
52		2515-00-789-15	60.31	37.57	कुल जिलों को निधियों की पहली खेप/किस्त की एवं सभी जिलों को दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
53		2517-00-796-15	156.00	119.35	कुल जिलों को निधियों की पहली खेप/किस्त की एवं सभी जिलों को दूसरे किस्त की अप्राप्ति।
54	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	399.31	124.98	कारण नहीं बताये गये हैं।
55		2202-02-109-35	28.05	28.05	केन्द्र सरकार का केन्द्रांश अप्राप्त ।
56	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2554.29	886.58	निधियों के अधिक प्रावधान एवं शेष सूचित नहीं की गई।
57		2202-01-101-03	183.80	127.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
58		2202-01-101-05	48.00	21.73	केन्द्रीय अंशदान की कम प्राप्ति एवं अंतिम बचत सूचित नहीं की गयी ।

परिशिष्ट 2.2 क्रमशः ...

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
59	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-104-01	56.36	21.93	निधियों के अधिक प्रावधान एवं अंतिम बचत नहीं की गयी।
60		2202-01-111-02	202.85	70.86	केन्द्रांश अप्राप्त ।
61		2202-01-789-25	73.80	25.78	केन्द्रांश अप्राप्त ।
62		2202-01-796-04	172.90	117.07	कारण नही बताये गये हैं ।
63		2202-01-796-25	184.40	64.41	केन्द्रांश अप्राप्त ।
64	60- समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-102-51	159.48	36.69	कारण नही बताये गये हैं।
65		2235-02-796-51	172.76	30.17	कोषागार से निधि का अनाहरण एवं अंतिम बचत सूचित नहीं की गयी है।
66		2235-02-796-71	30.87	30.80	कोषागार से निधि का अनाहरण एवं निधि का अधिक प्रावधान ।
67		2236-02-101-02	80.64	23.49	कोषागार से निधि का अनाहरण एवं अंतिम बचत सूचित नहीं की गयी है।
68		2235-02-103-70	26.37	26.37	कोषागार से निधि का अनाहरण ।
कुल			**11723.39**	**5386.36**	

परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ: कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 67)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	10	उर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	10	उर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	आपदा प्रबंधन विभाग	61.33
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उधोग विभाग	7.49
2004-05	39	आपदा प्रबंधन विभाग	69.34
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2005-06	10	उर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2006-07	38	निबंधन विभाग	$
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	^
कुल			**8540.79**

स्रोत:विनियोग लेखे संगत वर्षों के :

* **अतिरिक्त राशि केवल** ₹ 8,807 **थी।**

@ **अतिरिक्त राशि केवल** ₹ 1,072 **थी।**

\# **अतिरिक्त राशि केवल** ₹ 49,670 **थी।**

$ **अतिरिक्त राशि केवल** ₹ 81,665 **थी।**

^ **अतिरिक्त राशि केवल** ₹ 11,160 **थी।**

परिशिष्ट 2.4

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 68)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (भारित)				
1	13-ब्याज संदाय	243458.02	239124.92	4333.10	1400.00
2	34-झारखण्ड लोक सेवा आयोग	665.63	462.28	203.35	35.00
	कुल राजस्व भारित	**244123.65**	**239587.20**	**4536.45**	**1435.00**
	राजस्व (दत्तमत)				
3	1.कृषि गन्ना विकास विभाग	60429.17	44648.20	15780.97	10644.34
4	2-पशुपालन विभाग	14648.77	12521.42	2127.35	1422.21
5	3-भवन निर्माण विभाग	8619.98	8195.11	424.87	137.63
6	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2616.98	2363.27	253.71	654.63
7	6-निर्वाचन	2890.33	2794.41	95.92	100.98
8	9-सहकारिता विभाग	7735.76	5592.19	2143.57	29.37
9	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	6974.49	4385.49	2589.00	128.00
10	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	89064.69	79320.57	9744.12	21045.44
11	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	29131.34	26828.21	2303.13	2514.16
12	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	110586.97	79939.73	30647.24	1965.62
13	22-गृह विभाग	248723.87	237490.11	11233.76	1982.18
14	23- उद्योग विभाग	24413.03	20479.34	3933.69	4360.14
15	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	4939.75	4550.71	389.04	900.00
16	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	86052.85	68071.56	17981.29	5262.17
17	27- विधि विभाग	21209.86	16978.40	4231.46	1001.64
18	28- झारखण्ड का उच्च न्यायालय	4206.54	3618.36	588.18	235.30
19	32- विधान मंडल	4892.47	4292.10	600.37	54.23
20	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1513.13	1318.69	194.44	187.10
21	35-योजना एवं विकास विभाग	67905.25	8486.25	59419.00	18.80
22	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	20230.69	19966.01	264.68	248.20
23	37-राजभाषा विभाग	1453.31	1417.29	36.02	21.96
24	38-निबंधन विभाग	1757.46	1132.29	625.17	172.75
25	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	33708.26	26129.34	7578.92	138.63
26	41-पथ निर्माण विभाग	30426.80	28734.23	1692.57	1693.49
27	42-ग्रामीण विकास विभाग	77095.49	51551.49	25544.00	6188.32
28	43-विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग	8418.99	5505.30	2913.69	789.46

परिशिष्ट 2.4 क्रमशः ...

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
29	44-मानव संसाधन विकास विभाग	3228.06	3172.94	55.12	16.00
30	48-नगर विकास विभाग	57514.88	40480.58	17034.30	675.07
31	49- जल संसाधन विभाग	31639.96	22500.14	9139.82	115.43
32	50- लघु सिचाई विभाग	7693.88	6089.76	1604.12	20.23
33	51- कल्याण विभाग	76594.08	56623.03	19971.05	5054.69
34	52- कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	7354.86	4849.99	2504.87	242.37
35	54- डेयरी	8387.15	6842.81	1544.34	1155.31
36	56- पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष प्रमंडल)	150589.24	124804.70	25784.54	420.86
37	58-माध्यमिक शिक्षा	70293.68	48710.42	21583.26	2254.75
38	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	459264.54	316276.07	142988.47	6339.70
39	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	111228.52	81221.68	30006.84	200.91
कुल राजस्व (दत्तमत)		**1953435.08**	**1477882.19**	**475552.89**	**78392.07**
कुल राजस्व		**2197558.73**	**1717469.39**	**480089.34**	**79827.07**
पूँजीगत (दत्तमत)					
1	10-उर्जा विभाग	65300.00	54169.82	11130.18	14100.00
2	20- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	35255.58	14683.63	20571.95	5479.70
3	22-गृह विभाग	13945.00	11402.46	2542.54	24.00
4	30-अल्पसंख्यक कल्याण	9976.11	9154.44	821.67	2273.15
5	41-पथ निर्माण विभाग	163944.95	149890.38	14054.57	3400.00
6	47-परिवहन विभाग	5208.00	454.23	4753.77	197.00
7	49-जल संसाधन विभाग	163271.00	42286.47	120984.53	2300.00
8	50-लघु सिचाई विभाग	35609.00	19491.35	16117.65	610.00
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		492509.64	301532.78	190976.86	28383.85
सकल योग		**2690068.37**	**2019002.17**	**671066.20**	**108210.92**

परिशिष्ट 2.5

निधि का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(संदर्भ: कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 68)

(₹ *लाख में*)

क्र सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ अधिक्य (+)
1	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-50	650.00	---	(-)1042.57
2		4059-01-796-54	1250.00	---	(-)818.55
3		4216-01-796-10	120.00	---	(-)395.35
4	27-विधि विभाग	2052-00-090-18	5.00	---	(-)4.32
5	32-विधान मंडल	2011-02-103-01	2.05	---	(-)1.27
6	42-ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-102-08	1.30	---	(-)14.51
7		3451-00-090-10	1.00	---	(-)6.01
8	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-001-01	0.70	---	(-)11.23
	कुल		**2030.05**	**---**	**(-)2293.81**
9	2-पशुपालन विभाग	2403-00-001-04	---	17.00	(+)14.65
10	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-01	---	2.00	(+)1.63
11		4059-01-051-52	---	120.00	(+)86.40
12	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-101-02	---	1.00	(+)1.06
13	27-विधि विभाग	2014-00-105-01	---	5.00	(+)105.51
14	23-उद्योग विभाग	2850-80-102-04	---	2.21	(+)19.46
	कुल		---	**147.21**	**(+)228.71**
15	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-05	490.00	---	(+)81.61
16		2235-03-796-05	1100.00	---	(+)34.40
17	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-04	87.00	---	(+)25.44
18	45- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-796-71	15.00	---	(+)8.11
	कुल		**1692.00**	---	**(+)149.56**

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
	राजस्व			
1	1- कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	264.25	249.77	14.48
2	2- पशुपालन विभाग	35.50	34.47	1.03
3	12-वित्त विभाग	10.63	9.53	1.10
4	13-ब्याज संदाय	57.33	30.65	26.68
5	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	27.17	25.68	1.49
6	18- खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	307.90	267.18	40.72
7	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	48.17	45.53	2.64
8	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	326.13	304.01	22.12
9	23-उद्योग विभाग	82.94	81.39	1.55
10	35-योजना एवं विकास विभाग	594.38	593.05	1.33
11	38-निबंधन विभाग	7.98	5.26	2.72
12	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	77.18	72.88	4.30
13	41-पथ निर्माण विभाग	33.86	16.63	17.23
14	42-ग्रामीण विकास विभाग	317.32	266.65	50.67
15	47-परिवहन विभाग	116.55	110.05	6.5
16	48-नगर विकास विभाग	177.09	165.11	11.98
17	49-जल संसाधन विभाग	92.55	75.40	17.15
18	50-लघु सिचाई विभाग	16.24	10.16	6.08
19	51-कल्याण विभाग	250.26	177.10	73.16
20	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	27.47	19.51	7.96
21	55- ग्रामीण कार्य विभाग	32.93	31.29	1.64
22	56- पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी . (विशेष प्रमंडल) विभाग	262.05	255.30	6.75
23	58-माध्यमिक शिक्षा	238.38	102.32	136.06
24	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	1493.28	772.67	720.61
25	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	302.08	237.28	64.80

परिशिष्ट 2.6 क्रमश: ...

	पूँजीगत			
1	3-भवन निर्माण विभाग	114.97	84.03	30.94
2	30-अल्पसंख्यक कल्याण	30.95	26.65	4.30
3	41-पथ निर्माण विभाग	174.55	157.42	17.13
4	47-परिवहन विभाग	49.51	47.78	1.73
5	48-नगर विकास विभाग	490.99	374.04	116.95
6	49-जल संसाधन विभाग	1232.85	1189.15	43.70
7	50-लघु सिचाई विभाग	167.28	155.81	11.47
8	51-कल्याण विभाग	29.17	25.00	4.17
9	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	2.39	1.02	1.37
10	55-ग्रामीण कार्य विभाग	79.23	57.43	21.80
11	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	9.96	7.50	2.46
	कुल	**7581.47**	**6084.70**	**1496.77**

परिशिष्ट 2.7

30 और 31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि

(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1	1- कृषि एवं गन्ना विभाग	2401-00-109-28	20.63
2		2401-00-796-28	27.54
3		2401-00-796-19	22.50
4		2401-00-800-53	12.67
5		2401-00-796-56	15.68
6		2401-80-796-15	10.46
7	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-51	19.36
8		4059-01-796-53	34.10
9	8- नागर विमानन विभाग	3053-80-003-02	10.00
10		3053-80-003-02	50.00
11	10- उर्जा विभाग	2801-01-800-02	16.40
12		2801-80-800-09	11.00
13		6801-00-800-05	108.00
14	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-11	12.93
15	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-105-01	31.45
16		6003-00-109-01	38.51
17	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-001-05	18.54
18	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता	3456-00-102-13	33.63
19	मामले विभाग	3456-00-789-13	15.32
20		3456-00-796-02	10.75
21		3456-00-796-13	43.22
22	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार	2211-00-001-03	69.37
23	कल्याण विभाग	4210-02-103-08	15.89
24		4210-02-103-09	12.68
25		4210-02-103-10	11.48
26		4210-02-796-29	16.13
27		4210-02-796-38	10.77
28		4210-02-796-39	10.90
29		4210-02-796-40	16.33
30		4210-02-796-41	22.63
31		4210-02-796-48	60.00

परिशिष्ट 2.7 क्रमश: ...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
32	21-उच्च शिक्षा	2202-03-102-15	13.09
33		2202-03-102-22	10.50
34		2202-03-796-34	10.50
35	22-गृह विभाग	2055-00-104-02	14.25
36		2055-00-109-01	12.90
37		2055-00-110-01	45.39
38		2055-00-115-67	16.11
39		4055-00-207-45	11.98
40	23- उद्योग विभाग	2851-00-103-24	10.00
41	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-003-44	11.55
42		2230-03-101-02	11.13
43	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-796-44	11.55
44		2235-03-101-03	20.07
45		2235-03-789-03	26.31
46		2235-03-796-03	23.97
47	27- विधि विभाग	2014-00-105-01	11.34
48		2014-00-105-05	16.52
49	35- योजना एवं विकास विभाग	2053-00-796-11	35.00
50		2053-00-796-25	100.00
51		2053-00-796-27	48.60
52		2053-00-796-28	10.00
53		2053-00-800-11	45.95
54		2235-02-102-01	118.00
55		2235-02-796-01	117.41
56		3454-02-204-14	21.56
57	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	13.67
58		4215-01-796-02	20.39
59	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-01	16.20
60		2029-00-104-01	22.62
61	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-01	13.22
62		5054-03-796-01	21.69
63		5054-03-796-03	83.26
64	42- ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-05	11.92
65		2501-06-800-01	10.98
66		2505-01-702-02	36.04
67		2505-01-796-02	10.57

परिशिष्ट 2.7 क्रमशः ...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
68	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-004-05	11.10
69		2203-00-800-66	11.10
70		4202-02-105-06	30.35
71	47-परिवहन विभाग	3075-60-101-03	40.00
72		3075-60-796-03	60.00
73	48- नगर विकास विभाग	2215-01-191-01	13.26
74		2215-02-191-11	20.00
75		2215-02-796-09	30.00
76		2217-80-191-30	10.00
77		2217-80-191-39	10.98
78		2217-80-192-09	11.80
79		2217-80-193-08	10.67
80		2217-80-193-09	12.00
81		2217-80-796-23	12.60
82		4217-60-191-26	12.60
83		4217-60-191-28	115.22
84	48- नगर विकास विभाग	4217-60-191-29	31.15
85		4217-60-191-30	99.91
86		4217-60-789-37	13.00
87		4217-60-796-42	36.66
88		4217-60-796-43	28.40
89	49- जल संसाधन विभाग	2701-03-001-06	14.61
90		2701-03-001-07	10.80
91		2701-03-001-08	24.67
92		4700-80-789-09	13.71
93		4700-80-789-10	408.12
94		4700-80-796-09	12.24
95		4700-80-796-10	403-87
96		4700-80-796-11	108.12
97		4701-80-796-73	64.73
98	50- लघु सिचाई विभाग	4702-00-101-07	18.00
99		4702-00-101-33	42.00
100		4702-00-796-30	46.37
101	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2515-00-001-28	14.16
102		4515-00-103-04	46.52

परिशिष्ट 2.7 क्रमश: ...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
103	56-पंचायती राज एवं एन. आर. ई. पी. (विशेष मंडल) विभाग	2515-00-001-03	27.23
104		2515-00-001-15	64.19
105		2515-00-789-15	37.57
106		2515-00-796-15	119.35
107	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-35	16.05
108		2202-02-109-36	11.20
109	59- प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	144.93
110		2202-01-101-05	17.68
111		2202-01-104-01	14.66
112		2202-01-111-02	70.86
113		2202-01-112-04	17.18
114		2202-01-789-25	25.78
115		2202-01-796-04	16.90
116		2202-01-796-25	64.41
117	60- समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-102-51	28.14
118		2235-02-103-70	26.37
119		2235-02-796-51	20.87
120		2235-02-796-71	30.51
121		2236-02-101-02	13.13
122		2236-02-796-05	10.11
123		2236-02-796-05	10.56
कुल अनुदान			**4479.51**

परिशिष्ट 2.8
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2013 के दौरान किया गया खर्च	मार्च 2013 में किया गया खर्च	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी - मार्च 2013	मार्च 2013
1	कल्याण विभाग	4235	110.37	109.19	110.37	100.00	98.93
2	परिवहन विभाग	3075	297.59	297.59	297.59	100.00	100.00
3	उर्जा विभाग	2810	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	नागर विमानन विभाग	3053	40.06	40.01	40.26	99.50	99.37
5	कल्याण विभाग	4225	184.11	106.42	194.39	94.71	54.75
6	मानव संसाधन विभाग	2205	24.46	23.95	26.61	91.92	90.00
7	नगर विकास विभाग	4217	150.87	147.96	182.43	82.70	81.11
8	उद्योग विभाग	2852	87.58	56.44	111.97	78.22	50.41
9	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	109.66	99.62	150.43	72.90	66.22
10	कल्याण विभाग	2225	410.52	286.60	563.88	72.80	50.83
11	नगर विकास विभाग	2217	177.23	132.45	251.63	70.43	52.64
12	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	98.59	82.34	146.84	67.14	56.07
13	मतस्य विभाग	2405	28.66	22.85	42.81	66.95	53.38
14	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2402	31.19	26.99	46.67	66.83	57.83
15		2401	200.54	168.43	306.09	65.52	55.03
16	गृह विभाग	2216	25.78	21.45	41.08	62.76	52.22
17	सूचना प्रावैधिकी विभाग	2203	41.16	34.44	67.85	60.66	50.76
18	उद्योग विभाग	2851	54.18	48.62	90.50	59.87	53.72
19	डेयरी विभाग	2404	40.81	28.96	68.43	59.64	42.32

परिशिष्ट 2.9

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान असंशोधित रह गई (प्रत्येक मामलों मे ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ मे)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग	19.46
2	सचिव, प्रशासनिक, वित्त विभाग	10.38
3	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग भाग-4 ग्रामीण पुलिस	2214.15
4	वित्त आयुक्त	2931.19
5	सचिव, ऊर्जा विभाग	524.43
6	उद्योग निदेशक, खनिज एवं उद्योग विभाग	191.10
7	सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक एवं सुधार बोर्ड	10.71
8	पुलिस महानिरीक्षक (कारागार), गृह विभाग	78.92
9	अवर सचिव, भवन निर्माण एवं भवन लोक निर्माण विभाग	36.75
10	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा उप सचिव, उच्च शिक्षा	4396.02
11	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	22.10
12	सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं कल्याण विभाग	862.99
13	महानिदेशक, सुचना एवं प्रचार विभाग	43.53
14	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	193.72
15	सचिव, कल्याण विभाग	1008.01
16	सचिव, शहरी विकास विभाग	440.19
17	सचिव, कल्याण विभाग सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	755.19
18	श्रम आयुक्त निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	143.78
19	निदेशालय, मिट्टी एवं जल संरक्षण	46.37
20	सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	287.72
21	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	222.75
22	निदेशक, पंचायती राज विभाग	2314.76
23	सचिव, परिवहन एवं नागर उड्डयन-सह-राज्य आयुक्त	297.59
	कुल	**17051.81**

स्रोत: महालेखाकार (ले.एवं ह.)

परिशिष्ट 2.10

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा पूरे आबंटन की बचत

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 71)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना	मूल आबंटन	अनुपूरक आबंटन	बचत	प्रतिशतता
1	2401-00-796-43	मौसम आधारित फसल बीमा पायलट योजना	140.00	0.00	140.00	100.00
2	2401-00-102-43		110.00	0.00	110.00	100.00
3	2401-00-109-28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	2063.00	0.00	2063.00	100.00
4	2401-00-796-28		2754.00	0.00	2754.00	100.00
5	2401-00-109-29	सुक्ष्म सिंचाई योजना	261.00	0.00	261.00	100.00
6	2401-00-796-29		340.00	0.00	340.00	100.00
7	2401-00-789-20	मेक्रो प्रबंधन योजना	0.00	20.00	20.00	100.00
8	2401-00-789-53	झारखण्ड कृषि कार्ड योजना	50.00	0.00	50.00	100.00
9	2401-00-796-19	विस्तार सुधार	2250.00	0.00	2250.00	100.00
10	2401-00-796-60	खाद संग्रहन अनुदान	500.00	0.00	500.00	100.00
11	2401-00-796-67	मिट्टी उद्धार एवं मिट्टी प्रबंध योजना	540.00	0.00	540.00	100.00
12	2401-00-800-68		460.00	0.00	460.00	100.00
13	2401-00-796-68	जमीन अधिग्रहन योजना	20.00	0.00	20.00	100.00
14	2401-00-800-69		15.00	0.00	15.00	100.00
15	2401-00-796-75	राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि विकास	50.00	0.00	50.00	100.00
16	2401-00-800-51		50.00	0.00	50.00	100.00
17	2401-00-796-76	कीटनाशक प्रयोगशाला का स्थापना	75.00	0.00	75.00	100.00
18	2401-00-800-71		75.00	0.00	75.00	100.00
19	2435-01-102-05	कृषि प्रयोगशाला का सशक्तीकरण एवं स्थापना	100.00	0.00	100.00	100.00
20	3475-00-106-03	राजकीय कानूनी सुधार का सशक्तीकरण	0.00	128.00	128.00	100.00
		कुल	**9853.00**	**148.00**	**10001.00**	

परिशिष्ट 2.11

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा निरर्थक अनुपूरक

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ -72)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आबंटन			व्यय	बचत
		मूल आबंटन	अनुपूरक	कुल आबंटन		
1	2401-00-103-01	437.89	0.82	438.71	331.25	107.46
2	2401-00-105-01	114.17	0.64	114.81	63.47	51.34
3	2401-00-107-09	715.21	0.21	715.42	640.74	74.68
4	2401-00-109-01	3024.85	6.60	3031.45	2587.76	443.69
5	2401-00-109-28	364.00	88.00	452.00	323.99	128.01
6	2401-00-119-05	337.93	0.20	338.13	145.77	192.36
7	2401-00-796-28	486.00	115.00	601.00	447.71	153.29
8	2401-00-796-58	100.00	25.00	125.00	4.25	120.75
9	2402-00-001-05	83.16	1.95	85.11	57.05	28.06
10	2402-00-101-01	211.60	3.15	214.75	183.10	31.65
11	2402-00-101-02	73.77	8.44	82.21	63.78	18.43
12	2402-00-102-04	1267.46	14.83	1282.29	1050.05	232.24
13	2415-80-796-04	3000.00	200.00	3200.00	2359.22	840.78
14	2415-80-796-15	2000.00	500.00	2500.00	1453.82	1046.18
15	3451-00-090-07	407.21	5.00	412.21	254.42	157.79
	कुल	**12623.25**	**969.84**	**13593.09**	**9966.38**	**3626.71**

परिशिष्ट 2.12

बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ -72)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	योजना	अंतिम आबंटन	व्यय	आधिक्य	*प्रतिशतता*
1	2401-00-001-01	गैर-योजना	125.22	125.40	0.18	0.14
2	2401-00-102-04	राज्य-योजना	435.55	505.08	69.52	15.96
3	2401-00-107-09	गैर-योजना	639.48	640.74	1.26	0.20
4	2401-00-108-01	गैर-योजना	7.60	7.69	0.09	1.18
5	2401-00-108-02	गैर-योजना	71.63	73.63	2.00	2.79
6	2401-00-109-03	गैर-योजना	6.53	6.56	0.03	0.46
7	2401-00-109-08	गैर-योजना	94.56	95.41	0.85	0.90
8	2401-00-109-19	राज्य-योजना	245.58	256.87	11.29	4.60
9	2401-00-109-20-के.	केन्द्रांश	167.49	180.89	13.40	8.00
10	2401-00-109-29	राज्य-योजना	567.70	571.01	3.31	0.58
11	2401-00-109-46	राज्य-योजना	98.57	106.43	7.86	7.97
12	2401-00-119-01	गैर-योजना	228.45	228.62	0.17	0.07
13	2401-00-119-05	गैर-योजना	145.52	145.77	0.25	0.17
14	2401-00-119-48	राज्य-योजना	60.76	62.92	2.16	3.55
15	2401-00-789-02	राज्य-योजना	186.54	190.55	4.00	2.14
16	2401-00-789-49	राज्य-योजना	197.95	217.47	19.51	9.86
17	2401-00-796-20-के.	केन्द्रांश	36.28	63.54	27.26	75.14
18	2401-00-796-20	राज्य-योजना	4.58	4.64	0.07	1.53
19	2401-00-796-34	राज्य-योजना	39.67	39.97	0.29	0.73
20	2401-00-796-49- के.	केन्द्रांश	116.49	117.59	1.09	0.94
21	2401-00-796-61	राज्य-योजना	65.77	70.58	4.81	7.31
22	2401-00-796-66	राज्य-योजना	47.89	49.80	1.91	3.99
23	2401-00-800-49	केन्द्रांश	25.01	125.38	100.37	401.32
24	2401-00-800-53	राज्य-योजना	6216.42	6454.84	238.41	3.84
25	2401-00-800-66	राज्य-योजना	217.02	223.56	6.54	3.01
26	2402-00-101-02	गैर-योजना	63.72	63.78	0.06	0.09
27	2402-00-102-04	गैर-योजना	1020.89	1050.05	29.16	2.86
28	2415-01-004-02	गैर-योजना	78.13	78.22	0.09	0.12
29	2415-01-277-01	गैर-योजना	8.05	8.08	0.03	0.37
30	2415-01-277-02	गैर-योजना	96.44	96.62	0.18	0.19
31	3451-00-090-07	गैर-योजना	254.42	254.92	0.50	0.20
कुल			**11569.91**	**12116.61**	**546.65**	

परिशिष्ट 2.13

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 73)

(₹ में)

क्र. सं.	डी.डी.ओ. कोड	पदनाम	ए.सी.विपत्र सं.	आहरित राशि	सौंपे गये डी.सी. विपत्र	शेष
1	बीकेआरएसी एच 001	उप प्रमंडल, कृषि पदाधिकारी बेरमो, तेनुघाट	105	1250670	0	1250670
2	बीकेआरएसी एच 002	मिट्टी संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, बोकारो	84/12-13	4500000	0	4500000
			81/12-13	2428143	0	2428143
3	सीटीआरएसीएच 001	जिला उद्यान पदाधिकारी, चतरा	165/12-13	1135300	0	1135300
4	सीटीआरएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, चतरा	238/12-13	280000	0	280000
			237/12-13	129704	0	129704
			245/12-13	4812200	0	4812200
			243/12-13	12000000	0	12000000
			244/12-13	3731000	0	3731000
5	डीजीआरएसीएचई 67	उप कृषि पदाधिकारी, देवघर	160/12-13	1250670	0	1250670
6	डीजीआरएसडब्ल्यू सीई 69	मिट्टी संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, देवघर	158/12-13	387200	0	387200
			133/12-13	70000	0	70000
			152/12-13	7079300	0	7079300
7	डीएचएनएसीएच 001	जिला कृषि पदाधिकरी, धनबाद	162/12-13	1515300	0	1515300
8	डीएचएनएएनएस 001	मिट्टी संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, धनबाद	200/12-13	1249336	0	1249336
9	डीएमकेएसडब्ल्यु सी 002	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, दुमका	178/12-13	2025000	0	2025000
			160/12-13	57000	0	57000
			177/12-13	2900000	0	2900000
10	जीएमएलएसडब्ल्यू सी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, गुमला	127/12-13	10125000	0	10125000
			126/12-13	6000000	0	6000000
11	जीआरडीएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, गिरीडीह	156/2012-13	1939586	0	1939586
12	जीआरएचएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, गढ़वा	100/12-13	1000000	0	1000000
			102/12-13	12000000	0	12000000
13	एचजेडबीएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग	156/2012-13	762500	762500	0
			157/2012-13	322000	322000	0
14	एचजेडबीएसडब्ल्यूसी 002	मिट्टी एवं जल संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग	68/2012-13	18938500	0	18938500
			69/2012-13	546500	0	546500
15	एचजेडबीएसडब्ल्यूसी 003	मिट्टी एवं जल संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग	264/12-13	1800000	0	1800000
			242/12-13	2373500	0	2373500
16	जेएमटीएसीएच 001	उप प्रमंडल, कृषि पदाधिकारी, जामतारा	134/12-13	1135300	0	1135300

परिशिष्ट 2.13 क्रमश: ...

क्र. सं.	डी.डी.ओ. कोड	पदनाम	ए.सी.विपत्र सं.	आहरित राशि	सौंपे गये डी.सी. विपत्र	शेष
17	जेएमटीएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, जामतारा	120/2012-13	78000	0	78000
			117/2012-13	6122000	0	6122000
18	जेएसआरएसडब्ल्यूसी 003	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, जमशेदपुर	117/12-13	4311000	0	4311000
19	जेएसआरएसडब्ल्यूसी 002	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, घाटशिला	55/2012-20	1454000	0	1454000
20	एलडीजीएसीएच 001	जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	151/12-13	1135300	0	1135300
21	एलटीआरएसडब्ल्यूसी 002	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, लातेहार	101/12-13	2025920	0	2025920
			100/12-13	1859355	0	1859355
22	एमएएचएसडब्ल्यूसी 001	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, महेशपुर	212/12-13	6300000	0	6300000
			211/12-13	3050000	0	3050000
			209/12-13	10000000	0	10000000
			210/12-13	3700000	0	3700000
23	आरएनसीएसीएच 017	सहायक बीज जॉच पदाधिकारी, रॉची	90/12-13	500000	0	500000
24	आरएनसीएसीएच 028	उप निदेशक, कृषि (सामान्य), रॉची	237/12-13	2400000	0	2400000
			272/12-13	3475314	0	3475314
25	आरएनसीएसीएच 070	उप निदेशक, उद्यान, रॉची	23/12-13	60000000	60000000	0
			71/12-13	60000000	0	60000000
26	आरएनसीएसीएच O18	जिला कृषि पदाधिकारी, रॉची	178	1515300	0	1515300
27	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 004	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, बुण्डू, रॉची	175	4675000	0	4675000
			176/12-13	3256571	0	3256571
28	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 006	सहायक निदेशक एसयूआर.एस.सी, रॉची	115/2012-13	3850083	0	3850083
29	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 007	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, राँची	148/2012-13	6200000	0	6200000
			144	12954500	0	12954500
30	आरएनसीएसडब्ल्यू सी 010	उप निदेशक, मिट्टी संरक्षण, रॉची	91/12-13	202000	0	202000
31	आरएनसीएसडब्ल्यू सीके 01	मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, खूँटी, बुण्डू	163/12-13	10000000	0	10000000
32	एसबीजेएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, साहेबगंज	62/2012-13	65000	0	65000
			95/12-13	8100000	0	8100000
			94/12-13	8400000	0	8400000
33	एसडीजीएसडब्ल्यूसी 001	जिला मिट्टी संरक्षण पदाधिकारी, सिमडेगा	125/12-13	4145422	0	4145422
			115/12-13	6000000	0	6000000
34	एसजीएचएसीएच 002	उप प्रमण्डलीय कृषि पदाधिकारी, सिंहभूम	164/2012-13	1269600	0	1269600
			कुल	**340788074**	**61084500**	**279703574**

स्रोत: महालेखाकार (ले.एवं हक.),झारखण्ड द्वारा रखे गए वाउचर स्तरीय कंप्युटरीकृत डाटा

परिशिष्ट - 3.1

31 मार्च 2013 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2011-12 तक (2010-11 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2012-13 के दौरान(2011-12 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	80	573.87	2	1.81	82	575.68
मानव संसाधन विकास	36	142.69	11	110.26	47	252.95
सहकारिता	72	124.47	28	32.56	100	157.03
पशुपालन	31	14.47	2	1.85	33	16.32
चिकित्सा	0	0	1	10.00	1	10.00
कल्याण	119	134.00	139	13.74	258	147.74
कृषि	25	55.14	6	78.50	31	133.64
भूमि सुधार	2	0.63	0	0	2	0.63
नगर विकास	2364	670.49	541	399.61	2905	1070.10
अन्य	690	1370.38	150	906.01	840	2276.39
कुल	**3419**	**3086.14**	**880**	**1554.34**	**4299**	**4640.48**

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

नि.म.ले.प. डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 76)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति(एन.जी.ओ.सी.), मोराबादी, राँची	राँची	2008-09
2	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	बोकारो	2011-12
3	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	चाईबासा	2008-09
4	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	चतरा	2011-12
5	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	डालटेनगंज	2010-11
6	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	देवघर	2011-12
7	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	धनबाद	2011-12
8	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	दुमका	2010-11
9	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गढ़वा	2010-11
10	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गोड्डा	2011-12
11	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गुमला	2010-11
12	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	हजारीबाग	2011-12
13	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	जमशेदपुर	2011-12
14	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	जामताड़ा	2011-12
15	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	खूँटी	2011-12
16	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	कोडरमा	2011-12
17	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	लातेहार	2011-12
18	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	लोहरदगा	2010-11
19	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	पाकुड़	2011-12
20	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	रामगढ़	2011-12
21	शिक्षा	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्	राँची	3/2007
22	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	राँची	शून्य
23	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	साहेबगंज	2011-12
24	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	सरायकेला	2011-12
25	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	सिमडेगा	2010-11
26	शिक्षा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एस.एस.ए.	गिरिडीह	2010-11
27	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	बोकारो	अगस्त 2012
28	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	चतरा	शून्य
29	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	देवघर	नवम्बर 2012
30	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	धनबाद	2010-11
31	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	दुमका	फरवरी 2012

परिशिष्ट 3.2 क्रमशः ...

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
32	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पूर्वी सिंहभूम	2011-12
33	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गढ़वा	शून्य
34	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गिरिडीह	दिसम्बर 2012
35	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गोड्डा	2010-11
36	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गुमला	2010-11
37	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	हजारीबाग	शून्य
38	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	जामताड़ा	शून्य
39	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	खूँटी	2011-12
40	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	कोडरमा	शून्य
41	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लातेहार	शून्य
42	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लोहरदगा	जुलाई 2012
43	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पाकुड़	शून्य
44	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पलामू	शून्य
45	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	रामगढ़	2011-12
46	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति) राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, नामकुम के अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ सहित	राँची	2011-12
47	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	नवम्बर 2011
48	स्वास्थ्य	प्राचार्य, रिनपास कांके	राँची	2004-05
49	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सरायकेला खरसावॉ	शून्य
50	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सिमडेगा	शून्य
51	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पश्चिम सिंहभूम	शून्य

परिशिष्ट 3.2 क्रमशः ...

क्रं. सं	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखा परीक्षा की तिथि
52	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, रॉची	राँची	शून्य
53	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य रोग सहायता प्रबंधन सोसाइटी	राँची	शून्य
54	कल्याण	निदेशक, संथाल परगना सेवा दल, देवघर	देवघर	शून्य
55	कल्याण	निदेशक , भारत सेवाश्रम संघ, घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम	2010-11
56	कल्याण	निदेशक , भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी	जमशेदपुर	2006-07
57	कल्याण	निदेशक, आर.के. मिशन टी.बी.सैनिटोरियम, तुपुदाना	राँची	शून्य
58	कल्याण	निदेशक, आर.के. मिशन आश्रम, मोराबादी, रॉची	राँची	2007-08
59	कल्याण	झारखण्ड महिला सामाख्या सोसाइटी (जे.एम.एस.एस.),कडरू, रॉची	राँची	शून्य
60	स्वास्थ्य	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान	राँची	2012-13
61	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
62	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चतरा	2011-12
63	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
64	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2011-12
65	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	दुमका	2004-05
66	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2011-12
67	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11
68	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
69	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12
70	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गुमला	2011-12
71	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2011-12
72	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
73	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2011-12
74	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
75	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पलामू	2009-10
76	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	राँची	2004-05
77	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2004-05
78	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2009-10
79	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
80	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
81	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
82	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
83	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	सितम्बर 2010
84	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
85	उच्च शिक्षा	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2011-12

स्रोत: प्रधान महालेखाकार कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखा परीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	**गणना का आधार एवं व्याख्यान**
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियॉ विविध पूँजीगत प्राप्तियॉ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियॉ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयाविधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अत: चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिरूपनी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रयाप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियॉ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुऐ ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः ...

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियॉ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरूद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणत: पंजीकृत समितियों एवं संविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यो को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखलन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते है।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्त्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ठ कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरनार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियॉ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियॉ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियॉ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर

परिशिष्ट 4.1 क्रमश: ...

	आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्राहित ऋण भी कहा जाता है। यह सामेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तिय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्त्तमान वित्तिय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अप्रयाप्त पाया जाता है या वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियॉ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियॉ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तिय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जॉच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः ...

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी.बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी.बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी. ओ. आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नितिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर. ई.	राजस्व व्यय
आर. आर.	राजस्व प्राप्तियॉ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरियों
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी. ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर